

भारतीय रिज़र्व बैंक
बुलेटिन



अगस्त 2019

खंड 73 अंक 8

संपादन समिति

राजीव रंजन
डी. पी. रथ
सितीकांत पट्टनाईक
जी. पी. सामंता
एस. गंगाधरन
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवडकर

संपादक

शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2019

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
<http://www.bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20

तीसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 1

भाषण

पुस्तक विमोचन पर गवर्नर महोदय की टिप्पणी
शक्तिकांत दास 9

डिजिटल वित्तीय जगत में उपभोक्ता संरक्षण – की गई पहल और उससे आगे
एम के जैन 13

लेख

डिजिटल भुगतान के उत्प्रेरक: अंतर-देशीय अध्ययन 21

भारत में एनईएफटी लेनदेन का नेटवर्क विश्लेषण 35

वर्तमान सांख्यिकी 49

हाल के प्रकाशन 93

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20

तीसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20

तीसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प*

मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि –

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.75 प्रतिशत से 35 आधार अंक कम करके 5.40 प्रतिशत किया जाए।

परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.15 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 5.65 प्रतिशत पर समायोजित हो जाएगी।

- एमपीसी ने मौद्रिक नीति के उदार रुख को बनाए रखने का भी निर्णय लिया है।

ये निर्णय वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +2/-2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य से भी है।

इस निर्णय के समर्थन में प्रमुख विवेचनों को नीचे दिए गए विवरण में वर्णित किया गया है।

आकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. जून 2019 में एमपीसी की बैठक के बाद से वैश्विक आर्थिक गतिविधि, व्यापार तनाव और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण धीमी हो गई है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) के बीच, यूएस में कमजोर कारोबार स्थिर निवेश के कारण जीडीपी वृद्धि 2019 की दूसरी तिमाही में कमजोर हो गई। यूरो क्षेत्र में भी, बाह्य

* 07 अगस्त, 2019 को जारी किया गया।

परिस्थितियों के खराब होने पर जीडीपी वृद्धि दूसरी तिमाही में मध्यम रही। ब्रेकिंग से संबंधित अनिश्चितता और कमजोर औद्योगिक उत्पादन के कारण उपभोक्ता विश्वास में कमी के कारण दूसरी तिमाही में ब्रिटेन की आर्थिक गतिविधि नरम पड़ी। जापान में, औद्योगिक उत्पादन और उपभोक्ता विश्वास पर उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि दूसरी तिमाही में वृद्धि के मंद रहने की संभावना है।

3. प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में आर्थिक गतिविधि कमजोर बनी हुई है, जो मुख्य रूप से बाहरी मांग के धीमी हो जाने के कारण है। दूसरी तिमाही में चीनी अर्थव्यवस्था कई वर्षों के निचले स्तर तक कम हो गई है, जबकि रूस में पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधि कम हो गई है जो निर्यात और खुदरा बिक्री में धीमी गति के कारण दूसरी तिमाही तक जारी रही है। ब्राजील में, अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में कमजोर सेवा क्षेत्र की गतिविधि और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के कारण संकुचन के पश्चात गति हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। दक्षिण अफ्रीका में आर्थिक गतिविधियां दूसरी तिमाही में तेजी से कम होती जा रही हैं क्योंकि जून में विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में लगातार पिछले छः महीने से संकुचन आया है और कारोबार विश्वास भी कमजोर बना रहा है।

4. गैर-ओपेक उत्पादन में वृद्धि से अतिरिक्त आपूर्ति, संयुक्त रूप से मांग के और कमजोर होने के साथ कच्चे तेल की कीमतें मई के मध्य में तेजी से गिर गईं। नतीजतन, जुलाई की शुरुआत में ओपेक के उत्पादन में कटौती के विस्तार का कीमतों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। मई के अंतिम सप्ताह से सोने की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है, जो कि वृद्धि के लिए नीचे की ओर बढ़ते जोखिमों और खराब होती जा रही भू-राजनीतिक स्थिति के बीच सुरक्षित पनाह मांग (सेफ हेवन डिमांड) में वृद्धि से प्रेरित है। प्रमुख उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति मंद रही है।

5. वित्तीय बाजार प्रमुख केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति रुखों और तीव्र भू-राजनीतिक तनावों से प्रेरित रहे। यूएस में, यूएस फेड के डोविश दिशानिर्देशों द्वारा समर्थन से और चीन के साथ व्यापार तनाव में कुछ क्षणिक राहत से इक्विटी मार्केट मई में हुए अधिकांश नुकसानों से स्वस्थ हुए। ईएम स्टॉक अपने विकसित बाजार समकक्षों से पिछड़ गये, जिसमें मुख्य रूप से चीनी और दक्षिण कोरियाई शेयरों का कमजोर प्रदर्शन प्रतिबिम्बित हुआ। अमेरिका

में बॉण्ड प्रतिफल, जो पहले से ही नीतिगत दरों में कटौती की संभावना पर नरम पक्षपात के साथ कारोबार कर रहा था, व्यापार तनाव के बढ़ने पर अगस्त की शुरुआत में ही गिर गया। यूरो क्षेत्र में कुछ और सदस्य देशों में बॉण्ड प्रतिफल यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अधिक उदार मौद्रिक नीति रुख की उम्मीदों के कारण नकारात्मक क्षेत्र में चले गए। ईएमई में, बॉण्ड प्रतिफल प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों द्वारा अधिक उदार दिशानिर्देशों के कारण मामूली रूप से कम हुआ। मुद्रा बाजारों में, यूएस फेड द्वारा डोविश दिशानिर्देशों के कारण जून में प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर कमजोर हुआ लेकिन जुलाई में उसमें बढ़ोतरी हुई। ईएमई मुद्राएं, जो जुलाई में एक बढ़ोतरी के पूर्वाग्रह के साथ कारोबार करती रहीं, व्यापार तनाव में वृद्धि के कारण अगस्त के प्रारम्भ में कमजोर हुईं।

घरेलू अर्थव्यवस्था

6. घरेलू मोर्चे पर, दक्षिण-पश्चिम मानसून तीव्र रहा और 6 अगस्त 2019 तक दीर्घावधि औसत (एलपीए) से 6 प्रतिशत कम संचयी बारिश हुई। इसके स्थानिक वितरण के अनुसार, 36 उप-प्रभागों में से पिछले साल के 28 उप-प्रभागों के मुकाबले इस वर्ष 25 उप-प्रभागों ने सामान्य या अधिक वर्षा हुई। खरीफ फसलों के तहत बोया गया कुल क्षेत्रफल 2 अगस्त को एक वर्ष पहले की तुलना में 6.6 प्रतिशत कम था। 1 अगस्त को प्रमुख जलाशयों में तत्कालीन भंडारण एक वर्ष पहले की 45 प्रतिशत की तुलना में पूर्ण जलाशय स्तर के 33 प्रतिशत रहा। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) द्वारा मौसम की दूसरी छमाही (अगस्त-सितंबर) के दौरान वर्षा सामान्य रहने का अनुमान लगाया गया है।

7. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) द्वारा मापी गई औद्योगिक वृद्धि मई 2019 में कम हुई, जो विनिर्माण और खनन के कारण कम हुई जबकि बिजली की मांग के कारण बिजली उत्पादन में तेजी आई। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन कम हो गया। तथापि, मई में लगातार तीसरे महीने में उपभोक्ता गैर-टिकाऊता में तेजी आई। जून में आठ मूल उद्योगों के सूचकांकों के वृद्धि में कमी आई, जो कि पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और सीमेंट में संकुचन के कारण कम हो गई। रिजर्व बैंक की आदेश बही, वस्तु सूची और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) द्वारा मापा गया विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता

उपयोग (सीयू), 2018-19 की तीसरी तिमाही में 75.9 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 की चौथी तिमाही में मामूली रूप से 76.1 प्रतिशत तक बढ़ा; तथापि मौसमी समायोजित सीयू, तिमाही 3 में 75.6 प्रतिशत की तुलना में तिमाही 4 में 74.5 प्रतिशत तक गिर गया। तिमाही 1: 2019-20 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का व्यवसाय मूल्यांकन सूचकांक (बीएआई) मामूली रूप से सुधरा, जो सर्वेक्षणित फर्मों के लाभ मार्जिन में मामूली से कारण समर्थित है, जबकि उत्पादन और आदेश बही धीमे रहे। उत्पादन पीएमआई जून में 52.1 की तुलना में जुलाई में बढ़कर 52.5 हो गया, जो कि उत्पादन में बढ़ोतरी, उच्चतर नए आदेशों और आने वाले वर्ष में मांग की स्थिति में सुधार से रेखांकित किया गया।

8. मई-जून के लिए सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के उच्च आवृत्ति संकेतक एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की बिक्री - ग्रामीण मांग के संकेतक - में संकुचन जारी रहा। शहरी मांग के संकेतकों के बीच, जून में लगातार आठवें महीने में यात्री वाहन बिक्री संकुचित रही; तथापि, लगातार तीन महीने के संकुचन के बाद जून में घरेलू हवाई यात्री ट्रैफिक वृद्धि सकारात्मक रही। आधार प्रभावों को समायोजित करने के बाद भी वाणिज्यिक वाहन की बिक्री धीमी हो गई। जून में सीमेंट उत्पादन में संकुचन और तैयार स्टील की खपत में धीमी वृद्धि के साथ निर्माण गतिविधि संकेतक मंद हो गए। पूंजीगत वस्तुओं का आयात - निवेश गतिविधि का एक प्रमुख संकेतक - जून में संकुचित हुआ। नई व्यावसायिक गतिविधि, नए निर्यात आदेशों और रोजगार में वृद्धि पर पीएमआई जून में 49.6 की तुलना में जुलाई में बढ़कर 53.8 हो गई।

9. सीपीआई में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति, अप्रैल- मई में 3.0 प्रतिशत की तुलना में जून में बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गई, जो खाद्य और ईंधन मंदी को छोड़कर खाद्य मुद्रास्फीति के साथ ईंधन और सीपीआई मुद्रास्फीति द्वारा संचालित होती है।

10. मांस और मछली, दाल और सब्जियों की कीमतों में तेज उछाल के कारण खाद्य समूह की मुद्रास्फीति मई में 2.0 प्रतिशत और अप्रैल में 1.4 प्रतिशत से बढ़कर जून में 2.4 प्रतिशत हो गई। मुद्रास्फीति अनाज, दूध, मसाले और तैयार भोजन में भी बढ़ी। हालांकि, अंडे और गैर-मादक पेय पदार्थों में मुद्रास्फीति कम हुई,

और जून में फलों और चीनी एवं मिष्ठान की कीमतें अपस्फीति में बनी रही।

11. बिजली के अपस्फीति में रहने के साथ ईंधन और प्रकाश समूह में मुद्रास्फीति जून में मंद हो गयी। फायरवुड एवं चिप्स, और उपले जैसे ईंधन अप्रैल से अपस्फीति में रहे हैं। हालांकि, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और सब्सिडी वाले केरोसिन की कीमतों में मुद्रास्फीति उच्च रही।

12. खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल में 4.6 आधार से 50 आधार अंक घटकर मई में 4.1 प्रतिशत हो गई और जून में अपरिवर्तित रही। इस श्रेणी में मुद्रास्फीति में मंदी कपड़ों एवं जूतों; घरेलू सामान एवं सेवाओं; परिवहन एवं संचार; और मनोविनोद एवं मनोरंजन पर व्यापक रूप से आधारित थी। पिछले तीन महीनों में आवास मुद्रास्फीति अपरिवर्तित रही। कुछ मंदी के बावजूद, स्वास्थ्य उप-समूह में मुद्रास्फीति उच्च रही। व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव में मुद्रास्फीति जून में सोने की कीमतों में पुनरुत्थान के कारण बढ़ी।

13. भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण में जुलाई 2019 दौर में तीन महीने आगे के होरीज़ोन के लिए होरीज़ोन की उम्मीदों को पिछले दौर की तुलना में अपरिवर्तित रखा गया, लेकिन उन्होंने एक वर्ष आगे के होरीज़ोन के लिए 20 आधार अंकों की बढ़ोतरी की। कृषि और औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों से इनपुट लागत दबाव मई और जून में कम होना जारी रहा। ग्रामीण मजदूरी में नाममात्र वृद्धि मंद हो गई, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में कर्मचारियों की लागत में वृद्धि तिमाही 1 में कम हो गई। रिजर्व बैंक के औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण में भाग लेने वाली विनिर्माण कंपनियों को उम्मीद है कि तिमाही 2 में कच्चे माल की न्यून लागत के कारण इनपुट लागत दबाव मंद हो जाएगा।

14. प्रणाली में चलनिधि जून-जुलाई 2019 में (i) बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा की वापसी (ii) बैंकों द्वारा अतिरिक्त नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) के संतुलन को कम किया जाना (iii) खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) खरीद नीलामी; तथा (iv) रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा बाजार संचालन के कारण से बृहद अधिशेष में रही। रिजर्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत दैनिक निवल औसत पर जून में ₹ 51,710 करोड़, जुलाई में ₹ 1,30,931 करोड़ और अगस्त में ₹ 2,04,921 करोड़ (6 अगस्त, 2019 तक) की चलनिधि अवशोषित की। जून में ₹ 27,500 करोड़ की दो ओएमओ खरीद नीलामी के कारण सिस्टम में स्थायी चलनिधि

उपलब्ध हुई। भारत औसत मांग मुद्रा दर (डबल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य- जून में नीतिगत रेपो दर के अनुरूप रहा लेकिन औसत दैनिक आधार पर जुलाई में 14 बीपीएस तक और अगस्त (6 अगस्त, 2019 तक) में 17 बीपीएस तक नीतिगत रेपो दर से नीचे रहा।

15. एमपीसी की पिछली बैठक के बाद से बैंकों के नए रुपये ऋणों पर भारत औसत उधार दरों (डबल्यूएएलआर) के लिए नीतिगत रेपो दर का ट्रांसमिशन कम हो गया। कुल मिलाकर, बैंकों ने वर्तमान उदार रुख के दौरान अब तक (फरवरी-जून 2019) नए रुपया ऋणों पर भारत औसत व्यय दर (डबल्यूएएलआर) को 29 आधार अंकों से कम किया है।

16. रत्न और आभूषण, पेट्रोल उत्पाद, चावल, अभियंता वस्तुओं और कपास के कम प्रदर्शन के कारण जून 2019 में व्यापारिक माल की निर्यात संकुचित हुई। मई में मामूली वृद्धि के बाद आयात में जून में पेट्रोल उत्पादों की गिरती कीमतों और मोती और कीमती पत्थरों, परिवहन उपकरण, उपकरण, धातुई अयस्क, रसायन और उर्वरक की गिरती कीमतों के कारण संकुचन हुआ। चूंकि निर्यात की तुलना में आयात में भारी गिरावट आयी, मई-जून के दौरान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर व्यापार घाटे में मामूली गिरावट आई। अनंतिम आंकड़ों से पता लगता है कि मई 2019 में निवल सेवा निर्यात में क्रमिक गिरावट आई। वित्तीय पक्ष पर, निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह एक साल पहले के 7.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अप्रैल-मई 2019 में 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह पिछले वित्त वर्ष के 8.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल बहिर्वाह की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान अभी तक (05 अगस्त 2019 तक) घरेलू पूंजी बाजार में 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। मार्च 2019 की समाप्ति को भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में यूएस डॉलर 16.1 बिलियन की बढ़ोतरी होकर 2 अगस्त, 2019 को 429.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

संभावनाएं

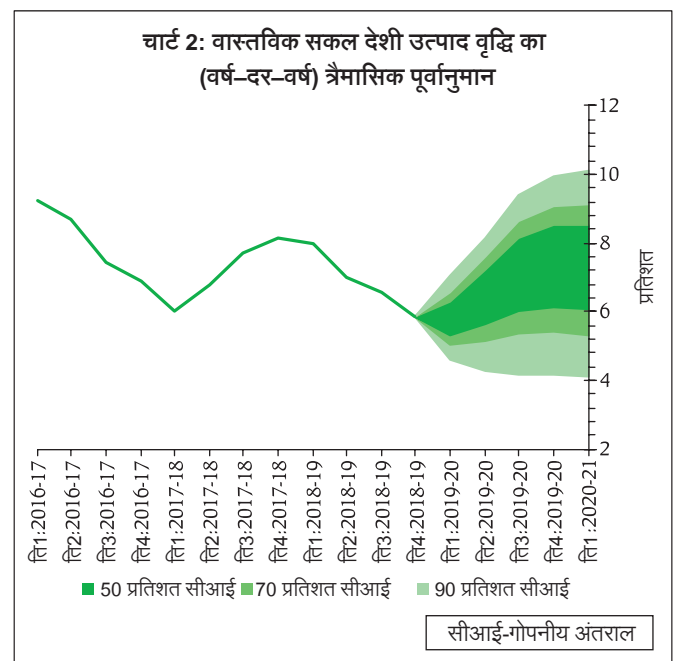
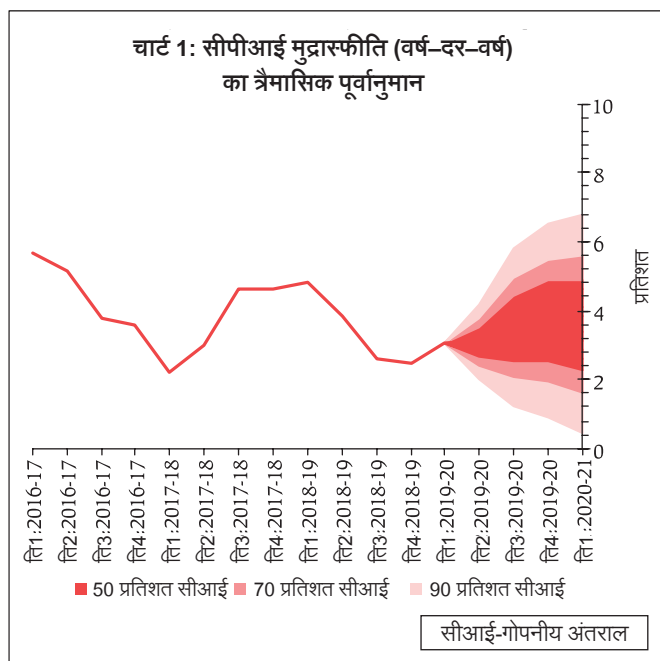
17. जून 2019 के दूसरे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति प्रस्ताव में, संतुलित जोखिम के साथ 2019-20 की पहली छमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति को 3.0-3.1 प्रतिशत और दूसरी छमाही के लिए 3.4-3.7 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया था। 2019-20 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक हेडलाइन मुद्रास्फीति परिणाम 3.1 प्रतिशत रहें जो कि इन अनुमानों के अनुरूप रहें।

18. अगली चार तिमाहियों के लिए बेसलाइन मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र को कई कारकों द्वारा आकार दिया जाएगा। सबसे पहले, हाल ही के आंकड़ों के सुझाव के अनुसार खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि सब्जियों और दालों की कीमतों के दबाव से बनी रह सकती है। मानसून का असमान स्थानिक और अस्थायी वितरण खाद्य पदार्थों पर कुछ दबाव बढ़ा सकता है, हालांकि इस जोखिम के हाल ही की बारिश में तेजी के कारण कम होने की संभावना है। दूसरा, अतिरिक्त आपूर्ति की स्थिति के बावजूद, मध्य-पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर हो सकती हैं। तीसरा, भोजन और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण मंद बना हुआ है। औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण में भाग लेने वाली विनिर्माण फर्मों को उम्मीद है कि आउटपुट कीमतें दूसरी तिमाही में कम होंगी। चौथा, रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त परिवारों की एक वर्ष आगे की मुद्रास्फीति की उम्मीदों में सुधार हो रहा है। इन कारकों और हाल की नीतिगत दर में कटौती के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, संतुलित जोखिम के साथ 2019-20 की दूसरी तिमाही के लिए 3.1 प्रतिशत और 2019-20 की दूसरी छमाही के लिए 3.5-3.7 प्रतिशत सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया गया है। 2020-21 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 3.6 प्रतिशत (चार्ट 1) अनुमानित है।

19. एमपीसी के जून के संकल्प में 2019-20 के लिए संतुलित जोखिम के साथ - 2019-20 की पहली छमाही के लिए 6.4-6.7 प्रतिशत और दूसरी छमाही के लिए 7.2-7.5 प्रतिशत की सीमा

में - 7.0 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान किया गया था। विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतक घरेलू और बाहरी दोनों मांग स्थितियों के कमजोर होने का संकेत दे रहे हैं। रिज़र्व बैंक के औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण का व्यावसायिक प्रत्याशा सूचकांक, दूसरी तिमाही में मांग की स्थितियों में मौन विस्तार दर्शाता है, हालांकि इनपुट लागत में गिरावट विकास के लिए शुभ संकेत है। फरवरी 2019 के बाद से मौद्रिक नीति में ढिलाई से आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ने में सहयोग मिलने की भी उम्मीद है। इसके अलावा, आधार प्रभाव 2019-20 की दूसरी छमाही में अनुकूल हो जाएंगे। उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए जून की नीति में, 2019-20 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2019-20 की पहली छमाही में 5.8-6.6 प्रतिशत और दूसरी छमाही के लिए 7.3-7.5 प्रतिशत की सीमा में - कुछ हद तक नीचे की ओर झुके हुए जोखिम के साथ 7.0 प्रतिशत से नीचे की ओर संशोधित होकर 6.9 प्रतिशत हो गई है; 2020-21 की पहली तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.4 प्रतिशत (चार्ट 2) पर अनुमानित है।

20. एमपीसी ने नोट किया है कि वर्तमान स्थिति में 12 महीने आगे के होरीजोन पर मुद्रास्फीति के लक्ष्य के भीतर रहने का अनुमान है। पिछली नीति के बाद से, घरेलू आर्थिक गतिविधि कमजोर बनी हुई है, वैश्विक मंदी और बढ़ते व्यापार तनाव के कारण नकारात्मक जोखिम बने हुए हैं। निजी खपत, कुल मांग का मुख्य आधार और निवेश गतिविधि सुस्त बनी हुई है। यहां तक



कि पिछली दर में कटौती को धीरे-धीरे वास्तविक अर्थव्यवस्था में संप्रेषित किया जा रहा है, सौम्य मुद्रास्फीति दृष्टिकोण नकारात्मक उत्पादन अंतर को समाप्त करने के लिए नीतिगत कार्रवाई के लिए अवसर प्रदान करता है। विकास चिंताओं का विचार करते हुए इस मोड़ पर मुद्रास्फीति की दर के अनुरूप रहकर सकल मांग, विशेष रूप से निजी निवेश को बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।

21. एमपीसी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो दर को कम करने और मौद्रिक नीति के समायोजन रुख को बनाए रखने के लिए मतदान किया।

चार सदस्यों (डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया, डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा, श्री बिभू प्रसाद कानूनगो और श्री शक्तिकांत दास) ने नीतिगत रेपो दर को 35 आधार अंकों तक कम करने के लिए मतदान किया, जबकि दो सदस्यों (डॉ. चेतन घाटे और डॉ. पामी दुआ) ने पॉलिसी रेपो दर को 25 आधार अंकों तक कम करने के लिए मतदान किया गया।

22. एमपीसी की बैठक के कार्यवृत्त 21 अगस्त 2019 तक प्रकाशित किए जाएंगे।

23. एमपीसी की अगली बैठक 1, 3 और 4 अक्टूबर 2019 के दौरान आयोजित की जाएगी।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य वित्तीय बाजारों के क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों; भुगतान और निपटान प्रणाली; बैंकिंग विनियमन, वित्तीय समावेशन और एनबीएफसी को ऋण प्रवाह को निर्धारित करता है।

I. वित्तीय बाजार

1. राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के लिए स्ट्रुपिंग / पुनर्गठन सुविधा का प्रारंभ

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 21ए के अनुसार राज्यों के लिए ऋण प्रबंधक के रूप में, रिज़र्व बैंक प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही खंडों में एसडीएल बाजार के विकास के लिए प्रयास कर रहा है। एसडीएल के लिए गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों और एग्रीगेटर्स / फैसिलिटेटर्स की योजना को प्रारंभ करना इस दिशा में किए गए कुछ प्रयास हैं। इन प्रयासों को जारी रखते हुए, एसडीएल के लिए स्ट्रुपिंग / पुनर्गठन सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह उपाय संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से कार्यान्वित किया जाएगा।

II. भुगतान और निपटान प्रणाली

2. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली की चौबीस घंटे उपलब्धता

वर्तमान में, खुदरा भुगतान प्रणाली के रूप में रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण भुगतान प्रणाली (एनईएफटी) सप्ताह के सभी कार्य दिवसों (महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर) पर पूर्वाह्न 8 बजे से शाम 7 बजे तक ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। जैसा कि भुगतान प्रणाली विजन 2021 दस्तावेज़ में उल्लिखित है, रिज़र्व बैंक दिसंबर 2019 से 24x7 आधार पर एनईएफटी प्रणाली उपलब्ध कराएगा। इससे देश की खुदरा भुगतान प्रणाली में क्रांति आने की उम्मीद है।

3. भारत बिल भुगतान प्रणाली के लिए बिलर श्रेणियों का विस्तार

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस), बारंबार बिल भुगतान के लिए एक अंतर-संचालित प्लेटफॉर्म है, जिसमें वर्तमान में पाँच खंड शामिल हैं अर्थात्, (i) डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच); (ii) बिजली; (iii) गैस; (iv) दूरसंचार; और (v) पानी के बिल। बीबीपीएस का

लाभ उठाने और इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए, बिलर्स की सभी श्रेणियों (प्रीपेड रिचार्ज को छोड़कर) को अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, जो स्वैच्छिक आधार पर बीबीपीएस में भाग लेने के लिए आवर्ती बिल भुगतान प्रदान करते हैं। नकद-आधारित बिल भुगतान के डिजिटलीकरण के अलावा, इन खंडों को ग्राहकों के लिए मानकीकृत बिल भुगतान अनुभव, केंद्रीयकृत ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र, निर्धारित ग्राहक सुविधा शुल्क और इसी तरह से अन्य भी लाभ होगा। इस संबंध में विस्तृत निर्देश सितंबर 2019 के अंत तक जारी किए जाएंगे।

4. खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए 'मांग पर' प्राधिकरण

जैसा कि 6 जून 2018 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया है, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से खुदरा भुगतान प्रणालियों में एकाग्रता जोखिम को कम करने के लिए सार्वजनिक परामर्श के लिए 21 जनवरी 2019 को एक नीति पत्र प्रकाशित किया। व्यक्तियों के एक व्यापक समूह, सार्वजनिक और निजी संस्थाओं, संस्थानों और उद्योग संघों से प्राप्त टिप्पणियों / प्रतिक्रिया ने अधिक खिलाड़ियों को भाग लेने और पैन-इंडिया भुगतान प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देने की आवश्यकता का सुझाव दिया। तदनुसार, नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए, साथ ही जोखिम के विविधीकरण से लाभान्वित होने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि संस्थाओं को, जो प्लेटफॉर्म का कार्य करने/ संचालित करने/ के लिए इच्छुक है, 'मांग पर' प्राधिकरण देने का निर्णय लिया गया है

- भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (बीबीपीओयू);
- ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरडीएस); और
- वाईट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए)

इस विषय पर निर्देश सितंबर 2019 के अंत तक जारी किए जाएंगे।

5. केंद्रीय भुगतानों धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री का निर्माण

वर्तमान में, बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक का केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी सेल सभी बैंकिंग धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए उपलब्ध एक तंत्र है। भुगतान अवसंरचना के विकास के साथ-

साथ डिजिटल भुगतान लेनदेन की मात्रा और मूल्य के मामले में डिजिटल भुगतान परिस्थिति की तंत्र पर्याप्त प्रगति कर रहा है, हितधारकों द्वारा धोखाधड़ी जोखिम निगरानी और प्रबंधन को महत्व दिया गया है। रिज़र्व बैंक का हमेशा यह प्रयास रहा है कि ग्राहकों का भुगतान प्रणाली में विश्वास बढ़े। भुगतान प्रणाली विजन 2021 में भुगतान प्रणाली में धोखाधड़ी के आंकड़ों को एकत्र करने के लिए एक रूपरेखा की परिकल्पना की गई है। इन प्रयासों को आगे बढ़ाने और त्वरित और प्रणालीगत प्रतिक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए, एक केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी रजिस्ट्री के निर्माण की सुविधा का प्रस्ताव है जो इन धोखाधड़ी को ट्रैक करेगा। भुगतान प्रणाली के प्रतिभागियों को निकट-समय पर धोखाधड़ी की निगरानी के लिए इस रजिस्ट्री तक पहुंच प्रदान की जाएगी। उभरते जोखिमों पर ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए एकत्रित धोखाधड़ी डेटा प्रकाशित किया जाएगा। इस संबंध में एक विस्तृत रूपरेखा अक्टूबर 2019 के अंत तक जारी की जाएगी।

III. बैंकिंग विनियमन, वित्तीय समावेशन और एनबीएफसी को क्रेडिट प्रवाह

6. क्रेडिट कार्ड प्राप्ति को छोड़कर उपभोक्ता क्रेडिट के लिए जोखिम भार में कमी

क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत, व्यक्तिगत ऋण और ऋणकार्ड प्राप्ति सहित, उपभोक्ता ऋण, 125 प्रतिशत या उससे अधिक का उच्च जोखिम भार आकर्षित करते हैं, यदि प्रतिपक्ष की बाहरी रेटिंग द्वारा वारंट किया गया हो। समीक्षा करने पर, व्यक्तिगत ऋण सहित उपभोक्ता क्रेडिट के लिए जोखिम वजन को, लेकिन क्रेडिट कार्ड प्राप्ति को छोड़कर, 100% तक कम करने का निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में दिशानिर्देश अगस्त 2019 के अंत तक जारी किए जाएंगे।

7. एनबीएफसी क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के उपाय:

पिछले एक साल के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अच्छी तरह से प्रबंधित एनबीएफसी/एचएफसी को क्रेडिट प्रवाह की सुविधा के लिए कई उपाय किए हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

- (i) 23 सितंबर 2018 को, रिज़र्व बैंक ने एक प्रेस प्रकाशनी जारी करते हुए कहा कि सेबी के साथ,

वह स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और आवश्यकतानुसार उपाय करेगा।

- (ii) एफएलएलसीआर (अर्थात् प्रतिभूतियां जिनकी एसएलआर और एलसीआर दोनों के लिए गणना की जा सकती है), प्रत्येक को दो अवसरों पर (27 सितंबर 2018 और 4 अप्रैल 2019) दो प्रतिशत बढ़ा दिया गया था, इसके कारण बैंक अपनी अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियों को बेचकर अतिरिक्त चलनिधि जुटाने में सक्षम हुए हैं।
- (iii) अक्टूबर 2018 में एनबीएफसी को ऋण देने के लिए विशेष रूप से 0.5 प्रतिशत का विशेष एफएलएलसीआर प्रारंभ किया गया था।
- (iv) एनबीएफसी के लिए बैंकों के एकपोजर का जोखिम भार अन्य कॉरपोरेट्स के समान अनुरूप किया गया।
- (v) बैंकों की एनबीएफसी के लिए जोखिम की विवेकपूर्ण सीमा को अन्य क्षेत्रों के साथ जोड़कर उसे बैंकों की पूंजी के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया।
- (vi) परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने या नियत करने की न्यूनतम होल्डिंग अवधि एक वर्ष से घटाकर छह महीने कर दी गई, जिससे एनबीएफसी और एचएफसी लंबी अवधि के लिए इंतजार किए बिना अपनी मूल परिसंपत्ति को सुरक्षित करके धन जुटाने में सक्षम होगी।
- (vii) सिस्टम में टिकाऊ चलनिधि को ओएमओ और विदेशी मुद्रा स्वैप की एक श्रृंखला के माध्यम से बढ़ाया गया।
- (viii) 5 जुलाई 2019 को, एफएलएलसीआर ने एनडीटीएल के 0.50 प्रतिशत को 1 अगस्त और 1 दिसंबर, 2019 को बढ़ाने का फैसला किया, जिससे बैंकों द्वारा एलसीआर की गणना के लिए एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी) को 5 जुलाई 2019 तक एनबीएफसी/एचएफसी की

अपनी बहियों में बकाया क्रेडिट की राशि से अधिक वृद्धिशील बकाया ऋण की सीमा तक फ्रंटलोड करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, उसी दिन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए आंशिक रूप से ऋण वृद्धि की केंद्रीय बजट में की गयी घोषणा के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने एक प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से, वित्तीय रूप से मजबूत एनबीएफसी / एचएफसी को अत्यधिक मूल्यांकित परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए बजट की घोषणा को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए उनकी अतिरिक्त जी-सेक होल्डिंग्स के आधार पर बैंकों को आवश्यक चलनिधि प्रदान करने के लिए अपनी सहमति दी थी।

अब यह निर्णय लिया गया है कि एनबीएफसी क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय और किए जाएँ।

(क) सामान्य एकल प्रतिपक्ष एक्सपोजर सीमा के साथ एकल एनबीएफसी के लिए बैंकों के एक्सपोजर के लिए एकल प्रतिपक्ष एक्सपोजर सीमा का सामंजस्य

1 अप्रैल 2019 से प्रभावी बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) पर संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, एक एकल एनबीएफसी के लिए बैंक का एक्सपोजर उसकी टीयर 1 कैपिटल के 15 प्रतिशत तक सीमित है, जबकि अन्य क्षेत्रों की संस्था के लिए एक्सपोजर

लिमिट बैंक की टीयर 1 पूंजी का 20 प्रतिशत हिस्सा है, जिसे असाधारण परिस्थितियों में बैंकों के बोर्ड द्वारा 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। सामान्य एनबीएफसी के साथ प्रतिपक्षीय एक्सपोजर सीमा के सामंजस्य के लिए एक कदम के रूप में, बैंक की एक्सपोजर सीमा को सिंगल एनबीएफसी के लिए बैंक की टीयर-1 पूंजी के 20% तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

(ख) प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण - बैंकों को एनबीएफसी के माध्यम से उधार देने की अनुमति

कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जो निर्यात और रोजगार के मामले में आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, में ऋण प्रवाह को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से, और इन क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने में एनबीएफसी द्वारा निभाई गई भूमिका की पहचान करते हुए, कुछ शर्तों के अधीन, यह निर्णय लिया गया कि, कृषि को ऋण देने के लिए पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) को बैंकों द्वारा दिए गए ₹ 10.0 लाख तक के ऋण (निवेश ऋण); सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ₹ 20.0 लाख तक और प्रति उधारकर्ता को ₹ 20.0 लाख (वर्तमान में ₹ 10.0 लाख से ऊपर) तक के ऋणों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी जाए।

उपरोक्त उपायों पर विस्तृत दिशानिर्देश अगस्त 2019 के अंत तक जारी किए जाएंगे।

भाषण

पुस्तक विमोचन पर गवर्नर महोदय की टिप्पणी
शक्तिकांत दास

डिजिटल वित्तीय जगत में उपभोक्ता संरक्षण – की गई पहल और उससे आगे
एम के जैन

पुस्तक विमोचन पर गवर्नर महोदय की टिप्पणी*

शक्तिकांत दास

मुझे प्रसन्नता है कि श्री वी. श्रीनिवास की पुस्तक 'इंडियाज़ रिलेशंस विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड' के विमोचन के इस आयोजन में शामिल होने का मुझे मौका मिला है। सिविल सेवा के 1989 बैच के वे एक सम्मानित अधिकारी रहे हैं और नीति निर्माण के क्षेत्र उनकी विद्वता और उनके अनुभव के साथ-साथ 2003-06 के दौरान आईएमएफ में भारत के कार्यपालक निदेशक के सलाहकार के रूप में उनके कार्यकाल का उन्हें अत्यधिक लाभ हुआ है। यह पुस्तक और आज का यह समारोह एक महत्वपूर्ण विषय पर पाठकीयता के साथ-साथ और अधिक विचार तथा विश्लेषण को बढ़ावा देगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मैक्रो आर्थिक हितों को व्यक्त करने तथा आईएमएफ के गवर्नेस के लिए आरबीआई एक संस्थान के रूप में आईएमएफ के साथ जुड़ा हुआ है।

भारत में 1966 और 1981 के पिछले फंड कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि में पुस्तक, 1991 के भुगतान संतुलन के संकट से भारत का फंड के साथ जुड़ाव से लेकर 2016 तक की अवधि तक सबसे महत्वपूर्ण अवधि पर अपना ध्यान केंद्रित करती है जिसमें आईएमएफ में भारत की एक लेनदार से एक देनदार यह स्थिति में आकस्मिक परिवर्तन को उजागर करती है। इसी अवधि में, भारतीय अर्थव्यवस्था आयात प्रतिस्थापन द्वारा संचालित अंतर्मुखी अर्थव्यवस्था से तेजी से खुलने वाली तथा गतिशील वैश्विक उभरती शक्ति बन गयी। इस अवधि के दौरान वित्तीय संकट के बाद फंड कलंकित अंतिम उधारदाता से विशेष रूप से विनिमय दर निगरानी पर केंद्रित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में विनिमय दर की निगरानी की केंद्रीय भूमिका में देखा गया। इस अवधि में, फंड ने न केवल समष्टि आर्थिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया है, बल्कि महिलाओं के सशक्तीकरण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, फिनटेक और

जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। जैसा कि डॉ. वाई. वी. रेड्डी ने पुस्तक के प्राक्कथन में कहा है: 'पुस्तक ने इस विषय पर मौजूदा साहित्य की दरार को भरा है।' मैं श्रीनिवास को इस पुस्तक के अध्ययनशील योगदान के लिए बधाई देता हूँ।

जी 20 शेरपा तथा अब फंड के गवर्नरों के बोर्ड में वित्त मंत्री के वैकल्पिक के रूप में मेरे अपने अनुभव से अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में फंड तथा फंड की भूमिका पर मैं अपने कुछ विचारों को साझा करना चाहता हूँ। इस साल अप्रैल में हुई फंड-बैंक स्प्रिंग मिटिंग में मैंने 'मुद्रा हेरफेर' जैसे लेबल का उल्लेख किया था और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की अपने बफर्स निर्माण करने की मजबूरियों के बारे में बेहतर समझ के लिए जानकारी मांगी थी। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मुद्रा हेरफेर 'की उत्पत्ति हाल ही की है, जो 2015 में हुई थी, जब यूएस ट्रेजरी ने इस विषय पर एक अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना शुरू किया था। इस पृष्ठभूमि में, यह मुख्य रूप से द्विपक्षीय धारणा के अर्थ में है। वर्तमान में, अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट देशों को तीन मानदंडों के आधार पर मुद्रा हेरफेर के रूप में दर्शाती है: (i) कम से कम 20 बिलियन यूएस डॉलर के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष; (ii) जीडीपी के कम से कम 2 प्रतिशत चालू खाता अधिशेष; और (iii) लगातार 12 महीनों में से 6 महीनों में एक तरफा शुद्ध खरीद जो 12 महीने की अवधि में अर्थव्यवस्था में कम से कम 2 प्रतिशत जीडीपी बढ़ाए। तीन मानदंडों में से दो मानदंडों को पूर्ण करने के बावजूद देश को निगरानी सूची में डाल दिया जाता है। 2018 में भारत का नाम इस सूची में शामिल किया गया था जो हाल ही में हटा दिया गया है। हाल की अवधि में, इस शब्द ने व्यापार युद्धों के कुप्रभावों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है।

एक सवाल यह है कि जब इस उद्देश्य के लिए बहुपक्षीय संस्थागत व्यवस्था मौजूद है तो लेबलिंग एक द्विपक्षीय विशेषाधिकार क्यों बन गया है? आखिरकार, करार की शर्तों की धारा 3 (ए) के अनुच्छेद IV के अनुसार फंड की स्थापना की है तथा अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की निगरानी में निवेश होता है। धारा 1 (iii) का अनुच्छेद IV, सदस्य देशों पर अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए विनिमय दरों में हेरफेर

* 26 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में 'इंडियाज़ रिलेशन विथ द इंटर नेशनल मॉनीटरी फंड' पुस्तक के विमोचन के अवसर पर श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक।

से बचने की आज्ञा देता है। धारा 3 के अनुच्छेद VIII के अनुसार सदस्यों और उनके वित्तीय एजेंटों को भेदभावपूर्ण मुद्रा व्यवस्था या एकाधिक मुद्रा प्रथाओं (MCPs) में शामिल न होना बाध्यकारी है जब तक फंड द्वारा अनुमोदित हो या धारा 2.3 के अनुच्छेद XIV, के अंतर्गत अंकित किया गया हो। MCP अवधारणा के आवेदन पर यथोचित रूप से विचार किया गया है, समझाया गया है और जरूरत पड़ने पर किए गए उपयुक्त परिवर्तनों के साथ फंड द्वारा लागू किया गया है।

स्थिर विनिमय दरों की ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन और 1973 से मुद्राओं के अस्थायी रूप से टूटने के बाद, 1978 में फंड के करार की शर्तों के दूसरे संशोधन ने अलग-अलग देशों की विनिमय दर पर अपनी निगरानी को निर्धारित करके अपने जनादेश को और अधिक स्पष्ट कर दिया। फंड के जनादेश को 2007 में यह स्पष्ट करने के लिए अद्यतन किया गया था कि विनिमय दर में हेरफेर 'फंडामेंटल मिसअलाइनमेंट' से जुड़ा था जिसके परिणामस्वरूप बाहरी अस्थिरता होती है। 2012 में सदस्यता के बीच लेबलिंग की आशंका के कारण कई समीक्षाएँ सामने आईं जब एक एकीकृत निगरानी निर्णय को अपनाया गया, जिसमें घरेलू और बाहरी स्थिरता के साथ-साथ वैश्विक जोखिमों और स्पिलओवर के बीच संबंध पर जोर दिया गया।

इस जनादेश का पालन करते हुए, फंड हर साल अपने अनुच्छेद IV के तहत परामर्श करता है, सदस्यों के आर्थिक विकास और नीतियों का विशेष रूप से विनिमय दर की नीतियों का गहराई से मूल्यांकन करता है। इसका मॉडल के एक समूह के माध्यम से कठोर तकनीकी मूल्यांकन किया जाता है। परामर्श रिपोर्ट प्रकाशित होती है और विनिमय दर के दुरुपयोग और / या कई मुद्रा प्रथाओं के किसी भी मामले को सुधार के लिए राष्ट्रीय अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है। यह अनिवार्य है, क्योंकि करार की शर्तें एक अंतरराष्ट्रीय संधि का गठन करती हैं; और भारत में, उन्हें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड और बैंक अधिनियम, 1945 के रूप में संसदीय कानून द्वारा इसे मजबूत किया गया है। इस बहुपक्षीय ढांचे को देखते हुए, द्विपक्षीय लेबलिंग का आवरण जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है, फंड की भूमिका पर प्रश्न उठाता है।

किसी भी नीति-निर्माण संस्थान की तरह, फंड की नीतियां और व्यवहार हमेशा उनकी प्रभावकारिता के संदर्भ में सही या सर्वश्रेष्ठ नहीं होंगे। जैसा कि 2005 में फंड के स्वतंत्र मूल्यांकन

कार्यालय (IEO) ने बताया, फंड के विनिमय दर की निगरानी की मुख्य जिम्मेदारी को पूरा करने में असफल रहने का एक प्रमुख कारण यह था कि कुछ सदस्य देशों के बीच एक मजबूत भावना थी कि निगरानी में समरूपता की कमी है - किसी तरह, यह मुद्रा मूल्यहास के प्रति सहिष्णु था लेकिन सराहना का विरोध करने वाले देशों का नहीं। 2017 के मूल्यांकन अपडेट में IEO द्वारा यह आलोचना की है। इस तरह की आलोचनाओं के बावजूद, आईएमएफ सीखने के लिए तत्पर है और अच्छी तरह से सम्मानित संस्था है। इसलिए, मौद्रिक, विनिमय दर, मैक्रो-प्रूडेंशियल और कैपिटल फ्लो प्रबंधन नीतियों के साथ अधिक एकीकृत ढांचे के लिए अप्रैल 2019 के फंड के प्रस्ताव के साथ जाने के लिए तत्पर हैं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि इन मुद्दों से निपटने के लिए आईएमएफ के तत्वावधान में एक बहुपक्षीय फ्रेमवर्क सबसे उपयुक्त उपाय है।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं जिस परिस्थिति में परिचालन करती हैं उसकी सराहना करनी चाहिए ताकि उनकी चुनौतियों को समझकर उनको बढ़ावा दिया जा सके। सबसे पहले, इन देशों के आघात का स्वरूप भुगतान के संतुलन से बदलकर पूर्ण-वित्तीय संकटों में परिवर्तित हुआ है। दूसरा, वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के वर्षों में, ईएमई और वित्तीय बाजारों को वैश्विक स्पिलओवरों की मार पड़ी है, जिससे अचानक वृद्धि और अचानक रुकाव या पूंजी प्रवाह का प्रत्यावर्तन दोनों को बढ़ाया है। वित्तीय सुरक्षा नेट की मौजूदा स्थिति, इस तरह की अस्थिरता के विरुद्ध आवश्यक बफर्स प्रदान करने में काफी अपर्याप्त है। इसके अलावा, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंकों के स्वैप की सुविधा ईएमई के लिए उपलब्ध नहीं है। कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, मुद्रा के उच्च उतार-चढ़ाव के कारण समष्टि आर्थिक परिणाम घोषित हुए हैं। मार्क कार्नी, गवर्नर, बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा हाल ही में व्यक्त किए गए विचारों में इसकी पुष्टि की गई है कि ईएमई के संस्थागत ढांचे में महत्वपूर्ण सुधारों को अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली और बाजार संचालित वित्त¹ में विषमताओं द्वारा ऑफसेट किया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि

¹ कार्नी, मार्क (2019), "पुल, पुश, पाइप्स: सस्टेनेबल कैपिटल फ्लोज फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर", 6 जून को टोक्यो के इंटरनेशनल फाइनेंस सिप्रग सदस्यता बैठक संस्थान में भाषण।

में, इन देशों ने पिछले दो दशकों में भंडार जमा किया है जिसके कारण पूंजी प्रवाह की संवेदनशीलता को काफी कम कर दिया है। पिछले दो दशकों में संचित भंडार जिसने कारकों को धक्का देने के लिए पूंजी प्रवाह की दबाव कारकों के प्रति संवेदनशीलता को काफी कम कर दिया है। गवर्नर कार्नी कहते हैं कि यह अतिरिक्त बीमा, ईएमई के लिए उच्च लागत पर आया है। इस संदर्भ में, मैं उल्लेख कर सकता हूँ कि उच्च लागत पर आने वाले बीमा के बावजूद, मैं यह कहना चाहूँगा कि बीमा की लागतों की अपेक्षा में वित्तीय संकटों की लागत बहुत अधिक है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ईएमई द्वारा आरक्षित निधि का निर्माण, अभी तक इतना अधिक नहीं है कि वैश्विक संक्रमण के खिलाफ अपनी मुद्राओं को संभालने के लिए स्वयं बीमा करने की आवश्यकता हो।

हम सामूहिक रूप से यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि व्यवस्थित विनिमय दर और भुगतान व्यवस्था के लिए बहुपक्षीय सिद्धांत और फ्रेमवर्क द्विपक्षीय प्रभाव से अधिक्रमित नहीं हो रहे हैं? सबसे अच्छा तरीका है कि फंड जैसे मौजूदा संस्थानों को मजबूत किया जाए और उन्हें अधिक प्रासंगिक और विश्वसनीय बनाया जाए। करार की शर्तों के अनुसार, फंड एक कोटा आधारित संगठन है, लेकिन वर्तमान में कोटा अपने संसाधनों का केवल 49 प्रतिशत है। वैश्विक वित्तीय संकट की चरमसीमा पर और इसके बाद के वर्षों में, फंड ने उधार लेने की व्यवस्था जैसे न्यू अरजमेंट टू बॉरो (NAB) और द्विपक्षीय नोट खरीद करार (NPA) सक्रिय कर दिया, जिसमें भारत ने भी योगदान दिया है। हालाँकि, उधार की व्यवस्था अस्थायी है। इसका समाधान सदस्यों द्वारा कोटा संसाधनों की प्रतिबद्धताओं में निहित है ताकि अंतिम उपाय के एक वैश्विक ऋणदाता अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का देखरेख करने वाला और एक विश्वसनीय नीति सलाहकार के रूप में फंड की वैधता को सुरक्षित किया जा सके। यह कोटा की 15 वीं सामान्य समीक्षा की तात्कालिकता दर्शाता है, जो अब चौथे वर्ष के लिए लंबित है।

वैश्विक आदेश आज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है जो अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कौशल के साथ-साथ राष्ट्रीय मौद्रिक और राजकोषीय अधिकारियों के कौशल का परीक्षण करेगा। हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय समन्वय कुछ कमजोर हो गया है। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएं (ईई) प्रतिकूल प्रभावों की पर्याप्त जानकारी के बिना लंबे समय से कम ब्याज दर की नीतियों का पालन कर रही हैं।

आज वैश्विक स्तर पर, नकारात्मक आय के साथ बांड की कुल राशि लगभग \$ 13 ट्रिलियन तक बढ़ गई है; इसका मतलब यह है कि लगभग एक तिहाई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सरकार नकारात्मक आय पर व्यापार करती है। इक्विटी प्रीमियम 4 फीसदी से अधिक हो गया है, जो कि लंबी अवधि के औसत से एक मानक विचलन है। ईई में कम ब्याज दरों पर वापस लौटने से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि लीवरेज पहले ही ईएमई में निर्मित हो चुका है और कई यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में अपेक्षित डिलीवरेजिंग पूरा नहीं हुआ है। कम वैश्विक ब्याज दरों के बीच, ईएमई में गैर-वित्तीय क्षेत्र में कुल ऋण, 2008 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के 107.2 प्रतिशत से बढ़कर 194.4 प्रतिशत हो गया। 2018 के अंत में घटकर 183.2 प्रतिशत होने से पहले मार्च 2018 तक जीडीपी के 4 प्रतिशत रहा। संकट के बाद की अवधि में शुद्ध निजी पूंजी प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो निवेश के रूप में ईएमई के लिए प्रवाहित होती है, जो भी लगभग दोगुनी है। इससे कुछ ईएमई को जोखिम है। इनमें से कुछ जोखिम कमजोर बैंक / गैर-बैंक बैलेंस शीट के रूप में सामने आए हैं और कुछ अव्यक्त हैं और सतह पर रह सकते हैं, खासकर जब वैश्विक ब्याज दर चक्र निर्णायक रूप से बदल जाते हैं। दुनिया भरोंसेमंद समाधान सुझाने के लिए आईएफ की ओर देख रही होगी। उनकी ओर से ईएमई को नीतियों का पालन करना होगा जो विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए मैक्रोइकॉनॉमिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देते हैं।

समाधान मिलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था तनावपूर्ण व्यापार सौदे, बढ़ते भू-राजनीतिक टकराव, और सीमित नीतिगत स्थान और कई अर्थव्यवस्थाओं में उच्च ऋण स्तरों के माहौल के अनिश्चित चरण में जा रही है। एक समूह के रूप में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का सामान्य सरकारी ऋण जीडीपी के 100 प्रतिशत से अधिक है। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय विस्तार भी बाधित है।

वैश्विक विकास धीमा होने की पृष्ठभूमि में यह महत्वपूर्ण है कि मौद्रिक और राजकोषीय प्राधिकारियों की नीतियां अच्छी तरह से कैलिब्रेट हो ताकि वे किसी लीवरेज और आस्ति मूल्य बुलबुले के निर्माण के बिना विकास का समर्थन कर सकें। विकास के लिए समष्टि आर्थिक स्थिरता के साथ विवेकपूर्ण नीतियां महत्वपूर्ण हैं। विश्व स्तर पर, हमें नीतिगत विस्तार, विवेकपूर्ण तरीके से इसका उपयोग और साथ ही साथ उत्पादकता में सुधार, नवोन्मेष और रोजगार सृजन के लिए संरचनात्मक सुधार पर ध्यान देने की जरूरत है।

आने वाला वर्ष इन क्षेत्रों में आईएमएफ का अपने नीति परामर्श के लिए परीक्षण करेगा। वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए वैश्विक आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए आईएमएफ और केंद्रीय बैंक आगे कैसे मार्गदर्शन करते हैं यह महत्वपूर्ण होगा।

मैंने कुछ समस्याओं पर प्रकाश डाला है जिससे मुझे वैश्विक मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली के भविष्य पर काफी आत्मनिरीक्षण

करने का मौका मिला है, खासकर जब हम आरबीआई में दिन-प्रतिदिन इन चुनौतियों का सामना करते हैं। प्रभावी समाधान के लिए एक वैश्विक खोज चल रही है। यह तलाश इतिहास और अनुभव के आधार पर होनी चाहिए, और इस संदर्भ में, मैं आपको यह पुस्तक पढ़ने की सिफारिश करता हूँ।

धन्यवाद।

डिजिटल वित्तीय जगत में उपभोक्ता संरक्षण – की गई पहल और उससे आगे*

एम के जैन

उप गवर्नर श्री कानुनो, कार्यपालक निदेशक श्रीमती मरांडी, भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य कार्यपालक निदेशकगण, बैंकों के प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विदेशी अतिथि, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य संस्थाओं के मेरे साथी।

मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैं उपभोक्ता प्रशिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी), केंद्रीय कार्यालय द्वारा इस वार्षिक आयोजन के अवसर पर व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि हम बैंकिंग लोकपाल योजना जो 14 जून, 1995 में प्रारंभ की गई थी, के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मैं जॉन एफ केनेडी के उस कथन को यहां उद्धृत करना चाहूंगा जो उन्होंने 15 मार्च, 1962 को अमरीकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था –

‘उपभोक्ता की परिभाषा में हम सभी शामिल हैं। अर्थव्यवस्था में ये सबसे बड़े आर्थिक समूह हैं, जो प्रत्येक सार्वजनिक एवं निजी आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं। अर्थव्यवस्था में कुल खर्च का दो-तिहाई हिस्सा उपभोक्ताओं द्वारा खर्च किया जाता है। लेकिन, अर्थव्यवस्था में केवल यही समूह है जो कारगर तरीके से संगठित नहीं है और जिनके विचारों को प्रायः संज्ञान में नहीं लिया जाता है।’

और हम सभी यह जानते हैं कि आज का यह दिन उपभोक्ता संरक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए कितना महत्वपूर्ण है।

उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपाय

बैंकिंग क्षेत्र में शुरुआत से ही ग्राहक सेवा और उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को जब से हमने पहचाना है तब से लेकर भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस दिशा में एक लंबी यात्रा तय की है। रिज़र्व बैंक, आम आदमी को, खुदरा ग्राहकों और छोटी संस्थाओं

को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर हमेशा ध्यान देता रहा है ताकि बड़े एवं कारपोरेट ग्राहकों की तुलना में ग्राहकों के इस तबके के प्रति बैंक/वित्तीय सेवा प्रदाताओं के दृष्टिकोण में संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। रिज़र्व बैंक एक बहु-सेवी केंद्रीय बैंक के रूप में अग्रसक्रिय रूप से सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली का निर्माण करने, वित्तीय सेवाओं के दायरे एवं पहुंच को विस्तार देने तथा बैंकों/वित्तीय सेवा प्रदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की पहल करता रहा है। वर्ष 1970 से लेकर रिज़र्व बैंक ने आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली जिसकी रिपोर्टिंग बोर्ड स्तर की समिति को की जाती है, सहित उत्तम ग्राहक सेवा के संबंध में बैंकों के लिए व्यापक दिशानिर्देशों के ढांचे का क्रमिक रूप से सृजन किया है, उसकी समीक्षा की है और उसे अद्यतन बनाता रहा है।

मैं, रिज़र्व बैंक द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उपायों के संक्षिप्त ब्योरे के साथ अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। वित्तीय सेवाओं के लिए सुव्यवस्थित तरीके से कार्य कर रहे बाज़ार के प्रति उपभोक्ता का विश्वास और भरोसा दीर्घकाल तक वित्तीय स्थिरता विकास, क्षमता तथा नवोन्मेष को बढ़ावा देता है। प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण विनियमन तथा साथ में ग्राहकों एवं विनियमित संस्थाओं के बीच समय पर विवादों के निपटारे के लिए आसानी से पहुंच बनाने की प्रणाली का होना उपभोक्ता के विश्वास को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा, वित्तीय मामलों पर ग्राहकों के लिए जागरूकता उपाय उनमें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी पैदा करते हैं और उन्हें सही वित्तीय निर्णय लेने में मदद करते हैं।

विशेष रूप से, उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्यों के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने बैंकों के ग्राहकों के लिए 14 जून, 1995 को बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की, जिसकी समय-समय पर समीक्षा की गई है ताकि वह शीर्ष स्तर पर बैंकों के ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र के रूप में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) प्रदाताओं के ग्राहकों को शामिल करने के लिए लोकपाल योजनाएं भी शुरू की हैं। ये योजनाएं रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के लिए शीर्ष स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के रूप में समय के साथ विकसित हुई हैं। मैं यहां उल्लेख कर सकता हूँ कि ये योजनाएं संबंधित योजनाओं

* श्री एम के जैन, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, द्वारा बैंकिंग लोकपाल वार्षिक सम्मेलन, मुंबई 2019 के अवसर पर दिया गया भाषण।

¹ जी-20 वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण के सिद्धांतों से संबंधित उच्च स्तरीय समिति

के अंतर्गत कवर की गई पात्र संस्थाओं द्वारा सेवाओं में कमी से संबंधित शिकायतों का लागत-मुक्त तरीके से और शीघ्र निवारण प्रदान करती हैं।

रिज़र्व बैंक ने जनता से प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए रिज़र्व बैंक में नोडल विभाग के रूप में कार्य करने के लिए 2006 में एक समर्पित ग्राहक सेवा विभाग का सृजन किया था। विभाग का अब उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग के रूप में पुनः नामकरण किया गया है, जो सूचनाओं की असमानताओं, अपर्याप्त खुलासे और अनुचित व्यवहार से उत्पन्न असंतुलन को कम करते हुए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले एवं उपभोक्ताओं के बीच समान स्तर पर कार्य करने का अवसर मुहैया कराने पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर, 2014 में रिज़र्व बैंक द्वारा ग्राहक अधिकार चार्टर² लागू किया गया जिसमें बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले व्यापक-संग्रह सिद्धांत शामिल हैं, जो उनके ग्राहकों के हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

भारत में, हमारे पास सुपरिभाषित शिकायत निवारण संरचना मौजूद है, शिकायत करने का पहला स्तर स्वयं शाखा है जहां बैंक/वित्तीय सेवा प्रदाता में शिकायत आगे ले जाने के उचित स्तर बने हुए हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि ग्राहकों की शिकायतों का समाधान पहले ही संपर्क स्थल पर बिना किसी बाधा के कर लिया जाए, और लोकपाल के पास अंतिम उपाय के रूप में शिकायत की जाए। बैंक के ग्राहकों के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दिशा में वर्ष 2015 में सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों, चुनिंदा निजी क्षेत्र एवं विदेशी बैंकों में आंतरिक लोकपाल प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू कर दिया जाना एक मील के पत्थर की हैसियत रखता है। सितंबर, 2018 में इसकी संरचना के बारे में की गई समीक्षा के आधार पर आंतरिक लोकपाल योजना को उन सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए भी विस्तारित कर दिया गया जिनकी भारत में 10 या उससे अधिक शाखाएं थीं। आंतरिक लोकपाल प्रणाली स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि बैंकों में ग्राहकों की शिकायत के समाधान के लिए पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया जा सके ताकि बैंकों के ग्राहकों को बैंकिंग लोकपाल तक पहुंचने से पहले उनकी आंशिक या पूरी तरह से समाधान न की गई शिकायतों की स्वतंत्र रूप से तथा स्वतः-समीक्षा हो

सके। आंतरिक लोकपाल प्रणाली से यह उम्मीद की जाती है कि इससे बैंकों में उपभोक्ता संरक्षण एवं शिकायत निवारण की प्रक्रिया मजबूत बनेगी।

डिजिटलाइजेशन के इस दौर में, सेवा प्रदाताओं और उनके ग्राहकों द्वारा प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्तेमाल, अनधिकृत लेनदेन किए जाने तथा उसके गहन हो जाने के मद्देनजर रिज़र्व बैंक ने ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए विनियामकीय अनुदेश जारी किए हैं।

‘अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने के संबंध में संरचना’ 6 जुलाई, 2017 को जारी की गई थी जो भुगतान और धन अंतरण लेनदेन में बढ़ते डिजिटलाइजेशन के चलते उत्पन्न होने वाले जोखिमों को देखते हुए उनमें हुई प्रगति को परिभाषित करती है, जिसमें लेनदेन के उपयोग आसानी पैदा करने तथा उसकी सुरक्षा के बीच विधिसम्मत संतुलन रखा गया है। इसके प्रावधान, प्रारंभ में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर लागू किए गए थे, लेकिन जनवरी 2019 से उन्हें पीपीआई जारी करे वाले प्राधिकृत गैर-बैंक संस्थाओं के लिए भी लागू कर दिया गया है।

वित्तीय क्षेत्र में हो रहे तीव्र उद्वेग को ध्यान में रखकर रिज़र्व बैंक क्रमिक रूप से ग्राहक सेवा से संबंधित अपने अनुदेशों एवं दिशानिर्देशों की समीक्षा की है और उसे अद्यतन बनाया है जैसे- अपने ग्राहक को जानिए(केवायसी) प्रक्रिया को आसान बनाना, यूरोपे मास्टरकार्ड एवं वीजा चिप/पिन कार्ड(ईएमवी) के निर्गम का अधिदेश, क्रेडिट के मूल्य-निर्धारण में पारदर्शिता आदि, जिसके बारे में आप भलीभांति परिचित हैं।

उपभोक्ता संरक्षण के लिए रिज़र्व बैंक की मौजूदा रणनीति यह है कि ग्राहक-उन्मुख वित्तीय प्रणाली के विकास के लिए सुगम वातावरण तैयार करना जिसके लिए वित्तीय सेवा-प्रदाताओं और उसके उपभोक्ताओं के बीच सूचना संबंधी असमानताओं को दूर करने के लिए प्रणाली स्थापित करना, प्रकटीकरण मानकों में वृद्धि करना तथा कुशल एवं कारगर शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध कराते हुए ग्राहकों की ज़रूरतों की तुलना में उत्पाद के आकार को और भी समरूप बनाया जाना सुनिश्चित करना है। वित्तीय जगत में होने वाले समस्त परिवर्तनों में तथा हुई प्रगति के माध्यम से रिज़र्व बैंक ने तीव्र उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली सुनिश्चित करने का प्रयास किया है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और जो विश्वसनीय भी है।

² भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2014 में ‘ग्राहक के अधिकार का चार्टर’ जारी किया था। चार्टर में बैंक ग्राहकों से संबंधित पांच बुनियादी अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार इस प्रकार हैं: निष्पक्ष व्यवहार, पारदर्शिता का अधिकार, निष्पक्ष एवं ईमानदारी से पेश आना, उपयुक्तता का अधिकार, निजता का अधिकार और शिकायत निवारण एवं क्षतिपूर्ति का अधिकार।

लोकपाल की भूमिका

इससे पहले कि मैं लोकपाल की भूमिका पर बात करूं, मैं यह कहना चाहूंगा कि 25 वर्ष की अपनी यात्रा में, लोकपाल और उनके स्टाफ ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने शिकायतों की बढ़ती हुई संख्या तथा उनकी जटिलताओं के संबंध में कार्रवाई की है। इसके साथ ही, अब वे निवारण ढांचे के अंतर्गत हाल में जुड़ी दो अन्य लोकपाल योजनाओं के तहत प्राप्त शिकायतों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं।

वित्तीय क्षेत्र सामान्य रूप से और बैंक खासतौर से क्रांतिकारी दौर से गुजर रहे हैं। फिनटेक की लहर ने समस्त वित्तीय उत्पादों, प्रक्रियाओं और डिलीवरी चैनल्स को अपने दायरे में ले लिया है। डिजिटलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं ने भुगतान प्रणाली की शकल को बदल कर रख दिया है। नये प्रकार की वित्तीय संस्थाएं पारंपरिक बैंकिंग कार्यप्रणाली के साथ स्पर्धा कर रही हैं, हालांकि ऐसा अभी काफी छोटे पैमाने पर है। प्रौद्योगिकी के प्रयोग और डिजिटलाइजेशन ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि वित्तीय सेवाएं बटन दबाते ही कभी भी, कहीं भी प्राप्त की जा सकती हैं। सुविधाजनक होना, संगतपूर्ण-लागत तथा स्पर्धा आज की कसौटी(हालमार्क) बन गई है।

लेकिन, साथ ही हम कई प्रकार के जाने-अनजाने जोखिमों तथा अनिश्चितताओं का सामना भी कर रहे हैं – साइबर सुरक्षा उल्लंघन, फिशिंग/विशिंग धोखाधड़ी, डाटा की चोरी और उसका दुरुपयोग, डाटा की निजता का उल्लंघन, मालवेयर अटैक आदि। जहां यह बात ज्ञात है कि ये जोखिम मौजूद हैं, वहीं यह बात अज्ञात है कि जिस रूप में ये जोखिम पैदा होते हैं वे कब पैदा होंगे और उनकी तीव्रता क्या होगी। सुविधा को लेकर ग्राहकों, संस्थाओं और विनियामकीय प्राधिकारियों के लिए ये नई चुनौतियां बन गई हैं। इस पृष्ठभूमि में देखें तो शिकायतों की बढ़ती हुई संख्या, उनकी जटिलताओं तथा बदलते वित्तीय परिवेश से मुकाबला करने की क्षमता ने लोकपाल की भूमिका को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

लोकपाल की हैसियत – वित्तीय विवादों के समाधान में 'तीसरे अंपायर' की तरह होती है- अर्ध-न्यायिक जिसमें प्राधिकार भी है और स्वतंत्रता भी। और स्पष्ट रूप से कहें तो प्राधिकार और स्वतंत्रता दोनों उत्तरदायित्व एवं उद्देश्यपरकता की दृष्टि से समानार्थक हैं। इस तरह, लोकपाल को अपने आचार, और व्यवहार तथा निर्णयों की गुणवत्ता के प्रति सतर्क रहना चाहिए। उन्हें इस बात के लिए भी जागरूक रहना चाहिए कि किसी भी

संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह के प्रति अति सक्रियता के साथ उसकी सुरक्षा करनी है। जहां यह बात सच है कि उन्हें अपने दायित्व को पूरा करने के लिए तकनीकी रूप से अन्वेषणात्मक भूमिका या अन्वेषण टूल नहीं सौंपा गया है, लोकपाल को चाहिए कि वे कम से कम संक्षिप्त निपटान के अपने सीमित अधिदेश में यह पता लगाने का दृष्टिकोण अपनाएं कि असल मुद्दा क्या है और उनमें कौन सी कमियां हैं। लोकपाल जहां अनुशासित, निष्पक्ष, सुस्पष्ट और सटीक तरीके से कार्य करते हैं, वहीं उनकी उपलब्धता ग्राहकों तक होनी चाहिए ताकि रिजर्व बैंक की प्रतिष्ठा को खतरा न होने पाए या उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली में जनता का विश्वास जोखिम में न पड़े।

लोकपाल के लिए उनका महत्वपूर्ण होना ही एक बात नहीं है, बल्कि विवादों का वस्तुनिष्ठ तरीके से समाधान करना उनकी एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए लोकपाल स्वयं को मात्र शिकायत निवारण की भूमिका तक सीमित रखने से परहेज करें। दरअसल, लोकपाल को चाहिए कि बैंकों के कारोबार-संचालन उनकी सुदृढ़ता तथा कमजोरियों के बारे में, निष्पक्ष विचार प्राप्त करने के लिए अपनी सुविधा का प्रयोग करें। विशेष रूप से, बैंकिंग लोकपाल यह सुनिश्चित करें कि विनियमित संस्थाएं अपने ग्राहकों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह रहें, तथा उनके व्यवहार रिजर्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के माध्यम से निर्धारित सुदृढ़ वित्तीय आचार के सिद्धांतों के अनुरूप हों।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता जागरूकता देश के दूर-दराज कोने तक सभी व्यक्तियों तक पहुंचे, हमें उसे प्रत्यक्ष और डिजिटल तरीके से फैलाने की आवश्यकता है। लोकपाल के लिए अपने कार्यक्षेत्र में टाउनहाल कार्यक्रमों के आयोजन एवं उसमें भाग लेना तथा अन्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन एवं उसमें सहभागिता करना सतत रूप से कार्यसूची में शामिल होना चाहिए। चूंकि ये कार्यक्रम लोकपाल कार्यालयों के बाहर आयोजित किए जाते हैं, इसलिए क्या ऐसे अवसरों का इस्तेमाल उनके नजदीक जाकर उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए किया जा सकता है? ऐसे मामले में लोकपाल को पहले से योजना बनानी होगी और शिकायतकर्ता तथा संबंधित संस्थाओं को वहां बुलाना होगा। लोकपाल तक पहुंच बनाने के संबंध में यह तरीका सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

डिजिटल माध्यमों से शिक्षा देने तथा जागरूकता फैलाने का कार्य केंद्रीय कार्यालय स्तर से किया जा रहा है। जहां इस प्रकार के प्रयासों को व्यापक पैमाने पर जारी रखने की

आवश्यकता है, वहीं जागरूकता का प्रसार स्थानीय भाषाओं में भी किया जाए ताकि समझने में आसानी हो और संप्रेषण प्रभावी हो। इसकी विषयवस्तु को सावधानीपूर्वक बनाया जाए ताकि ग्राहकों के अधिकारों, उनके दायित्वों, वित्तीय लेनदेन करने में उनकी जिम्मेदारी के संबंध में वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता का प्रसार हो और वित्तीय सूचना की सुरक्षा आसान तरीके से की जाए जो आम आदमी की समझ में आसानी से आ सके। उनकी सुरक्षा और कल्याण हेतु बनाए गए किसी भी कार्यक्रम के लिए ऐसा किया जाना महत्वपूर्ण है।

शिकायत प्रबंधन प्रणाली

लोकपाल ढांचे को प्रभावी समर्थन प्रदान करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने वर्तमान में चल रही शिकायत ट्रेकिंग प्रणाली(सीटीएस) के स्थान पर और भी उन्नत प्रौद्योगिकीयुक्त शिकायत प्रबंधन प्रणाली(सीएमएस) लागू करना शुरू किया है। नई प्रणाली रिजर्व बैंक के समस्त शिकायत निवारण तंत्र को एकसाथ जोड़ देगी जिसमें बैंकिंग लोकपाल, एनबीएफसी हेतु लोकपाल, डिजिटल लोकपाल तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के उपभोक्ता शिक्षण संरक्षण कक्ष शामिल होंगे जो ऐसी भी शिकायतों पर कार्रवाई करते हैं जो लोकपाल योजनाओं के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह नई प्रणाली समस्त विनियमित संस्थाओं – बैंक, एनबीएफसी तथा पीपीआई प्रदाताओं को अपने दायरे में ले लेगी- यह प्रणाली इस बात की भी अनुमति प्रदान करेगी कि ग्राहक स्वयं शिकायत एवं उसके समाधान की स्थिति पर नज़र रख सकें। इस प्रणाली में मैनुअल प्रक्रिया कम हो जाएगी और फलस्वरूप उसमें लगने वाला समय घट जाएगा तथा हितधारकों द्वारा उपयोग हेतु बेहतर डाटा विश्लेषण की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा, सीएमएस में, मुख पृष्ठ पर जागरूकता मॉड्यूल होगा जिसमें आडियो, वीडियो एवं लिखित फॉर्मेट में सामग्री उपलब्ध रहेगी।

बैंकों/एफएसपी की भूमिका

अब मैं बैंकों/एफएसपी की भूमिका के बारे में बात करूंगा। सभी वित्तीय संस्थाओं का उनके ग्राहकों के साथ विशेष संबंध होता है, इसलिए उनका यह कर्तव्य है कि वे वित्तीय लेनदेन में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को स्वीकार करें और ग्राहक की शिकायतों का निष्पक्ष समाधान प्रदान करें। बैंकों/एफएसपी मूल्य-निर्धारण, शुल्क तथा जुर्माना में पारदर्शिता बरतें।

बैंकों/एफएसपी के लिए केवल यही आवश्यकता नहीं है कि वे अपनी कार्यप्रणाली एवं परिचालनों के सभी पहलुओं के बारे

में पर्याप्त प्रकटीकरण करें बल्कि इस बात के लिए ग्राहकों को शिक्षा दें कि वे कौन से उत्पाद पेश कर रहे हैं, उनकी परिचालन तकनीक, उसमें निहित जोखिम, सुरक्षा तथा शिकायतों के निवारण के कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। बैंकों/एफएसपी की चूक के कारण ग्राहक को होने वाले नुकसान की देयता बैंकों/एफएसपी की होगी। अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता सीमित करने से संबंधित रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का लक्ष्य भी इसी परिप्रेक्ष्य में है। हालांकि क्षतिपूर्ति करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात जागरूकता पहल के माध्यम से 'रोकथाम' की जानी चाहिए। इससे बैंक/एफएसपी स्तर पर शिकायतों को न्यूनतम बनाने में सहायता मिलेगी और लोकपाल स्तर पर शिकायतों का बोझ भी कम हो जाएगा। जैसाकि मैंने पहले ही उल्लेख किया था, मैं यह बात और जोड़ना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक ने बैंकों में आंतरिक लोकपाल योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए पिछले वर्ष दिशानिर्देश जारी किए थे। जहां बात निहित है कि बैंकों द्वारा नियुक्त आंतरिक लोकपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, वहीं बैंकों के लिए यह समझना ज़रूरी है कि सभी शिकायतें जिन्हें आंशिक रूप से या पूरी तरह से बैंकों द्वारा निरस्त कर दिया जाता है उन्हें अंतिम रूप से बंद करने से पूर्व आंतरिक लोकपाल डेस्क से अनिवार्य रूप से गुज़रना होगा। मुझे यकीन है कि बैंक, योजना में किए गए प्रावधान के अनुसार उन्हें प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या के अनुसार पर्याप्त संख्या में आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति करने के लिए कदम उठा रहे होंगे।

उपभोक्ता संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू जिसके लिए बैंकों/एफएसपी के भीतर समर्पित रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि इससे प्रबंधन को अवगत कराते रहना चाहिए। शीर्ष और वरिष्ठ प्रबंधतंत्र, शिकायत निवारण प्रभारी को शिकायत निवारण ढांचे के कार्यनिष्पादन उसमें तेजी के प्रति जिम्मेदारी लेनी होगी और उससे गहरे से जुड़ना होगा, निहित मुद्दों पर बारीकी से निगरानी एवं चौकसी रखनी होगी। उन्हें और उनके स्टाफ को 'सच्ची सेवा' की भावना से आगे बढ़ना होगा। ग्राहक सेवा और उपभोक्ता संरक्षण को उन लक्ष्यों के कारण दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए कि मुश्किल लक्ष्य प्राप्त करने हैं और नये ग्राहकों के लिए बिक्री संबंधी प्रोत्साहन दिया

³ जुलाई, 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह अनुदेश जारी किया था कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक की देयता उस स्थिति में सीमित या शून्य होगी यदि वह अनधिकृत लेनदेन की सूचना बैंक को समय पर दे और ग्राहक के स्तर पर उस अनधिकृत लेनदेन में साथ देने के लिए कोई लापरवाही न की गई हो। इसके अतिरिक्त, ग्राहक द्वारा उस अनधिकृत लेनदेन में साथ देने की लापरवाही की गई या नहीं यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी बैंक की होगी।

जाना है। बैंकों/एफएसपी की ऐसे ही समय इन पहलुओं के लिए जरूरत महसूस होती है। ग्राहकों को गलत तथा अधुरी सूचनाएं देते हुए उत्पादों की गलत बिक्री करने से शिकायतों की बढ़ती हुई संख्या, सुरक्षा प्रोटोकाल का उल्लंघन करने से धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन का होना, ग्राहक की निजता भंग करना आदि इसी दिशा की ओर इशारा करते हैं।

अंतिम बात, ग्राहक की शिकायतों के समाधान हेतु सभी स्तर पर तीव्रता का पोषण किया जाना आवश्यक है। बैंकों/एफएसपी के भीतर प्राप्त होने वाली शिकायतों और लोकपाल कार्यालयों द्वारा उन्हें संदर्भित शिकायतों में लगने वाले समय को वर्तमान स्तर से भी और कम किया जा सकता है।

उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े मुद्दों का समाधान और शिकायत निवारण

वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित जी 20 उच्चस्तरीय सिद्धांतों को जिसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा अक्टूबर 2011 में अपनाया गया था, में अन्य बातों के साथ-साथ यह अधिदेश था कि अधिकारक्षेत्र यह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ता की पर्याप्त शिकायत संचालन तथा निवारण प्रणाली तक पहुंच हो अर्थात् ऐसी प्रणाली जिन तक उसकी पहुंच हो, वहनीय हो, स्वतंत्र हो, निष्पक्ष, जवाबदेह और सामायिक एवं कुशल हो। ये प्रणालियां उपभोक्ताओं पर अनुचित लागत न लगाएं, विलंब न करें अथवा उन पर बोझ न डालें। इन दिशानिर्देशों की तुलना में हमारे लिए और सुधार की गुंजाइश कितनी है? मैं इस संदर्भ में कुछ खास मुद्दों के बारे में बताना चाहूंगा।

- i) **शिकायत का सामयिक निपटान** - शिकायत से जुड़े पक्षकारों से अपेक्षित सभी प्रकार के इनपुट/दस्तावेज के साथ शिकायत की जांच में लगाने वाले न्यूनतम समय के बावजूद शिकायत का निपटान एक यथोचित समय में किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, आपको ज्ञात होगा कि हम इस समय एक ऐसे ढांचे पर काम कर रहे हैं जो टीएटी को ग्राहक की शिकायत के समाधान के लिए संसंगत बनाएगा और सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां प्रभार-समर्थित होंगी। शिकायतों के शीघ्र निपटान के बारे में लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और हमें भी विनियमित संस्थाओं से जवाबी कार्रवाई में होने वाले विलंब के मामले को शून्य-सहिष्णुता का फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है।

- ii) **असंधार्य शिकायतों का बढ़ता स्तर** - जहां असंधार्य शिकायतों के प्राप्त होने की अनिच्छा नहीं की जा सकती, वहीं वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त होने वाली असंधार्य शिकायतों की 48.9 प्रतिशत संख्या दो बातों की ओर संकेत करती है। पहली बात यह कि शिकायतकर्ताओं को यह जानकारी नहीं है कि शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है, और दूसरी बात यह कि कुछ मामलों में संभवतः शिकायतों को बिना पर्याप्त जांच किए बंद कर दिए जाने की प्रवृत्ति है। दोनों एफजी स्थिति में लोकपाल की ओर से और अधिक कार्य किए जाने की गुंजाइश मौजूद है।
- iii) **निरस्त की गई शिकायतों का बड़ा हिस्सा** - संधार्य शिकायतों का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से इस आधार पर निरस्त कर दिया जाता है कि इसमें बैंक की ओर से कोई कमी नहीं थी, इसलिए शिकायत तर्कसंगत नहीं थी। वर्ष 2017-18 के दौरान 33.82 प्रतिशत संधार्य शिकायतों को निरस्त किया गया था, जो यद्यपि पिछले वर्ष के 57.23 प्रतिशत से कम थी फिर भी अभी भी यह संख्या काफी है क्योंकि योजना का उद्देश्य मुद्दों का समाधान मध्यस्थता के माध्यम से किया जाता है। इतना ही नहीं, कुल शिकायतों का 8.27 प्रतिशत यह बताते हुए निरस्त किया गया है कि इसके साथ पर्याप्त दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए गए। हालांकि, कुछ अपील मामलों में, यह पाया गया था कि तथ्यों पर बेहतर ढंग से ध्यान देते हुए समीक्षा की गई होती तो उसके परिणाम दोनों पक्षकारों के लिए अधिक संतोषजनक निकलते और उसके लिए अपील प्रणाली का सहारा नहीं लेना पड़ता।
- iv) **संप्रेषण संबंधी मुद्दे** - कई बार हम ऐसे लोगों के साथ मामले को हल कर रहे होते हैं जो हमारी बातों के आशय और उससे होने वाले प्रभावों को समझ ही नहीं पाते हैं। अंततः समाधान प्राप्तकर्ता यदि यह समझ ही नहीं पता कि हमारे कहने का आशय क्या है, तो ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने का कोई मकसद ही नहीं पूरा होता है। इसलिए, इस बात की भरसक प्रयास करने की आवश्यकता है कि हम अपने पत्राचार और जागरूकता संबंधी सामग्री की कठिन शब्दावलियों को आसान बनाएं। यह भी अनिवार्य है कि स्टाफ

में इस प्रकार का कौशल विकसित किया जाए कि वे ग्राहक के साथ नरमी से पेश आए ताकि हमारे परिसर में आने वाला ग्राहक संतुष्ट होकर बाहर जाए।

- v) **बैंकों निवारण प्रणाली की प्रभावशीलता** - शिकायतों की संख्या में एक जैसी प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि अधिकांश कार्यालयों में शिकायतों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। जैसेकि मैंने पहले उल्लेख किया है, यह एक सकारात्मक संकेत भी हो सकता है कि लोकपाल प्रणाली के कार्यों पर भरोसा बढ़ रहा है। लेकिन, संख्या में कुछ हिस्से की वृद्धि होना यह भी दर्शाती है कि – ए) उत्पादों की जटिलताएं बढ़ रही हैं, तथा उन्हें प्रौद्योगिकीयुक्त बना दिया गया है, बी) वित्तीय सेवाओं का ज्यादा विस्तार हुआ है और ऐसे उपभोक्ता भी शामिल हो चुके हैं जिन्हें अपेक्षित स्तर तक की वित्तीय साक्षरता नहीं है, सी) बैंकों द्वारा डीलिंग स्टाफ/बैंकिंग संपर्कों पर निगरानी न रख पड़ना और उन्हें संवेदनशील न बना पाना, डी) आंतरिक रूप से अपर्याप्त निवारण प्रणाली, ई) अनुचित कारोबारी प्रथाओं का होना, एफ) आंतरिक लोकपाल का निष्प्रभावी होना और जी) मूल कारण का विश्लेषण न कर पाना जिससे एक ही प्रकार की शिकायतों का बार-बार प्राप्त होना। बैंकों/एफएसपी में निचले स्तर एवं नीतिगत स्तर दोनों पर इस मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है।

लोकपाल से अपेक्षाएं

में यह कहना चाहूंगा की समग्र रूप से लोकपाल कार्यालयों का निष्पाक्ष अच्छा रहा है। जो भी हो, ग्राहकों की जागरूकता, नवोन्मेष, डिजिटलाइजेशन और हितधारकों की अपेक्षाओं को लेकर बढ़ती हुई चुनौतियों को देखते हुए हमें सतत रूप से यह देखते रहने की जरूरत है कि कौन से क्षेत्रों में हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। अब मैं रिजर्व बैंक द्वारा लोकपाल से की जानेवाली अपेक्षाओं के बारे में बात करना चाहूंगा।

- i) **गुणवत्तापूर्ण परिणाम** : लोकपाल को शिकायतों का परीक्षण गहराई से करना चाहिए और वित्तीय सेवाओं के बारे में अपने विशिष्ट ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ग्राहक को किसी संसाधन या तकनीकी ज्ञान के अभाव में नुकसान न हो। निर्णय और निष्कर्ष

में वर्तमान विनियमों, लागू कानून और उद्योग की अच्छी प्रथाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके लिए लोकपाल और उनकी सहायता के अनुषंगी स्टाफ-सदस्य स्वयं को नीति और प्रथाओं में हुई नवीनतम प्रगति से अद्यतन रखें।

- ii) **निष्पक्षता** : लोकपाल को प्रक्रियागत निष्पक्षता के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। शिकायतकर्ता, विनियमित संस्था जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है और कोई व्यक्ति/संस्था यदि लोकपाल के निर्णय से सीधे-सीधे प्रभावित होती है तो उसे अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले उसका जवाब देने का अवसर दिया जाना चाहिए। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि ऐसे भी मौके आए हैं जिनमें मामले को अपील के चरण पर वापस बैंकिंग लोकपाल को संदर्भित किए जाने चाहिए थे लेकिन यह अवसर उन सभी पक्षों को नहीं दिया गया ताकि वे मामले में अपनी बात प्रस्तुत कर पाते।

- iii) **एकरूपता** : हमारा यह उद्देश्य हो कि एक जैसे मामलों में निष्कर्षों में एकरूपता होनी चाहिए। अन्यथा, बैंक यह नहीं जान पाएंगे कि उनसे उस मामले पर कार्रवाई करने की क्या अपेक्षा थी। यह भी हो सकता है कि ऐसे परिदृश्य में विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रणाली में गेम खेलने की प्रवृत्ति पैदा हो जाए। इस संबंध में बैंकिंग लोकपालों के बीच प्रायः परस्पर बातचीत और सुचनाओं को साझा करना सहायक हो सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि विभिन्न हितधारकों जैसे- बैंकिंग लोकपाल, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, बैंकिंग विनियमन विभाग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) पर आधारित एक समिति ने डिजिटल लेनदेन से संबंधित धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं की पड़ताल की है और कतिपय परिचालनगत प्रक्रियाओं की सिफ़ारिश की है ताकि उसका बेहतर समधान किया जा सके तथा संबंधित विनियामकीय अनुदेशों की समीक्षा करने का भी सुझाव दिया है। समिति की रिपोर्ट की जांच कार्यान्वयन हेतु की जा सकती है।

- iv) **सार्वजनिक जागरूकता पहल** : जब तक लोगों को यह नहीं मालूम होगा कि बैंकों/एफएसपी और

रिजर्व बैंक में समस्त “शिकायत निवारण” ढांचा “क्या और कैसा” है, तथा शिकायतें दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है, खास तौर से विभिन्न लोकपाल योजनाओं के अंतर्गत शिकायत के आधार क्या हैं, तब तक शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावशीलता को पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लोकपाल द्वारा लक्ष्य किए गए जागरूकता अभियानों और बैंकों तथा अन्य उपभोक्ता संगठनों द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अलावा, समाधान किए गए मामलों के अध्ययन की जानकारी संचार मीडिया को देने की संभावना का पता लगाया जा सकता है। संचार मीडिया की पहुंच व्यापक होगी और वह प्रभावी भी होगी।

- v) **आंकड़ों का उपयोग :** यद्यपि, योजनाओं का यह उल्लिखित उद्देश्य नहीं है, फिर भी शिकायतों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण लोकपालों द्वारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए ताकि विनियामकीय, पर्यवेक्षी तथा रिजर्व बैंक के अन्य विभागों को नीति निर्माण के लिए सार्थक अंतर्दृष्टि एवं सहायता प्राप्त हो सके। इसके अलावा, सीएमए के आंकड़ों को डाटा-विश्लेषण हेतु प्रभावी रूप से दिए जाने चाहिए ताकि उपयोगी जानकारी जैसे- सभी शिकायतों में आम बात कौनसी है, उनमें क्या काम दिए गए हैं तथा बैंकों/शाखाओं/डिलीवरी चैनल्स/ उत्पादों के बारे में आंकड़े जो प्रतिकूल स्थिति प्रदर्शित करते हैं। ये आंकड़े उपयुक्त नीतिगत एवं परिचालनगत कार्रवाइयों के उद्देश से उपयोगी हो सकते हैं।

- vi) **गुणवत्ता का आश्वासन :** अंतरराष्ट्रीय मानक आईएसओ 10003:2018, जो ग्राहक संतुष्टि के लिए एक गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन मानक है, किसी भी संगठन को ऐसी शिकायतों के लिए जिनका समाधान बाह्य संगठन द्वारा नहीं दिया जा सका है, के संबंध

में योजना बनाने, डिजाइन तैयार करने, विकसित करने, परिचालन करने, बनाए रखने तथा बेहतर एवं प्रभावी और कुशल विवाद समाधान प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश प्रदान करता है। हमारे लिए यह उपयोगी होगा कि अपनी प्रणाली में संभावित सुधार लाने के लिए ऐसे इसी प्रकार के मानकों से तुलना करते हुए अपनी प्रक्रियाओं का परीक्षण करें। इस संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि सीईपीडी द्वारा किए गए बैंकिंग लोकपाल योजना से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले हैं। हमें कुछ चुनिंदा अधिकारक्षेत्रों में सुविकसित विवाद निवारण प्रणाली सहित अपनाई जा रही प्रक्रियाओं और प्रथाओं का अध्ययन करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें रिजर्व बैंक द्वारा अंगीकार/अनुकूलन किया जा सके।

निष्कर्ष

अपनी बात समाप्त करते हुए मैं एक बार पुनः जॉन एफ केनेडी के कथन को उद्धृत करना चाहूंगा :

‘किसी भी कार्य को करने में जोखिम होते हैं और लागतें लगती हैं – लेकिन ये जोखिम और लागतें, आरामदेह निष्क्रियता के कारण लंबे समय तक लगाने वाली लागतों से कहीं ज्यादा कम हैं।’

यथास्थिति के साथ जिन्हे बदलाव लाने के लिए खास प्रयास न करने के लंबे समय तक निष्प्रभावी और अनुपयुक्त नतीजे होंगे। इसलिए, आईए हम समय के साथ आगे बढ़ें और उभरते रहने के लिए संकल्प लें।

मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन के दौरान किए जाने वाले विचार-विमर्श से वित्तीय क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को बेहतर बनाने की दिशा में समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने हेतु ठोस कार्रवाई बिंदु उभर कर सामने आएंगे।

आप सभी को मेरी शुभकामनाएं।

लेख

डिजिटल भुगतान के उत्प्रेरक: अंतर-देशीय अध्ययन

भारत में एनईएफटी लेनदेन का नेटवर्क विश्लेषण

डिजिटल भुगतान के उत्प्रेरक: अंतर-देशीय अध्ययन*

मुद्रा के मुकाबले डिजिटल भुगतान के कई फायदे होते हैं जैसे सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता। आठ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) और आठ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के पैनेल डेटा रिग्रेशन से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, उच्च शिक्षा का स्तर, डिजिटल बुनियादी ढांचे की व्यापक उपलब्धता, अधिक इंटरनेट पैठ, वित्तीय गहनता और कीमत स्थिरता किसी अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान को बढ़ाने में मदद करते हैं।

परिचय

डिजिटल क्रांति ने मानव जीवन के कई क्षेत्रों पर असर डाला है और उसमें आमूलचुल परिवर्तन ला दिया है। डिजिटल भुगतान में प्रगति इस क्रांति की एक प्रमुख विशेषता रही है। सुविधा, सुरक्षा और चलनिधि जैसे सुस्पष्ट फायदों के अलावा, लेन-देन के डिजिटल तरीकों के अन्य फायदों में जवाबदेही और ट्रेकिंग को बढ़ाकर पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है, और इस तरह दुरुपयोग और चोरी की गुंजाइश कम हो जाती है। अक्सर वित्तीय सेवाओं की एक सीमा तक पहुंच को बढ़ाकर डिजिटल भुगतान अक्सर कम लागत पर वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देते हैं। यद्यपि देशभर में मूल्य और परिमाण दोनों के मामले में हाल के वर्षों में डिजिटल भुगतान¹ धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तथापि आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि उसी समय सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में मुद्रा भी समग्र आर्थिक वृद्धि के अनुरूप बढ़ी है। हालांकि, कई विसंगतियां इस प्रवृत्ति में दिखाई देती हैं: पहला, कोई देश कितना विकसित है इसका डिजिटल भुगतान के उपयोग और प्रसार का कोई विशेष संबंध नहीं है - कई ईई का जीडीपी अनुपात की तुलना में डिजिटल भुगतान कम हैं जबकि कुछ ईएमई ऐसे हैं जिनके अनुपात की तुलना ईई से की जा सकती है; दूसरा, एक निश्चित अवधि में जीडीपी अनुपात की तुलना में डिजिटल भुगतान में वृद्धि होती है

* यह आलेख आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) के डॉ. स्नेहल एस. हेरवाडकर, राधेश्याम वर्मा और प्रबल बिलंतू द्वारा तैयार किया गया है। आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं।

¹ जीडीपी अनुपात की तुलना में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों पर लेनदेन के मूल्य के संदर्भ में आकलन किया गया है।

तो इसका स्वतः आशय यह नहीं है कि देश की जीडीपी अनुपात की तुलना में मुद्रा में गिरावट हो ही। इस प्रकार, नीति के नजरिए से देखें तो यदि डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग को एक वांछनीय उद्देश्य माना जाता है, तो इसके प्रसार में योगदान करने वाले कारकों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण आवश्यक है और यही इस लेख का उद्देश्य है।

वर्ष 2003-2016 की अवधि के लिए 8 ईई और 8 ईएमई के पैनेल डेटासेट का उपयोग करते हुए, हमने डिजिटल भुगतान और प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी अनुपात की तुलना में ऋण, मुद्रास्फीति, इंटरनेट पैठ, कुल जनसंख्या में ग्रामीण आबादी की हिस्सेदारी और शिक्षा का स्तर जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के बीच संबंधों की जांच की है। देश-विशिष्ट व्यवहारिक विसंगतियों को दूर करने के लिए, हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि सहायक बुनियादी ढांचे और मैक्रोइकॉनॉमिक और कीमत स्थिरता डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाने में मदद करते हैं।

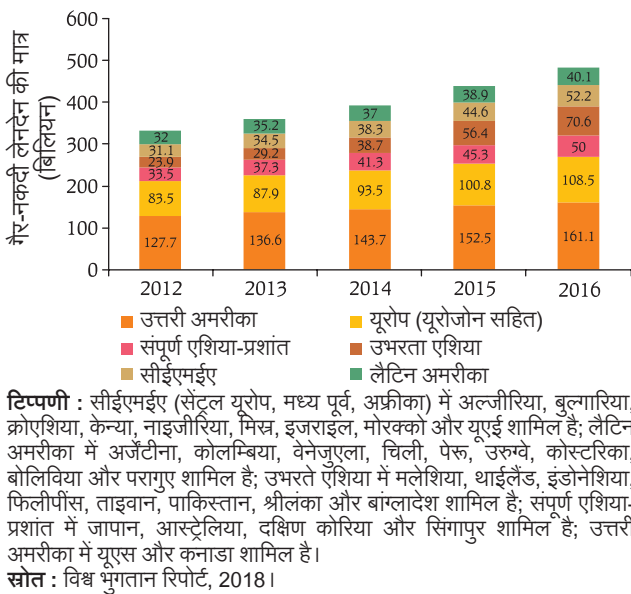
लेख का शेष भाग निम्नानुसार आयोजित किया गया है: डिजिटल भुगतान के मामले में अंतर-देशीय अनुभव को खंड II में शामिल किया गया है। हाल के वर्षों में भारत में डिजिटल भुगतान के विस्तार के संबंध में कुछ शोधपरक तथ्यों को खंड III में दिया गया है। अब तक के अनुभवजन्य साक्ष्य से संबंधित संक्षिप्त साहित्य सर्वेक्षण को खंड IV में प्रस्तुत किया गया है। खंड V में प्रमुख निष्कर्षों के साथ अनुभवाश्रित विश्लेषण के लिए प्रयुक्त कार्यपद्धति के बारे में बताया गया है। निष्कर्ष खंड VI में दीए गए हैं।

II. डिजिटल भुगतान में प्रवृत्ति: अंतर-देशीय विश्लेषण

वैश्विक स्तर पर गैर-नकद लेनदेन की मात्रा 2012-2016 की अवधि के दौरान 9.8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ी, जो उभरते एशिया और सीईएमईए (मध्य यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका) (विश्व भुगतान रिपोर्ट 2018) द्वारा संचालित थी। गैर-नकद लेनदेन में मात्रा के मामले में अधिकांश हिस्सेदारी भले ही ईई की हो, लेकिन ईएमई तेजी से उनके निकट पहुंच रहे हैं (चार्ट 1)।

इस तथ्य के बावजूद कि एक समूह के रूप में ईएमई डिजिटल भुगतान में लंबी छलांग लगा रहे हैं, अलग-अलग देशों से प्राप्त डेटा और साक्ष्य कुछ विसंगतियों की ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले, डेटा पर एक सरसरी नज़र डालने से पता चलता है कि डिजिटल भुगतान के उपयोग की प्रसार और तीव्रता

चार्ट 1: गैर-नकदी लेनदेन: क्षेत्रवार



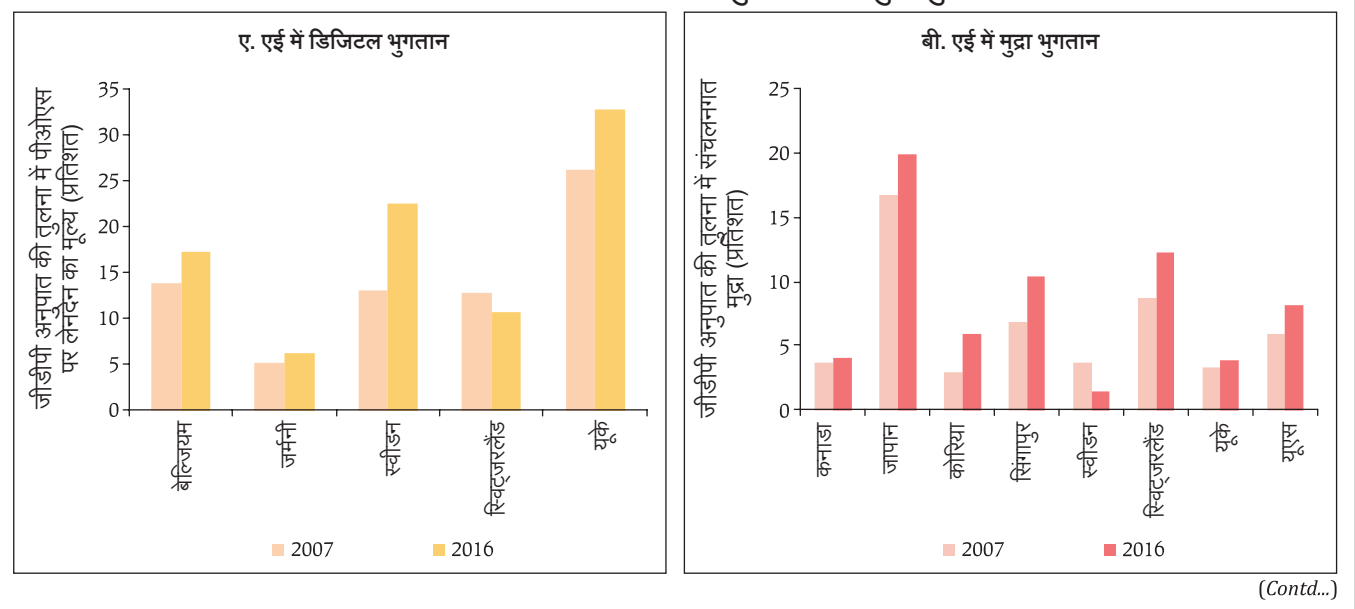
हमेशा देश के सकल घरेलू उत्पाद के स्तर के साथ-साथ नहीं बढ़ती है। जहां जर्मनी की तरह कुछ आई में जीडीपी अनुपात² की तुलना में डिजिटल भुगतान कम है, वहीं कुछ ईएमई और आई में यह अनुपात काफी समान है (उदाहरण के लिए, ब्राजील जैसे ईएमई में अनुपात बेल्जियम के अनुपात के काफी करीब है)। इसके विपरीत, किसी उच्च जीडीपी स्तर का भी स्वतः यह

अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि वहाँ मुद्रा का प्रयोग कम है। उदाहरण के लिए, जापान में जीडीपी अनुपात की तुलना में मुद्रा का सर्वाधिक प्रयोग होता है - यहां तक कि अधिकतर ईएमई की तुलना में सबसे ज्यादा है - और दुनिया में जीडीपी अनुपात की तुलना में कैशलेस भुगतान सबसे कम एक है। दूसरा, समय के साथ जीडीपी अनुपात की तुलना में डिजिटल भुगतान में वृद्धि से ऐसा नहीं लगता है कि मुद्रा के उपयोग में कमी आयी है। उदाहरण के लिए, ब्राजील, मैक्सिको, सऊदी अरब और भारत में 2016 को समाप्त दशक में जीडीपी अनुपात की तुलना में डिजिटल भुगतान में काफी वृद्धि हुई, लेकिन इन देशों में जीडीपी अनुपात की तुलना में मुद्रा का उपयोग या तो स्थिर रहा या बढ़ा (चार्ट 2)। इन विसंगतियों की पृष्ठभूमि के निमित्त देखें तो यह स्पष्ट है कि डिजिटल भुगतान में वृद्धि के उत्प्रेरकों की पहचान करने के लिए कई आर्थिक और व्यवहारात्मक कारकों के संयोजन का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, जो इस आलेख का उद्देश्य है।

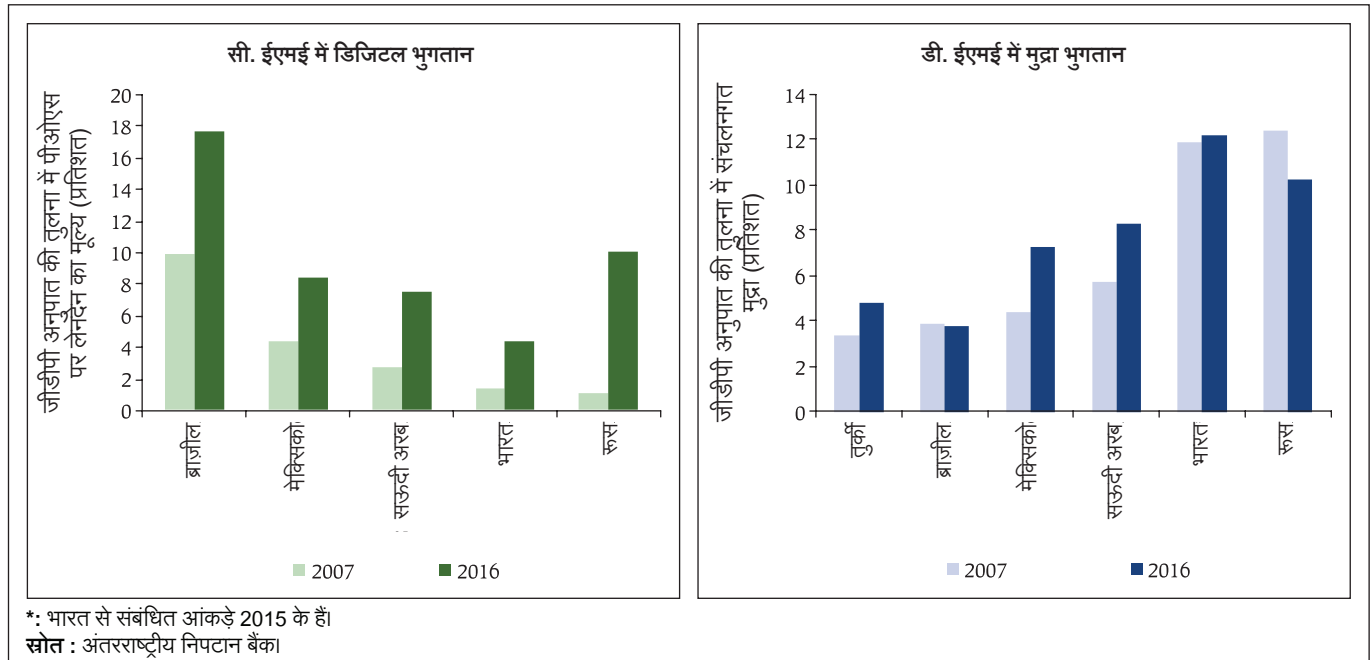
III. विश्व की तुलना में भारत में डिजिटल भुगतान: शोधपरक तथ्य

यद्यपि भारत में जीडीपी अनुपात की तुलना में डिजिटल भुगतान पारंपरिक रूप से कम रहा है, तथापि पिछले कुछ वर्षों में कैशलेस भुगतानों के विभिन्न लिखतों को पेश करने और बढ़ावा देने के मामले में इसने लंबी छलांग लगायी है, जिसके

चार्ट 2: ईएमई और आई में डिजिटल भुगतान और मुद्रा भुगतान

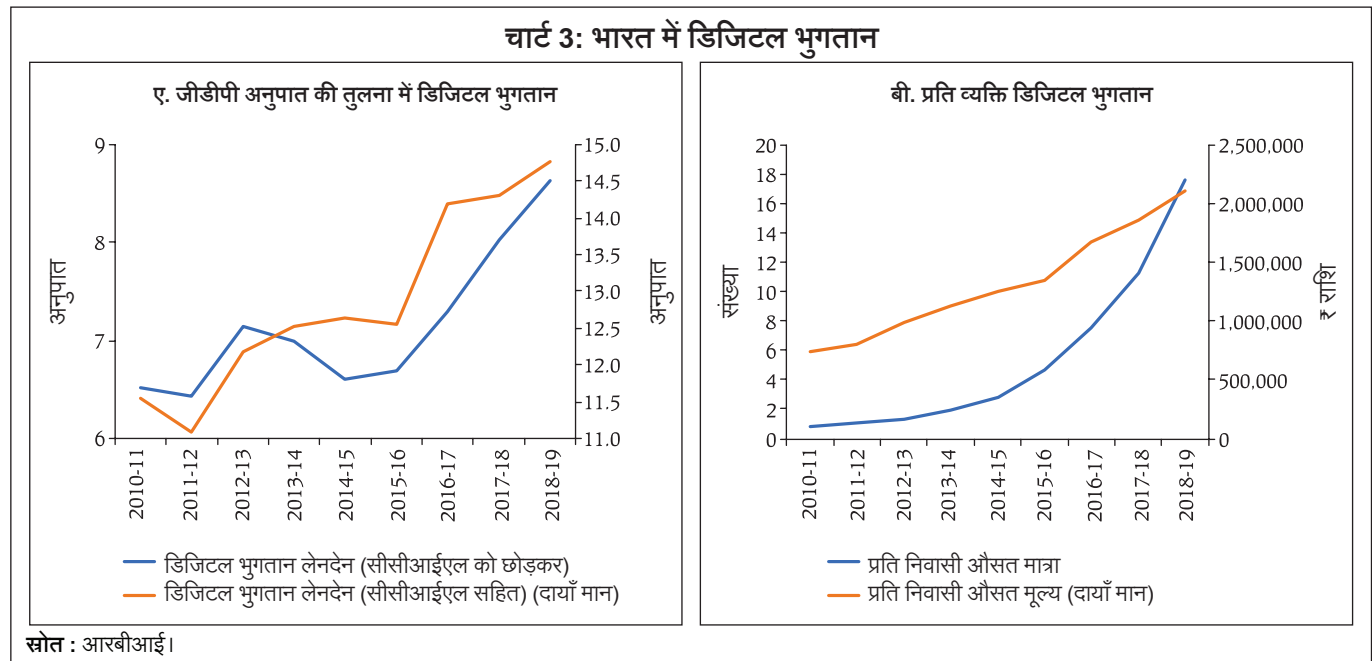


² जीडीपी अनुपात की तुलना में पीओएस टर्मिनलों पर लेनदेन के मूल्य के संदर्भ में आकलन किया गया है।



परिणामस्वरूप डिजिटल भुगतान लेनदेन³ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेष रूप से विमुद्रीकरण के बाद (चार्ट 3ए)। मूल्य और मात्रा दोनों के मामले में प्रति व्यक्ति डिजिटल भुगतान भी साथ-साथ बढ़ा (चार्ट 3बी)।

प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) जैसे खुदरा भुगतान के कुछ नए तरीकों के उभरने के कारण कुल भुगतान में खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान⁴ की हिस्सेदारी मात्रा और मूल्य दोनों के लिहाज से 2011-12



³ डिजिटल भुगतान लेनदेन में तत्काल सकाल भुगतान (आरटीजीएस), खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन (इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) और पीओएस टर्मिनलों पर कार्ड से भुगतान शामिल हैं।

⁴ खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में ईसीएस डेबिट शामिल है; ईसीएस क्रेडिट; एनईएफटी, आईएमपीएस, एनएसीएच, यूपीआई।

चार्ट 4: भुगतान प्रणाली संकेतक

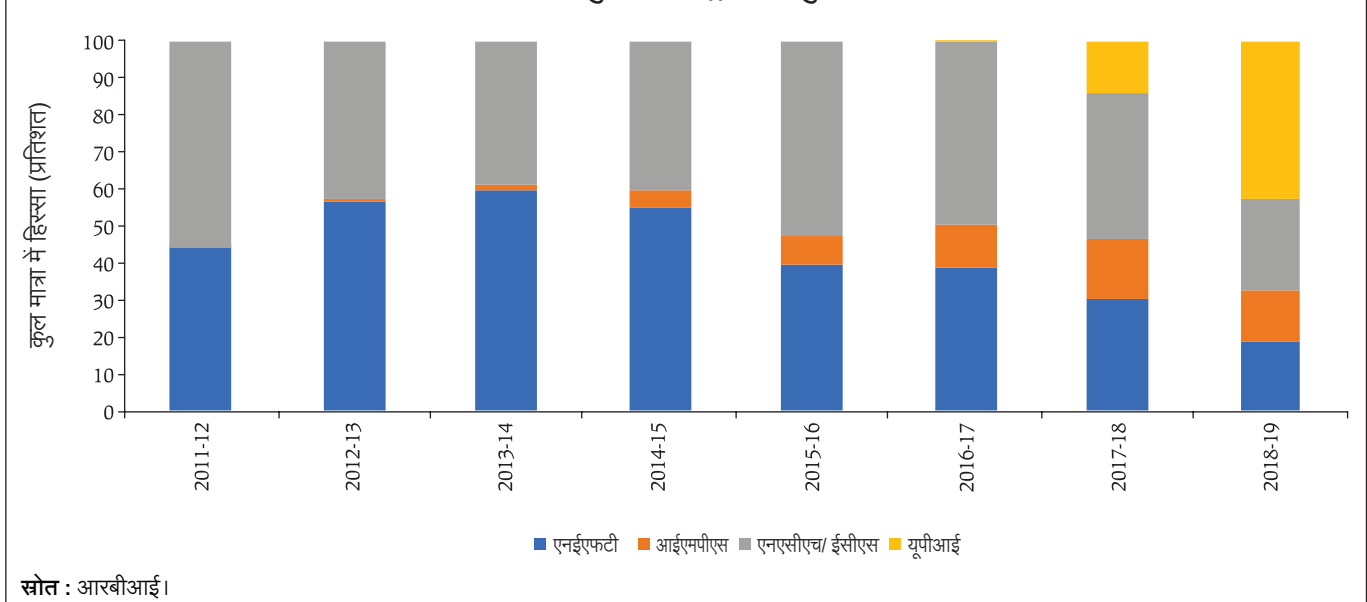


से लगातार बढ़ रही है। इसी समय, मात्रा के लिहाज से कार्ड से भुगतान⁵ की हिस्सेदारी घट रही है, हालांकि यह अभी भी भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। मूल्य के मामले में देखें तो तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) और भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से ही भुगतान की प्रमुखता है। वर्ष 2018-19 के दौरान मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में

देखें तो पेपर क्लियरिंग का हिस्सा घट कर कुल भुगतान प्रणाली लेनदेन का लगभग 3 प्रतिशत तक आ गया है (चार्ट 4)।

वर्ष 2016-17 में यूपीआई की शुरुआत ने खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के परिदृश्य को बिल्कुल बदल दिया - इसमें यूपीआई की हिस्सेदारी तीन साल में बढ़कर 43 प्रतिशत हो गई (चार्ट 5)।

चार्ट 5: खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान



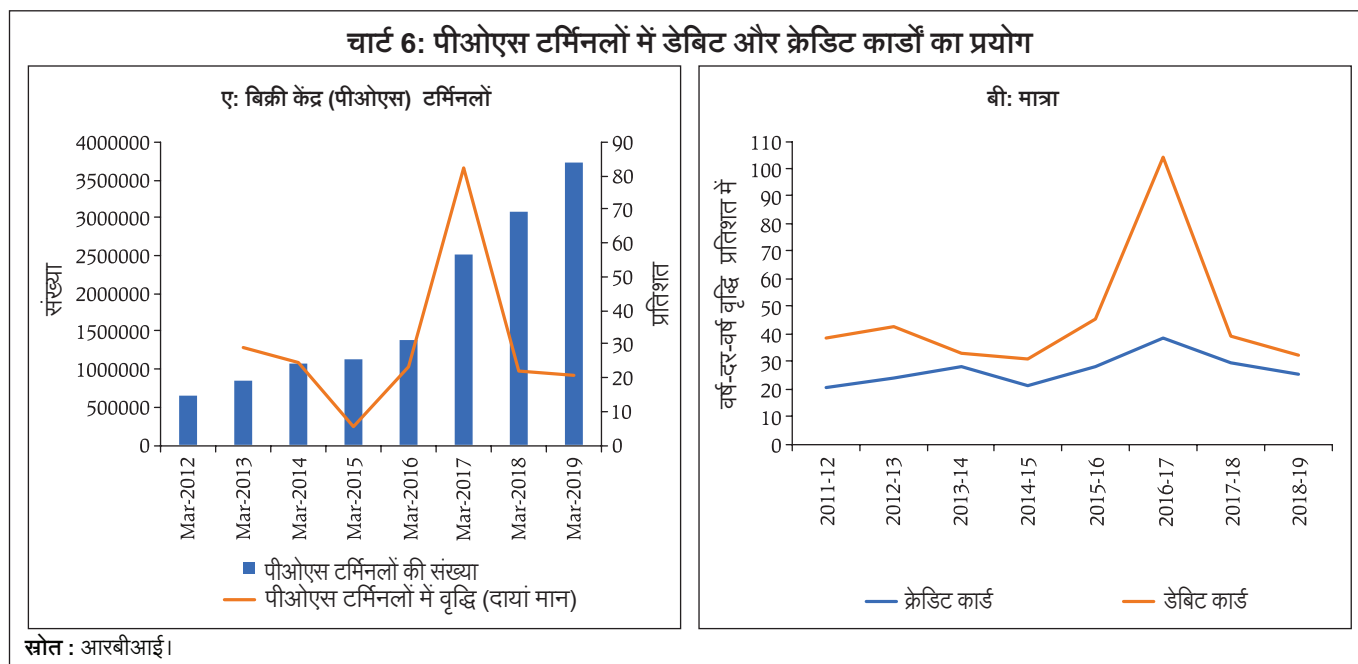
⁵ कार्ड भुगतान डेटा में डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों के पीओएस टर्मिनलों पर लेनदेन शामिल होता है।

बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों पर डेबिट कार्ड के कुल उपयोग⁶ के अनुपात के रूप में इसके उपयोग पर गौर करें तो हाल के वर्षों में इसमें तेजी देखी गयी है। मात्रा के लिहाज से, वर्ष 2018-19 में इनकी हिस्सेदारी बढ़कर 31 फीसदी हो गई, जो 2011-12 में 6 फीसदी थी, जबकि इसी अवधि के दौरान मूल्य के लिहाज से हिस्सेदारी बढ़कर 3 फीसदी से बढ़कर 16 फीसदी हो गयी। पीओएस टर्मिनलों पर डेबिट कार्ड के उपयोग में वृद्धि आम तौर पर क्रेडिट कार्ड की तुलना में अधिक रही है। डेबिट कार्ड के उपयोग में जबरदस्त वृद्धि का कारण प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत रूपे कार्ड के माध्यम से दिया जाने वाला जोर, पीओएस टर्मिनलों की संख्या में वृद्धि और डिजिटल भुगतान के लिए सरकार और व्यापारियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहन हो सकते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान विमुद्रीकरण के कारण पीओएस टर्मिनलों की संख्या और डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड का प्रयोग काफी बढ़ गया। यद्यपि विमुद्रीकरण के बाद की अवधि में पीओएस टर्मिनलों पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड के उपयोग में जो वृद्धि हुई थी उसमें गिरावट आ गयी, फिर भी यह ऊंचे स्तर पर बना रहा (चार्ट 6)।

डिजिटल भुगतानों का व्यापक रूप से उपयोग दोनों आपूर्ति पक्ष कारकों (जैसे कि मजबूत भुगतान प्रणाली के बुनियादी ढांचे, ई-भुगतान की कम लागत, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने

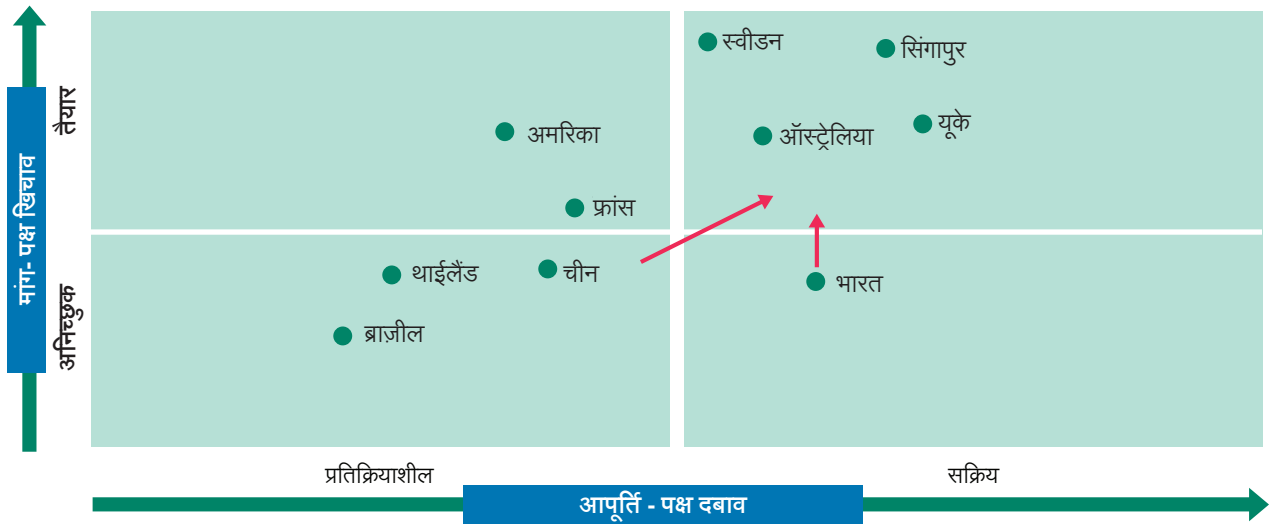
के लिए नई और अभिनव योजनाओं की शुरुआत, अधिक से अधिक वित्तीय साक्षरता और बैंक खातों पर जोर) और मांग पक्ष कारकों (जैसे सुविधा, सुरक्षा और इससे जुड़े लाभों के कारण ई-भुगतान के लिए मजबूत उपभोक्ता मांग) पर निर्भर करता है। द वर्ल्ड पेमेंट्स रिपोर्ट, 2018 में कहा गया है कि यूके, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन दोनों नियामक आपूर्ति-पक्ष और मांग-पक्ष के मामले में अग्रणी हैं (चार्ट 7)। भारत में, सरकार और रिजर्व बैंक ने विभिन्न उपाय किए हैं, जिससे डिजिटल भुगतान का उपयोग और पैठ को बढ़ाने में मदद मिली है। यूपीआई, पीपीआई जैसी पहलेकदमी, जन-धन खातों और आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से रूपे डेबिट कार्ड की पहुंच में उल्लेखनीय विस्तार से डिजिटल भुगतान की आदत को लोकप्रिय बनाने और आत्मसात करने में काफी मदद मिली है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा देने और हल्की नकदी वाले समाज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई उपायों को शुरू करने में रिजर्व बैंक अग्रसक्रिय रहा है। रिजर्व बैंक की 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: विज्ञान 2019-2021' में दक्षता बढ़ाने, संरक्षित, सुरक्षित, सुलभ और सस्ती भुगतान प्रणाली की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों के साथ-साथ उन लोगों की सेवा करने के लिए भी प्रयत्न किया गया है जो भुगतान प्रणाली से अबतक अछूते हैं।

चार्ट 6: पीओएस टर्मिनलों में डेबिट और क्रेडिट कार्डों का प्रयोग



⁶ कुल उपयोग में एटीएम और पीओएस टर्मिनलों का उपयोग शामिल है।

चार्ट 7: डिजिटल भुगतानों को प्रभावित करने वाले मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष के कारक



स्रोत : विश्व भुगतान रिपोर्ट, 2018।

हालाँकि इन पहलों के कारण भारत में डिजिटल भुगतान को अपनाने में कुछ प्रगति परिलक्षित हुई है, लेकिन भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग बड़े उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है (चार्ट 8 ए और 8 बी)।

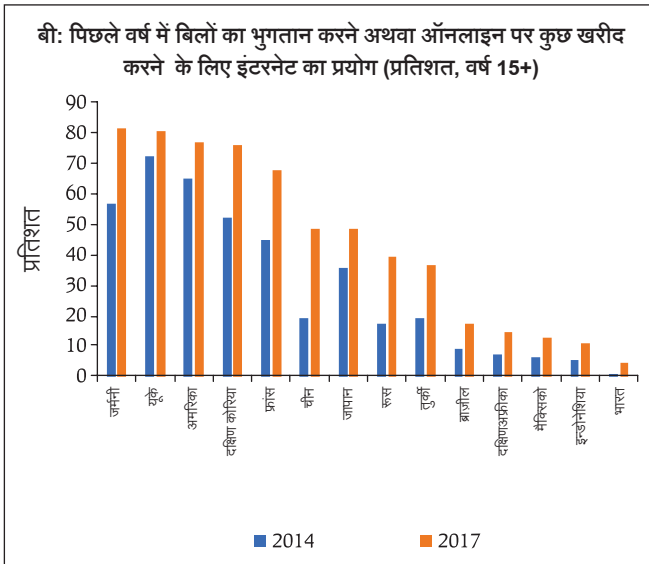
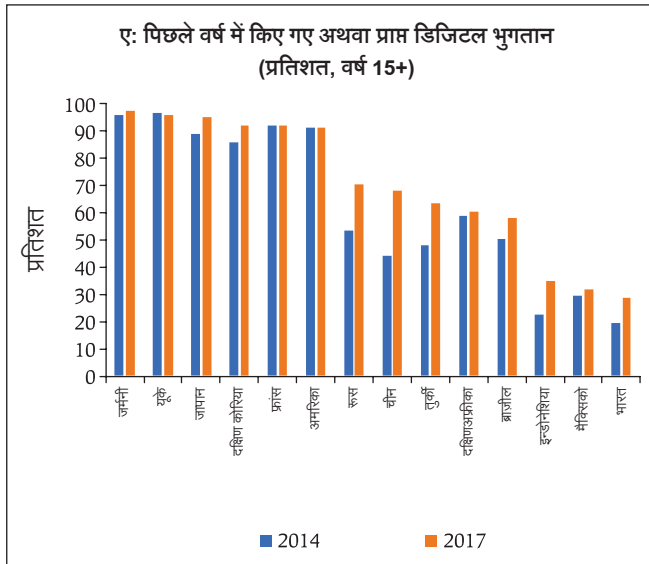
भुगतान प्रणाली के बुनियादी ढांचे के विभिन्न संकेतकों और उपयोग जैसे कि प्रति निवासी कार्डों की संख्या, प्रति निवासी नकदी रहित भुगतानों की संख्या और प्रति निवासी

नकदी रहित भुगतानों के मूल्य के मामले में भारत एई और अन्य ईएमई से पीछे है। इसी समय, संकीर्ण मुद्रा के प्रतिशत के साथ-साथ जीडीपी के प्रतिशत के रूप में संचलनगत मुद्रा का मूल्य अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक रहा (सारणी 1)।

IV. साहित्य समीक्षा

इस विषय पर अनुभवजन्य शोध ने कुछ सामान्य कारकों की पहचान की है जो डिजिटल भुगतान उपयोग की तीव्रता को बढ़ाते

चार्ट 8: विभिन्न देशों में डिजिटल भुगतान का प्रसार



स्रोत : विश्व फिडैक्स डाटाबेस, विश्व बैंक

सारणी 1: चुनिंदा भुगतान प्रणाली संकेतकों की अंतर-देशीय तुलना (2017)

देश	संकीर्ण मुद्रा और संचलन में मुद्रा का अनुपात (%)	सकल घरेलू उत्पाद और संचलन में मुद्रा का अनुपात (%)	प्रति निवासी कार्ड (डेबिट + क्रेडिट) की संख्या	प्रति निवासी नकदी रहित भुगतान की औसत संख्या	प्रति निवासी कैशलेस भुगतान का औसत मूल्य (यूएसडी)	प्रति निवासी पीओएस टर्मिनलों की संख्या
अर्जेंटीना	63.3	6.8	2.4	46.7	35,278	0.01
ऑस्ट्रेलिया	22.8	4.5	2.8	497.2	539,748	0.04
ब्राज़िल	65.2	3.8	2.3	150.2	72,549	0.02
कनाडा	9.4	4.3	2.9	366.7	129,441	0.04
चीन	14.2	9.5	4.9	96.3	386,045	0.02
फ़्रांस	NA	NA	1	339.4	477,920	0.03
जर्मनी	NA	NA	1.4	254.3	760,628	0.01
भारत*	57.6	11.2	0.7	18.3	3,910	0.003
इंडोनेशिया	50	5.1	0.7	34.3	6,993	0.005
इटली	NA	NA	1.3	99.7	168,733	0.04
जापान	14.9	20.4	3.5	NA	234,401	NA
कोरिया	12.7	6.2	5.1	499.9	426,066	NA
मेक्सिको	36.1	6.7	1.4	36.7	132,776	0.01
रूस	48.9	10.4	1.9	175.7	86,527	0.02
सऊदी अरब	17.3	7.9	1	29	563,294	0.01
दक्षिण अफ्रीका	9.2	3.4	NA	80.5	40,524	0.01
तुर्की	29.7	4.3	2.1	65.9	51,419	0.03
यूनाइटेड किंगडम	NA	NA	2.5	410.9	1,791,862	0.04
संयुक्त राज्य अमेरिका	44.3	8.2	4.2	473.4	601,977	NA

टिप्पणी : * भारत के लिए आंकड़ा वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित है और इसे आरबीआई स्रोत से लिया गया है। नकदी रहित भुगतान से संबंधित आंकड़ों में आरटीजीएस और सीसीआईएल लेनदेन शामिल नहीं है।
एनए – आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक।

अथवा घटाते हैं। इन अध्ययनों से पता चलता है कि नकदी का उपयोग कम-मूल्य के लेनदेन के लिए अधिक बार किया जाता है। नकदी का उपयोग शिक्षा और आय के उच्च स्तर के साथ घटता है। डिजिटल अवसंरचना की उपलब्धता नकदी उपयोग को कम कर सकती है, और पुरानी पीढ़ियों द्वारा नकदी का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग किया जाता है (डेविस एवं अन्य, 2016)।

नकदी की मांग आम तौर पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से उलट पाई जाती है, यानी, नकदी उपयोग में गिरावट आती है क्योंकि देश अमीर बनते जाते हैं (बेक एवं अन्य, 2018)। एक अनुमान के मुताबिक, उच्च आय वाले घरों में क्रेडिट कार्ड, एटीएम, डायरेक्ट डिपॉजिट, इंटरनेट बैंकिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र का अधिक से अधिक उपयोग होता है। इसके अलावा, अच्छा-खासा शिक्षित व्यक्ति सामान्य रूप से, डिजिटल भुगतान के विचार के लिए अधिक खुले और ग्रहणशील पाए जाते हैं (स्टाविन्स, 2001)। इसके अलावा, शिक्षित व्यक्तियों को अक्सर नौकरी मिलती है जहां वेतन सीधे बैंक अंतरण द्वारा भुगतान किया जाता है, जो कार्ड से किए जाने

वाले भुगतान को अधिक सुविधाजनक बनाता है (गोकज़ेक और विटकोव्स्की, 2016; बर्गमैन एवं अन्य, 2007)।

इसके अलावा, जनसंख्या की औसत आयु और नकदी के लिए लेन-देन की मांग के बीच एक सकारात्मक संबंध प्रतीत होता है, क्योंकि युवा लोगों को भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करने की अधिक संभावना है, यहां तक कि छोटे मूल्य के लेनदेन के लिए भी, जबकि बुजुर्ग व्यक्ति भुगतान के लिए नकदी का उपयोग करते हैं (स्टाविन्स, 2001; एस्सेलिक और हर्नांडेज़, 2017; बेक एवं अन्य, 2018; बर्गमैन एवं अन्य, 2007)।

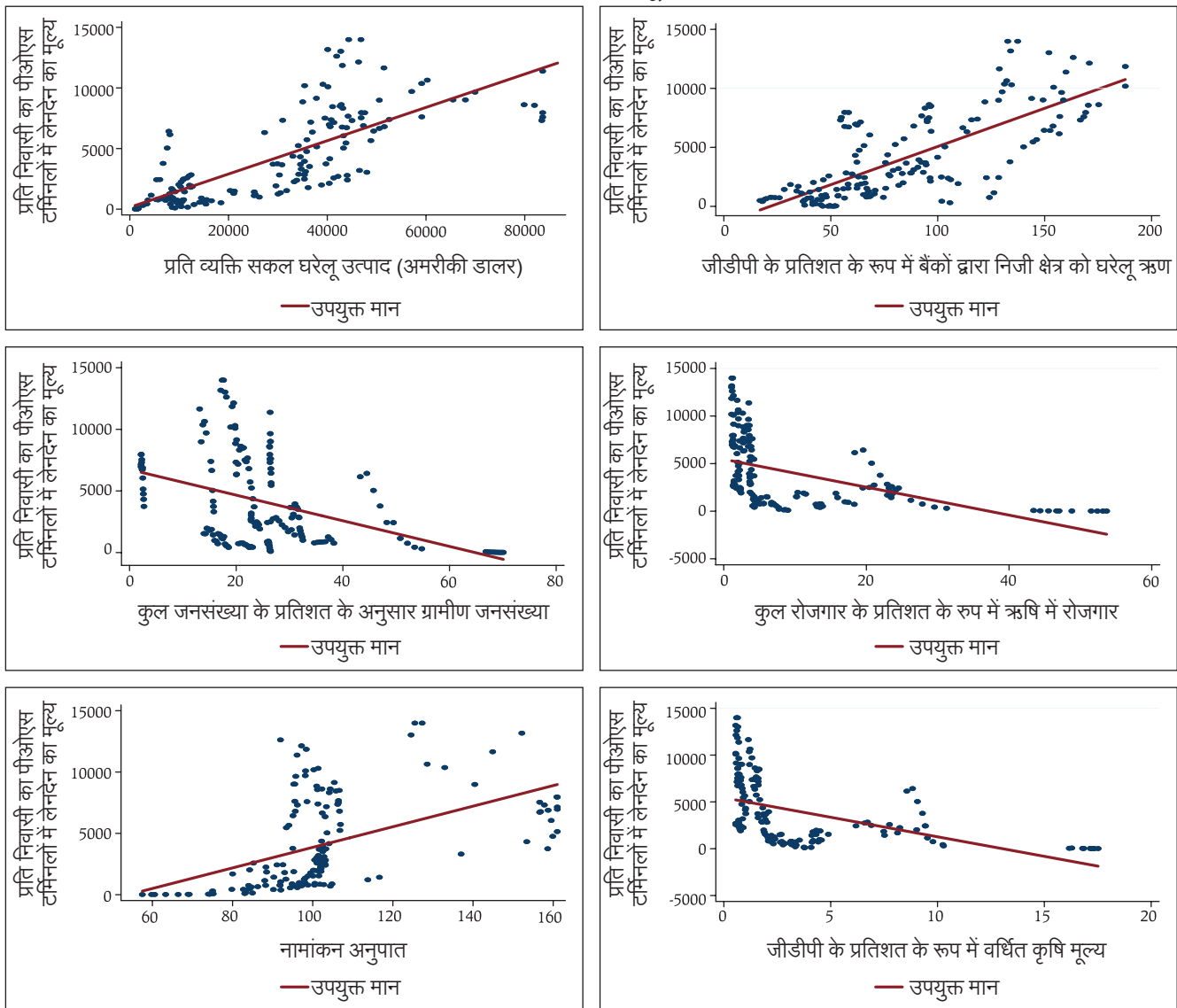
किसी देश की भुगतान प्रणाली के तकनीकी विकास की स्थिति भी नकदी प्रतिस्थापन प्रक्रिया की स्थिति को समझाने में मदद करती है। दस यूरोपीय देशों के लिए किए गए एक विश्लेषण से पता चला कि नकद और चेक के एवज में कार्ड से भुगतान का प्रतिस्थापन कार्ड भुगतान के बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण और पीओएस टर्मिनलों के विस्तार पर निर्भर करता है (स्नेलमैन एवं अन्य, 2001)।

V. डेटाबेस, कार्यप्रणाली और निष्कर्ष

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के विश्व विकास सूचकांक डेटाबेस से 8 ई और 8 ईएमई⁷ के वर्ष 2003-2016⁸ की अवधि के लिए पैनल डेटासेट का उपयोग करके, डिजिटल भुगतान और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के बीच संबंध का विश्लेषण किया गया। प्रति निवासी पीओएस पर लेनदेन के मूल्य/मात्रा का उपयोग डिजिटल भुगतान के लिए एक परोक्षी के रूप में किया गया था।

चार्ट के माध्यम से एक प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ-साथ डिजिटल भुगतान का मूल्य / मात्रा भी बढ़ता है, जो पहले के निष्कर्षों के अनुरूप है (हम्फ्री 2004)। आंकड़ों पर नज़र डालने से भी जीडीपी अनुपात की तुलना में ऋण और डिजिटल भुगतान के बीच एक सकारात्मक संबंध का पता चलता है। दूसरी ओर, ग्रामीण आबादी का अधिकांश हिस्सा कम डिजिटल भुगतान से जुड़ा हुआ है, जबकि नामांकन अनुपात- शिक्षा के स्तर के लिए एक परोक्षी- डिजिटल भुगतान के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ है (चार्ट 9 और 10)।

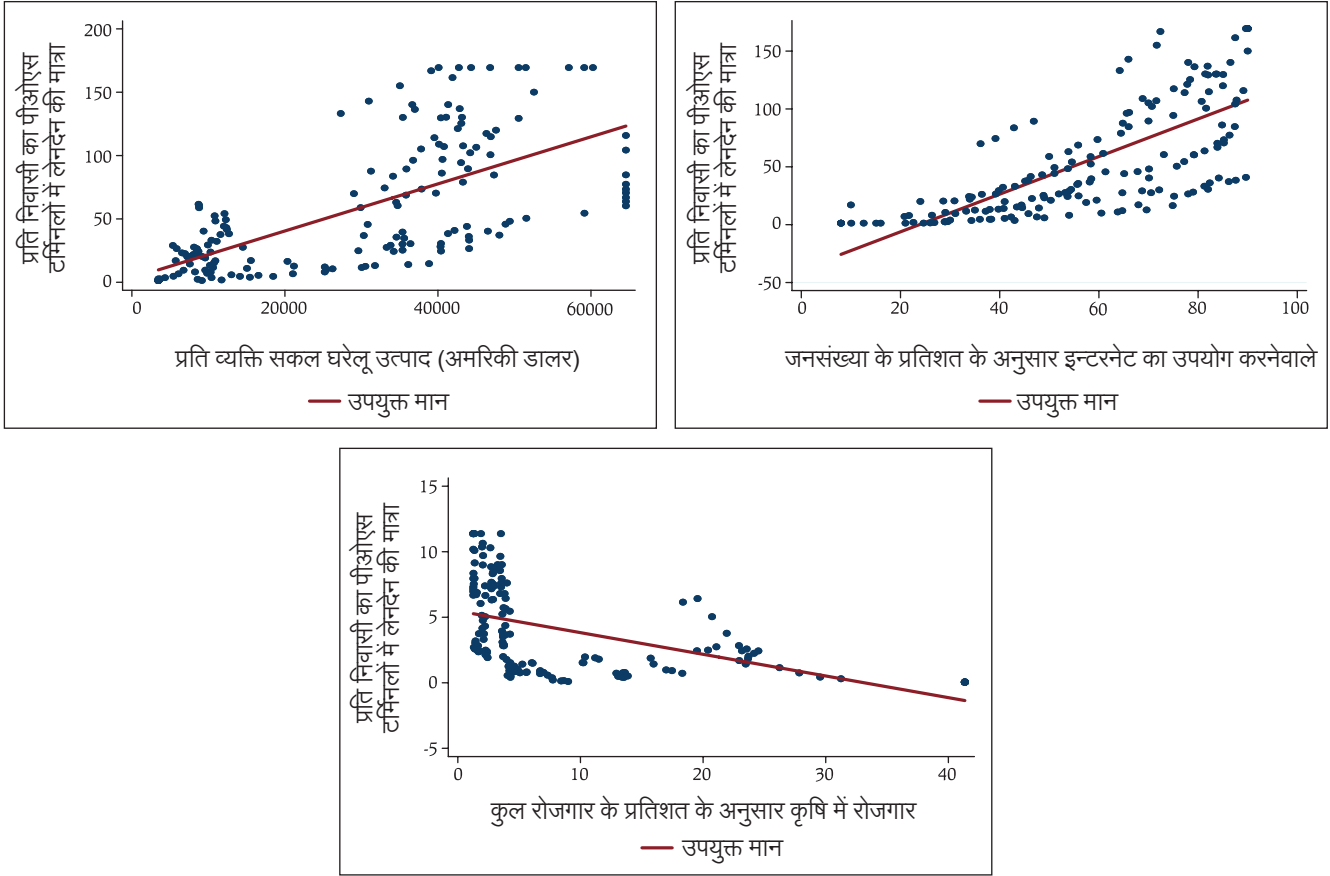
चार्ट 9: पीओएस पर प्रति निवासि लेनदेन का मूल्य और विभिन्न आर्थिक संकेतक



स्रोत : बीआईएस, विश्व बैंक और लेखक की गणना।

⁷ ई में बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। ईएमई में ब्राजील, चीन, भारत, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल हैं।

⁸ नवीनतम अवधि जिसके लिए पैनल में सभी देशों के लिए निरंतर डेटा श्रृंखला उपलब्ध है।

चार्ट 10: निवासियों और विभिन्न आर्थिक संकेतकों के अनुसार पीओएस में लेनदेन की मात्रा

स्रोत : बीआईएस, विश्व बैंक और लेखक की गणना

पीओएस टर्मिनलों की संख्या, पीओएस टर्मिनलों पर लेन-देन की मात्रा/मूल्य, एटीएम की संख्या (जिसे डिजिटल भुगतान में सहायक बुनियादी ढांचे के लिए एक परोक्षी के रूप में माना जाता है), प्रति व्यक्ति जीडीपी और सीपीआई मुद्रास्फीति के संबंध में अंतर-देशीय आंकड़े भुगतान और बाजार अवसंरचना से संबंधित बीआईएस सांख्यिकी से प्राप्त किए जाते हैं। निजी क्षेत्र को दिए गए घरेलू ऋण (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में), कृषि मूल्य (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में), इंटरनेट उपयोगकर्ता (कुल जनसंख्या के अनुपात के रूप में इंटरनेट का उपयोग करने वाले व्यक्ति), नामांकन अनुपात (कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में माध्यमिक विद्यालय में नामांकन), कृषि में रोजगार (कुल रोजगार के प्रतिशत के रूप में), और ग्रामीण जनसंख्या (कुल जनसंख्या का प्रतिशत के रूप में) से संबंधित आंकड़े विश्व बैंक के विश्व विकास सूचकांक से लिया जाता है।

डिजिटल भुगतान के अंतर - देशीय निर्धारकों का विश्लेषण एक निश्चित प्रभाव वाले पैनल रिग्रेशन

फ्रेमवर्क⁹ में विश्लेषण किया गया। पीओएस टर्मिनलों पर लेनदेन के मूल्य/मात्रा का उपयोग डिजिटल भुगतान के लिए एक परोक्षी के रूप में किया गया था। निम्नलिखित मौजूदा साहित्य, प्रति व्यक्ति जीडीपी, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी क्षेत्र को घरेलू ऋण, जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में इंटरनेट उपयोगकर्ता, नामांकन अनुपात, कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा, जीडीपी में कृषि मूल्य का हिस्सा, कृषि में संलग्न व्यक्तियों का हिस्सा, प्रति व्यक्ति एटीएम की संख्या और सीपीआई मुद्रास्फीति का उपयोग व्याख्यात्मक चर के रूप में किया गया था। आंकड़ों को उचित रूप से दोनों पक्षों पर 5 प्रतिशत के स्तर पर वर्गीकृत किया गया था। परिणाम परिशिष्ट सारणी 1 और सारणी 2 परिशिष्ट में प्रस्तुत किए गए हैं।

परिणाम से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा स्तर में वृद्धि (स्कूल नामांकन द्वारा अनुमानित) पीओएस टर्मिनलों

⁹ हाउसमैन परीक्षण के परिणामों ने यादृच्छिक-प्रभाव मॉडल के बदले निश्चित-प्रभाव मॉडल के चयन का सुझाव दिया।

पर मूल्य/लेन-देन की मात्रा में वृद्धि के निर्धारक हैं। आय और शिक्षा के स्तर के साथ सकारात्मक संबंध साहित्य में निष्कर्षों के अनुरूप है जो दर्शाता है कि आय और शिक्षा के स्तर में वृद्धि से नकदी का उपयोग कम हो जाता है और भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग की संभावना बढ़ जाती है। (डेविस एवं अन्य, 2016; बेच एवं अन्य, 2018; स्टेविंस, 2001)।

हमें पीओएस टर्मिनलों पर मूल्य और लेनदेन की मात्रा पर ग्रामीण आबादी के अनुपात का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को नहीं मिला। हालांकि, पीओएस टर्मिनलों पर लेनदेन में मात्रा के संबंध में यह पाया गया कि कृषि में रोजगार का इससे नकारात्मक संबंध है। इन्फ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल भुगतान की उपलब्धता के बीच संबंधों का मूल्यांकन करने के लिए हमने कुल आबादी के प्रतिशत के रूप में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और पीओएस लेनदेन की मूल्य के बीच संबंधों का भी पता लगाया, और दोनों के बीच एक सकारात्मक संबंध पाया गया। इसी प्रकार, यह पाया गया कि प्रति व्यक्ति पीओएस टर्मिनलों की संख्या, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एक और परोक्षी, भी डिजिटल लेनदेन के मूल्य के साथ सकारात्मक रूप से संबद्ध है।

यह भी पाया गया कि पीओएस टर्मिनलों पर लेनदेन के उच्चतर मूल्य/मात्रा को बढ़ाने में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी क्षेत्र को घरेलू ऋण सहायक होगा, जो वित्तीय विकास का एक संकेतक है।

एटीएम की संख्या डिजिटल लेनदेन के मूल्य/मात्रा के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ी हुई पाई गई क्योंकि अधिक संख्या में एटीएम वाले लोग कम नकदी अपने साथ रखते हैं। इसके अलावा, अधिकांश एटीएम कार्ड में डेबिट/क्रेडिट फीचर्स होते हैं, जिसके कारण पीओएस टर्मिनलों पर इसका उपयोग बढ़ जाता है।

यह भी पाया गया कि पीओएस पर डिजिटल लेनदेन की अधिक मात्रा का कारण कम सीपीआई मुद्रास्फीति थी, जिसकी वजह अनिश्चितता को कम करने में मूल्य स्थिरता का अनुकूल असर हो सकता है।

VI. निष्कर्ष

संक्षेप में, हमारे निष्कर्षों से पता चलता है कि उच्च प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का उच्च स्तर, जीडीपी के प्रतिशत के रूप

में निजी क्षेत्र को घरेलू ऋण में वृद्धि, अधिक से अधिक इंटरनेट विस्तार, और कम मुद्रास्फीति डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में मदद करती है। दूसरी ओर, कुल रोजगार में कृषि रोजगार का एक बड़ा हिस्सा और जीडीपी में कृषिगत मूल्य वर्धित का अधिकांश हिस्सा कम डिजिटल भुगतान के साथ जुड़ा पाया गया। विशिष्ट रूप से भारतीय संदर्भ में, भुगतान के डिजिटल मोड को अपनाने को बढ़ावा देने में डीबीटी की भूमिका के कारण, और वित्तीय समावेशन पर रिज़र्व बैंक के जोर की वजह से भी, कुल रोजगार में कृषि रोजगार की हिस्सेदारी से संबंधित पैलल डेटा परिणाम को नहीं पकड़ा जा सकता है। नीति के दृष्टिकोण से देखें तो, हमारे निष्कर्षों से पता चलता है कि डिजिटल भुगतान को जोरदार तरीके से बढ़ाने के लिए एक अनुकूल समष्टि-आर्थिक वातावरण और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु एक सुरक्षित और आसान पहुंच प्रदान करना महत्वपूर्ण है।

संदर्भ

- Bech, M. L., Faruqui, U., Ougaard, E., & Picillo, C. (2018). Payments are a-changin'but cash still rules. *BIS Quarterly Review, March*.
- Bergman, M., Guibourg, G., & Segendorf, B. L. (2007). The Costs of Paying - Private and Social Costs of Cash and Card Payments. *Riksbank Research paper series*, (212).
- Capgemini, B. N. P. Paribas (2018). *World Payments Report, 2018*, available at <https://worldpaymentsreport.com/wp-content/uploads/sites/5/2018/10/World-Payments-Report-2018.pdf>.
- Dembiermont, C. (2017): Recent Developments in Payment Systems, accessed at https://www.bis.org/ifc/events/ifc_isi_2017/13_dembiermont_paper.pdf.
- Davies, C., Doyle, M. A., Fisher, C., & Nightingale, S. (2016). The Future of Cash. *RBA Bulletin, December*, 43-52.
- Esselink, H., & Hernández, L. (2017). The Use of Cash by Households in the Euro Area. *ECB Occasional Paper*, (201).
- Goczek, L., & Witkowski, B. (2016). Determinants of Card Payments. *Applied Economics*, 48(16), 1530-1543.

- Hancock, D., & Humphrey, D. B. (1997). Payment Transactions, Instruments, and Systems: A survey. *Journal of Banking & Finance*, 21(11-12), 1573-1624.
- Humphrey, D. B. (2004). Replacement of Cash by Cards in US Consumer Payments. *Journal of Economics and Business*, 56(3), 211-225.
- Schmidt, T., & Bundesbank, D. (2016). Cash Payments More Popular in Germany than in other Countries. *Deutsche Bundesbank Research Brief*.
- Schneider, F. (2017). Restricting or Abolishing Cash: An Effective Instrument for Fighting the Shadow Economy, Crime and Terrorism?
- Shah, A., Kaushik, V., Roongta, P., Jain, C., & Awadhiya, A. (2016). Digital Payments 2020: The Making of a \$500 billion Ecosystem in India. *The Boston Consulting Group*.
- Snellman, J. S., Vesala, J. M., & Humphrey, D. B. (2001). Substitution of Noncash Payment Instruments for Cash in Europe. *Journal of Financial Services Research*, 19(2-3), 131-145.
- Stavins, J. (2001). Effect of Consumer Characteristics on the Use of Payment Instruments. *New England Economic Review*. February.

परिशिष्ट सारणी 1: आश्रित चर - प्रति निवासी पीओएस टर्मिनलों पर लेनदेन के मूल्य का लॉग

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रति व्यक्ति जीडीपी लॉग	0.782*** (0.172)				
नामांकन अनुपात	0.0049* (0.0018)		0.0039 (0.0020)	0.0024 (0.0043)	
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी क्षेत्र को घरेलू ऋण	0.0082* (0.0029)	0.0085* (0.0039)	0.0099* (0.0034)		
पीओएस टर्मिनलों की संख्या का लॉग	0.698*** (0.110)	0.834*** (0.0811)	0.726*** (0.144)	0.618*** (0.128)	
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कृषिगत मूल्य वर्धित		-0.156 (0.126)			
कुल आबादी के अनुपात की तुलना में इंटरनेट उपयोगकर्ता			0.007 (0.0038)	0.0093* (0.0038)	0.0115* (0.0043)
कुल रोजगार के प्रतिशत के रूप में कृषि में रोजगार				-0.0518* (0.0202)	
कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा					-0.0547 (0.0611)
प्रति निवासी एटीएम का लॉग					0.834** (0.241)
स्थिरांक	1.881 (1.881)	11.27*** (0.649)	9.299*** (0.903)	10.16*** (0.927)	14.58***
देश निश्चित प्रभाव	हां	हां	हां	हां	हां
एन	155	166	155	155	170
आर ² समग्र	0.913	0.872	0.887	0.847	0.623
कोष्ठक में पुष्ट मानक त्रुटियां * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$					

परिशिष्ट सारणी 1: आश्रित चर - प्रति निवासी पीओएस टर्मिनलों पर लेनदेन का लॉग

	(1)	(2)	(3)
प्रति व्यक्ति जीडीपी लॉग	0.508 (0.293)		
नामांकन अनुपात	0.0228* (0.0103)	0.0116* (0.0044)	0.0116 (0.0055)
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी क्षेत्र को घरेलू ऋण	0.0117* (0.0049)	0.0078* (0.0032)	
कुल रोजगार के प्रतिशत के रूप में कृषि में रोजगार	-0.103*** (0.0248)	-0.0773* (0.0297)	
कुल आबादी के प्रतिशत के रूप में इंटरनेट उपयोगकर्ता		0.0229** (0.0067)	0.0219** (0.0062)
सीपीआई मुद्रास्फीति		-0.0323** (0.0084)	
कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा			0.0460 (0.0953)
प्रति निवासी एटीएम का लॉग			0.837* (0.294)
स्थिरांक	-3.997* (1.804)	1.063 (0.833)	5.962** (1.816)
देश निश्चित प्रभाव	हां	हां	हां
एन	160	160	160
आर ² समग्र	0.735	0.766	0.448
कोष्ठक में पुष्ट मानक त्रुटियां * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$			

भारत में एनईएफटी लेनदेन का नेटवर्क विश्लेषण*

भारतीय परिप्रेक्ष्य में पहले प्रयास के रूप में, हम एनईएफटी प्रणाली के नेटवर्क टोपोलॉजी को परखते हैं और सेंट्रालिटी के नेटवर्क मेट्रिक्स का उपयोग करके वित्तीय अंतर्संबद्धता का विश्लेषण करते हैं। वर्ष 2019 के मार्च और अप्रैल माहों की प्रत्येक प्रतिभागी संस्था की जानकारी का उपयोग करते हुए, हम लिंकेज को दर्शाते हुए नेटवर्क ग्राफ का निर्माण करते हैं। हम पैटर्न की पहचान करने के उद्देश्य से बैंकों के विभिन्न समूहों के आपस के संबंध का पता लगाने के लिए इन डेटा का उपयोग करते हैं। हम गैर-पैरामेट्रिक पद्धति का उपयोग करके उनके प्रणालीगत महत्व के क्रम में पेमेन्ट नेटवर्क में प्रमुख प्रतिभागियों का पता लगाने का भी प्रयास करते हैं।

परिचय

वित्तीय स्थिरता के परिप्रेक्ष्य में, केंद्रीय बैंकों और विनियामकों ने ज्यादा से ज्यादा महसूस किया कि वित्तीय प्रणाली की बनावट में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में अंतर्निहित अंतर्संबद्धता को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तदनुसार, वित्तीय स्थिरता के पर्यवेक्षी और विनियामक ढांचे ने अंतर्संबद्धता को मापने एवं प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं को पहचानने के लिए उन्नत सैद्धांतिक तथा प्रयोगसिद्ध मॉडल के उपयोग के जरिए काफी सख्ती बरती है। 2008 के वैश्विक संकट के बाद से, नेटवर्क मॉडल अंतरबैंक वित्तीय एक्सपोजर के विश्लेषण के लिए एक उपकरण के रूप में उभरा है। तदनुसार हाल के साहित्य ने वित्तीय स्थिरता विश्लेषण (Caccioli *et al.*, 2018) के मौजूदा फ्रेमवर्क के पूरक के रूप में अंतरबैंक भुगतान लेनदेनों के नेटवर्क विश्लेषण की भूमिका पर जोर दिया है। जहां केंद्रीय बैंक भुगतान और निपटान इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऑपरेटर हैं, जैसा भारत में, वहां तुलनात्मक लाभ यह है कि स्वच्छ, संरचित और सटीक डेटा प्राप्त करना अपेक्षाकृत रूप से आसान होता है क्योंकि ये डेटा नेटवर्क विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अतः, आश्चर्यजनक बात यह

* यह आलेख भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के शशि कांत और शरत चंद्र ढल द्वारा तैयार किया गया है। हम भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के मनीष तरोगे की सहायता के लिए आभार प्रकट करते हैं। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

है कि भारत में भुगतान प्रणाली में भाग लेने वाली संस्थाओं की अंतर्संबद्धता के विषय में थोड़ा ही शोध हुआ है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पहले प्रयास के रूप में इस अंतर को पाटना इस अध्ययन की प्रेरणा है। हम केस स्टडी के रूप में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली का उपयोग करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा परिचालित, यह मात्रा के आधार पर भारत की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली है और खुदरा भुगतान के क्षेत्र में काया पलट करने वाली साबित हुई। हम एनईएफटी प्रणाली के नेटवर्क टोपोलॉजी को परखते हैं और सेंट्रालिटी के नेटवर्क मेट्रिक्स का उपयोग करके वित्तीय अंतर्संबद्धता का विश्लेषण करते हैं। वर्ष 2019 के मार्च और अप्रैल माहों की प्रत्येक प्रतिभागी संस्था की जानकारी का उपयोग करते हुए, हम लिंकेज को दर्शाते हुए नेटवर्क ग्राफ का निर्माण करते हैं। हम पैटर्न की पहचान करने के उद्देश्य से बैंकों के विभिन्न समूहों के आपस के संबंध का पता लगाने के लिए इन डेटा का उपयोग करते हैं। हम गैर-पैरामेट्रिक पद्धति का उपयोग करके उनके प्रणालीगत महत्व के क्रम में पेमेन्ट नेटवर्क में प्रमुख प्रतिभागियों का पता लगाने का भी प्रयास करते हैं (Jaramillio *et al.*, 2014)।

संक्षेप में, हमारे निष्कर्ष से पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों, जिसका एनईएफटी में कुल लेनदेन मूल्य मार्च और अप्रैल माह में क्रमशः लगभग 83 प्रतिशत और 87 प्रतिशत हिस्सा है, में से निजी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अत्यधिक प्रवाह हो रहे हैं जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रणाली में शुद्ध प्राप्तकर्ता रहे। हम जनता और सरकारी क्षेत्र के बीच तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच मजबूत संबंधों के साक्ष्य, एनईएफटी में सहकारी बैंकों की नयी भूमिका और नव स्थापित भुगतान बैंकों की भूमिका भी प्रस्तुत करते हैं। आलेख के बाकी हिस्सों को पांच खंडों में विभाजित किया गया है। खंड II में एनईएफटी प्रणाली के संक्षिप्त परिचय के बाद, खंड III में वित्तीय अर्थशास्त्र में नेटवर्क विज्ञान के प्रयोग के साहित्य की समीक्षा की गई है। खंड IV में कार्यपद्धति एवं डेटा निर्धारित किए गए हैं। खंड V में शीर्ष के 20 प्रभावशाली बैंकों के प्रयोगसिद्ध परिणाम व रैंकिंग दिए गए हैं। नीति को लेकर कुछ नजरिया पेश करने के साथ ही खंड VI को समाप्त किया गया है।

II. एनईएफटी प्रणाली पर प्रारंभिक कार्य

एनईएफटी की नींव देश की पहली भुगतान प्रणाली के तौर पर 1990 के दशक के अंत में प्रारंभ भूतपूर्व इलेक्ट्रॉनिक

निधि अंतरण (ईएफटी) से पड़ी थी, जिसकी बदौलत प्रत्येक को अलग-अलग निधि अंतरण किया जा सका। यह देश के 15 प्रमुख केंद्रों पर परिचालित था। 2005 में, इसे एक समृद्ध और अधिक कुशल प्रणाली अर्थात् एनईएफटी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों- सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंक सहित 210 से अधिक संस्था एनईएफटी प्रणाली में सम्मिलित हैं, लेन-देन की मात्रा के संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा संचालित यह सबसे बड़ी प्रणाली है। यह एक देशव्यापी भुगतान प्रणाली है जो लेनदेन राशि पर किसी भी सीमा के बिना प्रत्येक को अलग-अलग धन अंतरण की सुविधा प्रदान करती है, हालांकि इसका उपयोग आमतौर पर ₹2 लाख तक के खुदरा भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रणाली में, सभी बैंक कार्य दिवसों पर सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक आधे-आधे घंटे के बैच में निधि अंतरण होता है। एनईएफटी ऑपरेशनल प्लो को चार्ट 1 में दर्शाया गया है। लाभार्थी लेन-देन का निपटान किए गए बैच से दो करोबारी घंटों के भीतर राशि प्राप्त करने का हकदार है। यदि एनईएफटी लेनदेन को निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा या वापस नहीं किया जाता है, तो विलंब की अवधि के लिए/वापसी की तारीख तक जैसा कि मामला हो प्रभावित ग्राहकों को बैंक वर्तमान रिजर्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) रेपो परिकल्पित दर पर तथा इसके अतिरिक्त 2

प्रतिशत दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ने लेन देन लागत कम करने और डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए एनईएफटी प्रोसेसिंग प्रभार माफ कर दिए हैं।

III. साहित्य

भौतिकी में अपनी उत्पत्ति के कारण नेटवर्क सिद्धांत का अर्थशास्त्र और वित्त के क्षेत्रों की एक विस्तृत शृंखला: सामाजिक नेटवर्क (ग्रैंडजीन, 2016; डंबर एट अल., 2015), अंतरराष्ट्रीय व्यापार (एमए और मोनड्डोन, 2015; काली और रेयेस, 2007), विदेशी निवेश प्रवाह और क्रॉस कंट्री ऋण होल्डिंग्स (इलियट एट अल., 2014) और इंटरबैंक एक्सपोजर (अपर एण्ड वर्मस, 2004; लैंगफील्ड एट अल., 2014; कोंट एट अल., 2010; लोरी एट अल., 2005) में अनुप्रयोग देखा गया है।

वित्तीय लेनदेन के डिजिटल चैनलों में धड़केदार वृद्धि और जटिलता में सहवर्ती वृद्धि के साथ, भुगतान प्रणाली ने विद्वानों और व्यावसायिकों का ध्यान आकर्षित किया है। भुगतान प्रणालियों की ओर बढ़ते ध्यान को अपेक्षाकृत रूप से सुलभता से डेटा का एक्सेस करने से भी बल मिलता है क्योंकि केंद्रीय बैंकों के पास भुगतान प्रणालियों के डेटा सहज रूप से उपलब्ध हैं। अमेरिका में फेडरल रिजर्व द्वारा संचालित फेडवायर फंड सेवा के माध्यम से अंतरबैंक भुगतान प्रवाह के नेटवर्क टोपोलॉजी का

चार्ट 1: एनईएफटी प्रक्रिया



अध्ययन इस साहित्य के लिए एक मौलिक जोड़ है। अध्ययनों से पता चला है कि फेडवायर भुगतान नेटवर्क का सही परिणाम एक बिजली कानून वितरण¹ (सोरमाकी एट अल, 2006; प्रॉपर एट अल., 2008; एम्ब्री और रॉबर्ट्स, 2009) का अनुसरण करता है। इसी तरह का अध्ययन ब्रिटेन में बेचर एट अल(2008) द्वारा संचालित क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम (चैप्स) के लिए किया गया था। उन्होंने दिन के विशेष समय में विभिन्न प्रतिभागियों की निपटान असफलताओं के कारण कमजोरियों का आकलन करने के लिए एक दिन के दौरान नेटवर्क विशिष्टता के फेरबदल को देखा। बैंक ऑफ जापान फाइनेंशियल नेटवर्क सिस्टम (बौओजे-नेट) से निपटान डेटा की जांच की गई ताकि इमाकुबो और सोजिमा (2010) द्वारा इंटरबैंक मुद्रा बाजार में लेनदेन की संरचना का अध्ययन किया जा सके। मेक्सिको में इंटरबैंक एक्सचेंज और भुगतान प्रणाली नेटवर्क का अध्ययन किया गया था और प्रणालीगत जोखिम परिप्रेक्ष्य से परस्पर जुड़ाव का एक उपाय जारामिलो एट अल(2014) द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस प्रकार, इन अध्ययनों में एक आम धागा प्रत्यक्ष नेटवर्क लेआउट में पैटर्न की खोज और समूहों की पहचान करने के बारे में है जिसका पारंपरिक अर्थशास्त्र का उपयोग करते हुए पता लगाना मुश्किल है।

भुगतान प्रणाली अन्य जटिल नेटवर्क के समान होती हैं क्योंकि वे उच्च क्लस्टरिंग गुणांक, स्केल-फ्री डिग्री वितरण और स्मॉल वर्ल्ड फेनोमेनन² (सोरमाकी एट अल, 2006) जैसी समान विशेषताओं को साझा करते हैं। नेटवर्क विश्लेषण का दायरा नेटवर्क लेआउट में पैटर्न की खोज से अधिक फैला हुआ है जिसके भविष्य के अध्ययनों में जांच की जा सकती है। नेटवर्क विश्लेषण भी एक नेटवर्क के मुख्य घटकों का पता लगा सकता है जो प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्थाओं की पहचान करने में बहुत

¹ नेटवर्क ग्राफ तब स्केल फ्री कहे जाते हैं जब उनका मात्रात्मक वितरण (डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन) एक पावर लॉ पर चलता है; एक संभावना वितरण जो वितरण में दो मूल्यों के अनुपात के लिए मान परिवर्तनहीनता (स्केल इनवैरिएंस) दर्शाता है। यह कई मानव निर्मित और प्राकृतिक प्रणालियों में देखा गया है जैसे फोन कॉल नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब, एक्टर कॉलेबोरेशन नेटवर्क आदि में। 2 के पावर लॉ घातांक (एक्सपोनेंट) वाले नेटवर्क का अर्थ हुआ कि डिग्री 6 का एक नोड डिग्री 3 के नोड की तुलना में चार गुना कम आवृत्ति वाला है। डिग्री 10 का एक नोड डिग्री 5 के नोड की तुलना में चार गुना कम आवृत्ति वाला है (चैपमैन, 2011)।

² क्लस्टरिंग गुणांक यह मापता है कि किस हद तक किसी ग्राफ में नोड क्लस्टर बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। छोटी दुनिया की घटना (स्मॉल वर्ल्ड फेनामिना) का सिद्धांत कहता है कि एक नेटवर्क के सभी नोड्स छोटे लिंक्स, यानी, छोटे पाथ लेंथ्स द्वारा किसी भी नोड से पाए (एक्सेस किए) जा सकते हैं।

महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, इंटरबैंक नेटवर्क कोर-परिधि संरचना (बोर्गटी एट अल, 1999)³ का प्रतिरूप है। वित्तीय नेटवर्क में संक्रमण का अध्ययन करने के लिए यादृच्छिक रेखांकन के साथ नेटवर्क सिमुलेशन नियोजित किया है। नेटवर्क में परिवर्तन के साथ विशेष स्वरूप और प्रणालीगत आघात के कारण संक्रमण के संभावित प्रभाव का पता गाई और कपाड़िया (2010) द्वारा लगाया गया था। संक्रमण पर कनेक्टिविटी की डिग्री के प्रभाव की जांच की गई और यह पाया गया कि कनेक्टिविटी में थोड़ी सी वृद्धि शुरू में संक्रमण प्रभाव को बढ़ाती है; लेकिन एक निश्चित सीमा मूल्य के बाद, कनेक्टिविटी आघात (नियर एट अल., 2007) को अवशोषित करने के लिए बैंकिंग प्रणाली की क्षमता में सुधार करती है। आघात की गंभीरता के संबंध में संक्रमण प्रभाव की जांच की गई और निष्कर्ष निकाला गया कि घने नेटवर्क छोटे नकारात्मक आघातों के लिए शॉक डिफ्यूज़र के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन पर्याप्त रूप से बड़े आघातों (एसीमोग्लू एट अल, 2015) के लिए शॉक एम्पलीफायरों में बदल जाते हैं।

IV. कार्यप्रणाली और डेटा

भुगतान प्रणाली को समझने के लिए नेटवर्क दृष्टिकोण पारंपरिक आर्थिक मॉडलिंग से अलग है। नेटवर्क विश्लेषण की उपयोगिता पर एक सार्थक चर्चा के लिए, हम नेटवर्क विश्लेषण का गैर तकनीकी विवरण प्रदान करते हैं। नेटवर्क विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण घटक नेटवर्क की कल्पना करना है। भुगतान नेटवर्क में नोड्स का एक सेट होता है, जहां प्रत्येक नोड एक प्रतिभागी इकाई यानी लघु वित्त बैंक, आरआरबी और लघु वित्त बैंक (एसएफबी) आदि को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) का प्रतिनिधित्व करता है। नेटवर्क एड्ज लेनदेन की मात्रा या लेनदेन मूल्य के आधार पर दो पक्षकारों के बीच द्विपक्षीय संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। नेटवर्क एड्ज का निर्देशन किया जाता है और एक संस्था से दूसरे संस्था में धन प्रवाह की दिशा को प्रतिबिंबित किया जाता है। इसका घनत्व भुगतान की मात्रा और मूल्य (बैरात एट अल, 2004) के संदर्भ में संबद्ध लिंकेज भार के आनुपातिक है। हमने कामदा-कवाई एल्गोरिदम का उपयोग किया है जो एक तरह से 3डी अंतरिक्ष में नेटवर्क के नोड्स को

³ मूलभूत (कोर)-परिधि (पेरिफेरी) संरचना दो समूहों से बनती है: मूलभूत (कोर) और परिधि (पेरिफेरी)। कोर और पेरिफेरल नोडों में अंतर इस प्रकार किया जाता है: कोर पूरे नेटवर्क का एक सबग्राफ है जिसमें नोड्स सघनता से एक दूसरे से जुड़े हैं। पेरिफेरल नोड्स कोर नोड्स से तो जुड़े होते हैं परंतु दूसरे पेरिफेरल नोड्स से नहीं।

प्लॉट करता है ताकि सिस्टम (कामदा और कवाई, 1989) की स्प्रिंग एनर्जी को कम किया जा सके। एक स्पष्ट चित्र प्राप्त करने के लिए, भुगतान प्रवाह के व्यापक पैटर्न का आकलन करने के लिए हम समूह वार नेटवर्क भी तैयार करते हैं।

महत्वपूर्ण नोड्स की पहचान नेटवर्क विश्लेषण का और एक घटक है। नेटवर्क मॉडल इस उद्देश्य के लिए विभिन्न सेंट्रालिटी उपायों का उपयोग करते हैं। संक्षेप में, यह एक ऐसा कार्य है जो दूसरों पर इसके प्रभाव के अनुसार नेटवर्क के प्रत्येक वर्टेक्स को संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर, स्थानीय सेंट्रालिटी उपाय केवल नोड्स और उसके आसन्न वर्टेक्स और एडज को ध्यान में रखते हैं। ये उपाय एक समय में केवल एक नोड पर विचार करते हैं; जिससे शेष नेटवर्क में निहित महत्वपूर्ण जानकारी लुप्त हो जाती है। डिग्री सेंट्रालिटी (डीसी) प्रत्येक वर्टेक्स 5 के निकट नोड्स की संख्या गिनता है। नोड अधिक महत्वपूर्ण है अगर यह एक उच्च डिग्री है। इन-डिग्री सेंट्रालिटी और आउट-डिग्री सेंट्रालिटी क्रमशः इनकमींग और आउट गोईंग एडज को ध्यान में रखता है। स्ट्रेंथ सेंट्रालिटी प्रत्येक वर्टेक्स के सभी नजदीकी एडज के एडज भार को समेटता है। हम इनवर्ड और आउटवर्ड लेनदेन को अलग-अलग करते हैं क्योंकि भुगतान नेटवर्क संचालित ग्राफ है। विशेष रूप से, हमारी डिग्री और स्ट्रेंथ सेंट्रालिटी उपाय आउटवर्ड मूल्य लेनदेन पर आधारित हैं क्योंकि वे भुगतान दायित्वों के निपटान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भुगतान प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है।

एक नोड उच्च डिग्री हो सकता है लेकिन इसके कनेक्शन नेटवर्क के नजरिए से महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में, डिग्री उपायों से नोड के महत्व के बारे में गलत व्याख्याएं हो सकती हैं। वैश्विक सेंट्रालिटी उपाय पूरे नेटवर्क में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कनेक्शन पर विचार करते हैं और इसलिए, नेटवर्क के पूरे पैटर्न पर जानकारी देते हैं। इस ढांचे के भीतर, एजेन वेक्टर सेंट्रालिटी (ईसी) एक नोड कितनी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और उनके कनेक्शन के कितने लिंक हैं, इस पर नेटवर्क के माध्यम से विचार करता है। दूसरी ओर, पेजरैंक सेंट्रालिटी

⁴ नेटवर्क नोड्स को ऐसी भौतिक वस्तुओं के रूप में देखा गया है जो एक दूसरे को विकर्षित करती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन। नोडों के बीच के कनेक्शन नोडों की जोड़ी से जुड़े धातु के स्प्रिंग की तरह हैं। ये स्प्रिंग एक बल प्रकार्य (फोर्स फंक्शन) के अनुसार अपने अंतिम बिंदुओं (एंड प्वाइंट्स) को आकर्षित करते हैं। लेआउट अलगोरिथ्म नोडों की स्थिति को इस प्रकार सेट करता है जिससे नेटवर्क में स्प्रिंग एनर्जी कम से कम लगे (साइटोस्केप यूजर मैनुअल)।

⁵ नेटवर्क की शब्दावली में नोड और वर्टेक्स एक ही हैं।

(पीआर) गूगल द्वारा वेबपेज (ब्रिन और पेज, 1998) को रैंक करने के लिए डिज़ाइन किया गया ईसी का एक अधिक परिष्कृत संस्करण है। प्रत्येक वेबपेज को आने वाले लिंक (इसकी 'इन-डिग्री') की संख्या के आधार पर एक स्कोर दिया जाता है।⁵ ये लिंक भी अपने उद्भव नोड के सापेक्ष स्कोर के आधार पर भारित हैं। इस प्रकार, पीआर खाते में लिंक दिशा और भार लेता है जो ईसी नहीं करता है (डिज्नी, 2015)। बिटवीननेस सेंट्रालिटी भुगतान नेटवर्क के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नेटवर्क पर कार्यनीति बिंदुओं पर स्थित होने से संबंधित है जो दो अन्य नोड्स को जोड़ने वाले सबसे छोटे मार्ग में स्थित है। अनुलग्नक में हमारे विश्लेषण के मूल सेंट्रालिटी उपायों का संक्षिप्त गणितीय विवरण प्रदान किया गया है।

कई अन्य सेंट्रालिटी उपाय हैं जिनका उपयोग नेटवर्क के सबसे प्रभावशाली नोड्स को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इस बात पर कोई आम सहमति नहीं है कि कौन सा सबसे अच्छा है। हम इन सेंट्रालिटी उपायों का उपयोग करते हैं जो वित्तीय संक्रमण के नजरिए से महत्वपूर्ण हैं और गणना के लिए कम गहन हैं। इसके बाद, हम सेंट्रालिटी का एक सूचकांक बनाकर नोड्स को रैंक करने के लिए जारामिलो एट अल, (2014) द्वारा प्रस्तावित पद्धति का पालन करते हैं। हम सेंट्रालिटी उपायों के जेड-स्कोर के रैखिक संयोजन के साथ एक सूचकांक बनाने के लिए प्रमुख घटक विश्लेषण (पीसीए) दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं क्योंकि सभी उपायों का सहसंबद्ध होना अपेक्षित है। पीसीए डेटा की आयामीता और अतिरेक को कम करने में सहायता करता है। यह एक्सेस को फिर से नई दिशा देता है और उन निर्देशों के साथ डेटा प्रस्तुत करके डेटासेट को बदल देता है जिसमें डेटासेट अधिकतम परिवर्तन दिखाता है। यह इन उपायों में से प्रत्येक के लिए इष्टतम भार प्रदान करता है जिसका उपयोग अंतिम सेंट्रालिटी स्कोर पर पहुंचने के लिए किया जाता है जिसमें इन पांच स्कोर में निहित सभी जानकारी शामिल है।

साक्ष्य से पता चलता है कि दैनिक नेटवर्क मासिक नेटवर्क की तुलना में बहुत मुखर और विरल हो सकता है और वे एक विशुद्ध रूप से यादृच्छिक तरीके से दिन-प्रतिदिन अपनी संरचना को बदलने के लिए दिखाई देते हैं (कैसिओली एट अल, 2018)। इसलिए, हमने मार्च 2019 की अवधि में एक महीने का कुल इंटरबैंक डेटा लिया है। इस महीने का चयन इसलिए किया गया है कि देश में वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कारण इस महीने में बहुत

सारी वित्तीय गतिविधियां होती है। हमने तुलनात्मक संभावना के लिए अप्रैल 2019 का डेटा भी एकत्र किया। डेटा में 210 संस्थाओं के इंटरबैंक भुगतान लेनदेन की मात्रा और मूल्य शामिल है जिन्हें आठ समूहों में वर्गीकृत किया गया है; सहकारी बैंक (सीओओपी), वित्तीय संस्थान (फिन), विदेशी बैंक (एफआरएन), भुगतान बैंक (पीएमटी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीयूबी), निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीटी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और लघु वित्त बैंक (एसएफबी)। फिन ग्रुप में डिपॉजिट इश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी), नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड), स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी), एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (एकिजम बैंक) और रिजर्व बैंक, लोक लेखा विभाग (पीएडी) का समावेश है।

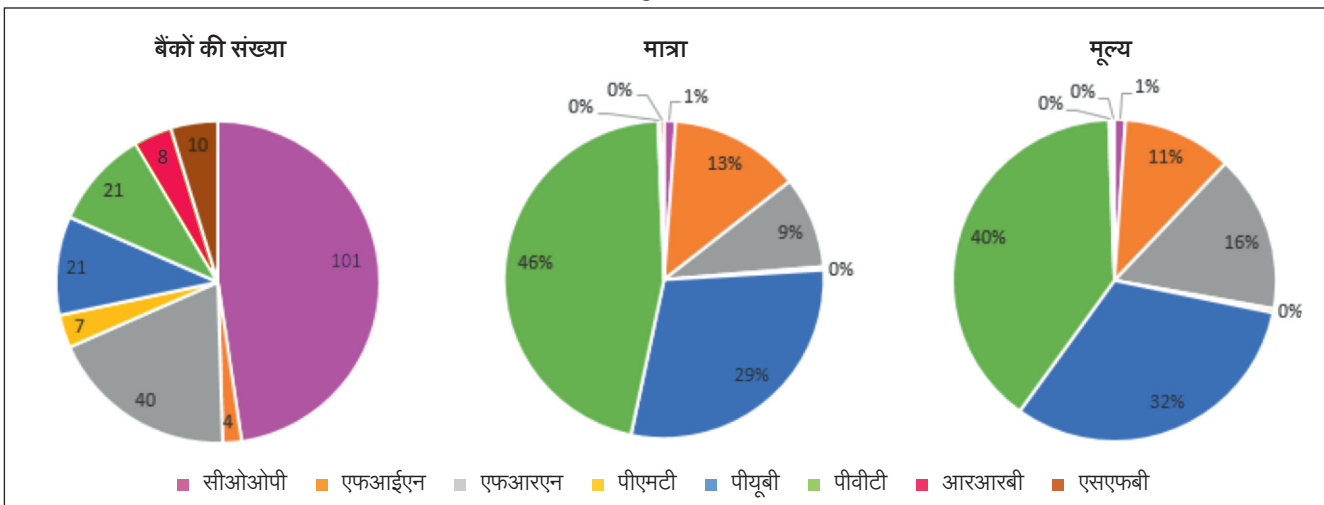
V. अनुभवजन्य परिणाम

हम तीन भागों में अनुभवजन्य विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। पहला भाग शैलीबद्ध तथ्य प्रस्तुत करता है। दूसरा भाग नेटवर्क टोपोलॉजी और विशेषताओं का वर्णन करता है और संस्थानों के बीच अंतर-संपर्कों के प्रत्यक्ष पैटर्न या लेआउट के साथ नेटवर्क विजुअलाइजेशन प्रस्तुत करता है। अंत में, हम उनके प्रणालीगत महत्व के आधार पर संस्थानों की रैंकिंग प्रस्तुत करते हैं।

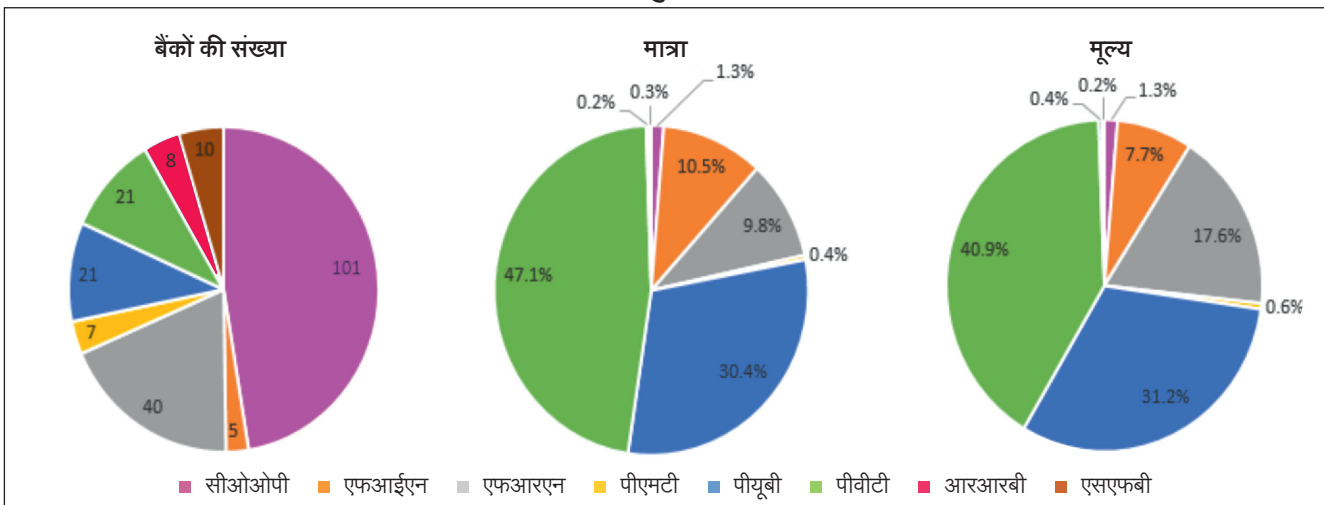
एनईएफटी प्रणाली: शैलीगत तथ्य

एनईएफटी प्रतिभागियों का एक स्नैपशॉट और उनकी ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी चार्ट 2 और सारणी 1 में दी गई है। जबकि सहकारी बैंक सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों से अधिक संख्या में हैं, मात्रा और मूल्य के मामले में भुगतान

चार्ट 2ए: मार्च 2019 में भुगतान आवागमन के संघटक



चार्ट 2बी: अप्रैल 2019 में भुगतान आवागमन के संघटक



**सारणी 1ए: मात्रा के अनुसार मुद्रा प्रवाह के आंकड़े –
मार्च 2019 (प्रतिशत में)**

		लाभार्थी								
मात्रा		सीओओपी	एफआईएन	एफआरएन	पीएमटी	पीयूबी	पीवीटी	आरआरबी	एसएफबी	कुल
आदाता	सीओओपी	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	0.0	0.0	1.2
	एफआईएन	0.1	0.0	0.0	0.0	12.2	0.6	0.2	0.0	13.2
	एफआरएन	0.2	0.0	0.4	0.1	4.1	4.4	0.0	0.0	9.3
	पीएमटी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.4
	पीयूबी	0.6	0.4	0.6	0.0	19.1	8.2	0.2	0.0	29.3
	पीवीटी	1.2	0.1	1.5	0.1	30.3	12.4	0.3	0.1	46.1
	आरआरबी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2
	एसएफबी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.4
	कुल	2.3	0.6	2.6	0.2	67.0	26.2	0.8	0.2	100.0

**सारणी 2 ए: मूल्य के अनुसार मुद्रा प्रवाह के आंकड़े –
मार्च 2019 (प्रतिशत में)**

		लाभार्थी								
मात्रा		सीओओपी	एफआईएन	एफआरएन	पीएमटी	पीयूबी	पीवीटी	आरआरबी	एसएफबी	कुल
आदाता	सीओओपी	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	1.1
	एफआईएन	0.0	0.4	0.4	0.0	7.2	2.8	0.0	0.0	10.9
	एफआरएन	0.1	0.1	4.9	0.3	3.3	7.1	0.0	0.0	15.8
	पीएमटी	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4
	पीयूबी	0.5	0.9	2.1	0.0	15.4	12.6	0.1	0.1	31.7
	पीवीटी	0.7	0.4	5.1	0.1	16.7	16.2	0.1	0.2	39.5
	आरआरबी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.3
	एसएफबी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3
	कुल	1.5	1.9	12.9	0.4	43.5	39.4	0.3	0.3	100.0

आवागमन में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा निजी क्षेत्र के बैंक मात्रा और मूल्य दोनों लिहाज से एनईएफटी नेटवर्क में सबसे बड़े प्रतिभागी हैं।

अधिकांश लेनदेन हिस्सा (कुल भुगतान मात्रा और मूल्य का 80 प्रतिशत से अधिक) सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों (टेबल 1 और 2) के बीच होता है। मासिक मूल्य के समुचित अंशों के आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नेटवर्क में शुद्ध रिस्वीवर हैं, जिनमें दोनों महीनों में 40 प्रतिशत से अधिक इनफ्लो है, जो लगभग 31 प्रतिशत आउटफ्लो से अधिक है। मुख्य घटक के रूप में रिजर्व बैंक के साथ फिन समूह नेटवर्क में नेट ट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है। मार्च और अप्रैल 2019

**सारणी 1 बी: मात्रा के अनुसार मुद्रा प्रवाह के आंकड़े –
अप्रैल 2019 (प्रतिशत में)**

		लाभार्थी								
मात्रा		सीओओपी	एफआईएन	एफआरएन	पीएमटी	पीयूबी	पीवीटी	आरआरबी	एसएफबी	कुल
आदाता	सीओओपी	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	0.0	0.0	1.3
	एफआईएन	0.2	0.0	0.0	0.0	9.7	0.4	0.1	0.0	10.5
	एफआरएन	0.2	0.0	0.4	0.1	4.2	4.8	0.0	0.0	9.8
	पीएमटी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.4
	पीयूबी	0.6	0.4	0.7	0.1	19.6	8.8	0.2	0.1	30.4
	पीवीटी	1.2	0.2	1.7	0.1	30.4	13.0	0.4	0.1	47.1
	आरआरबी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2
	एसएफबी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.3
	कुल	2.4	0.7	2.9	0.3	65.2	27.6	0.8	0.2	100.0

**सारणी 2 बी: मूल्य के अनुसार मुद्रा प्रवाह के आंकड़े –
अप्रैल 2019 (प्रतिशत में)**

		लाभार्थी								
मात्रा		सीओओपी	एफआईएन	एफआरएन	पीएमटी	पीयूबी	पीवीटी	आरआरबी	एसएफबी	कुल
आदाता	सीओओपी	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	1.3
	एफआईएन	0.1	0.0	0.2	0.0	6.8	0.7	0.0	0.0	7.7
	एफआरएन	0.1	0.2	5.5	0.3	3.5	8.0	0.0	0.0	17.6
	पीएमटी	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.6
	पीयूबी	0.5	0.4	2.3	0.0	14.6	13.4	0.1	0.1	31.2
	पीवीटी	0.7	0.4	6.3	0.2	16.4	16.6	0.1	0.1	40.9
	आरआरबी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.4
	एसएफबी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2
	कुल	1.5	1.0	14.8	0.5	42.2	39.6	0.2	0.2	100.0

में इसका आउटवर्डफ्लो क्रमशः 10.9 प्रतिशत और 7.7 प्रतिशत था, जो कि इनफ्लो के विपरीत था और मार्च और अप्रैल में 1 से 2 प्रतिशत के बीच रहा। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि ये निष्कर्ष मासिक कुल राशियों पर आधारित हैं और नेट रिस्वीवर और ट्रांसमीटर पैटर्न हर बैच सेटलमेंट में भिन्न हो सकता है।

नेटवर्क टोपोलॉजी

एनईएफटी नेटवर्क एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें मार्च और अप्रैल 2019 में लगभग 210 नोड्स और 23 हजार एड्जेस शामिल हैं। बैंकों की सभी श्रेणियों में औसत इन और आउट डिग्री 109 है। इससे संकेत मिलता है कि औसतन हर बैंक नेटवर्क में आधे से ज्यादा बैंकों से जुड़ा होता है। भुगतान नेटवर्क

में उच्च नेटवर्क घनत्व है, यानी एड्जेस की वास्तविक संख्या का अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक एड्जेस (कनेक्टिविटी) की अधिकतम संभव संख्या तक है। पारस्परिकता, एक नेटवर्क में लिंक की कुल संख्या के लिए द्विदिशात्मक लिंक के अनुपात के रूप में परिभाषित है जो 87.6 प्रतिशत है, जिससे संकेत मिलता है कि लगभग एक बैंक से हर आउटवर्ड लिंक के लिए, एक इनवर्ड लिंक है। एक उच्च पारस्परिकता एनईएफटी की समाशोधन संरचना को देखते हुए एक सहज घटना है जो प्रतिभागियों को सीधे एक और एनईएफटी सक्षम बैंक से लिंक करने की अनुमति देती है। एक आदर्श परिदृश्य में जहां प्रत्येक बैंक के नेटवर्क में हर दूसरे बैंक के साथ लेन-देन होता है, पारस्परिकता 100 प्रतिशत के बराबर होगी। हालांकि, लेनदेन के आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ बैंकों ने नेटवर्क में कुछ बैंकों के साथ लेनदेन नहीं किया जिससे पारस्परिकता एकता कम हो गई। मूल नेटवर्क स्वरूप को सारणी 3 में संक्षेप में शामिल किया गया है।

नेटवर्क विशेषताएं

नेटवर्क विजुअलाइजेशन भुगतान नेटवर्क के व्यापक पैटर्न का आकलन करने में सहायता करता है। नेटवर्क के डिग्री वितरण से पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंक वितरण के चरम सीमा पर हैं, जिसका अर्थ अन्य प्रतिभागियों (चार्ट 3) के साथ उच्च जुड़ाव है।

चार्ट 4, मार्च 2019 में नेटवर्क अप्रैल 2019 की तुलना में घना प्रतीत होता है जो सारणी 3 में दर्शाए गए अनुसार उच्च नेटवर्क घनत्व से सुसंगत है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक नेटवर्क के केंद्र में हैं। सार्वजनिक क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र से निजी क्षेत्र; और निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र के बीच उच्च अंतरण मूल्य और इसके विपरीत जैसा कि सारणी 2 में

सारणी 3: एनईएफटी नेटवर्क का स्वरूप

	मार्च 2019	अप्रैल 2019
नोड	212	213
एजेस	23.1	23.0
टोटल वॉल्यूम (मिलियन)	242.4	203.4
मिन वॉल्यूम पर नोड	1.1	1.0
टोटल वॉल्यूम (₹बिलियन)	25.5	20.5
मिन वॉल्यूम पर नोड (₹बिलियन)	120.1	96.5
डिग्री (मेक्स, एवरेज,मिन)	(417,217.8.2)	(417,216.2.2)
आउट	(208,108.9.0)	(208,108.1.0)
इन	(210,108.9.0)	(209,108.1.1)
रेसिप्रोसिटी (परसेंट)	87.6	87.5
नेटवर्क डेंसिटी	51.6	51.0

दर्शाया गया है चार्ट 4 में आरेखीय रूप से प्रस्तुत किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के भीतर मजबूत अंतर-संपर्क और सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच अंतर-संबंध स्पष्ट हैं। निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रवाह अपने समकक्ष की तुलना में काफी मजबूत है। भुगतान नेटवर्क में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंक मिलाकर दोनों महीनों में मूल्य के अनुसार कुल लेनदेन का 60 प्रतिशत से अधिक है जो उनकी अधिक भागीदारी को दर्शाता है। इसके विपरीत सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण, भुगतान और लघु वित्त बैंक के भुगतान नेटवर्क में कम कनेक्टिविटी है। चार्ट 4 बी में एड्जेस का घनत्व बैंक समूहों और अंतर-समूह लेनदेन के बीच लेनदेन मूल्य की गंभीरता का संकेत देता है।

एनईएफटी नेटवर्क के शीर्ष 20 बैंक

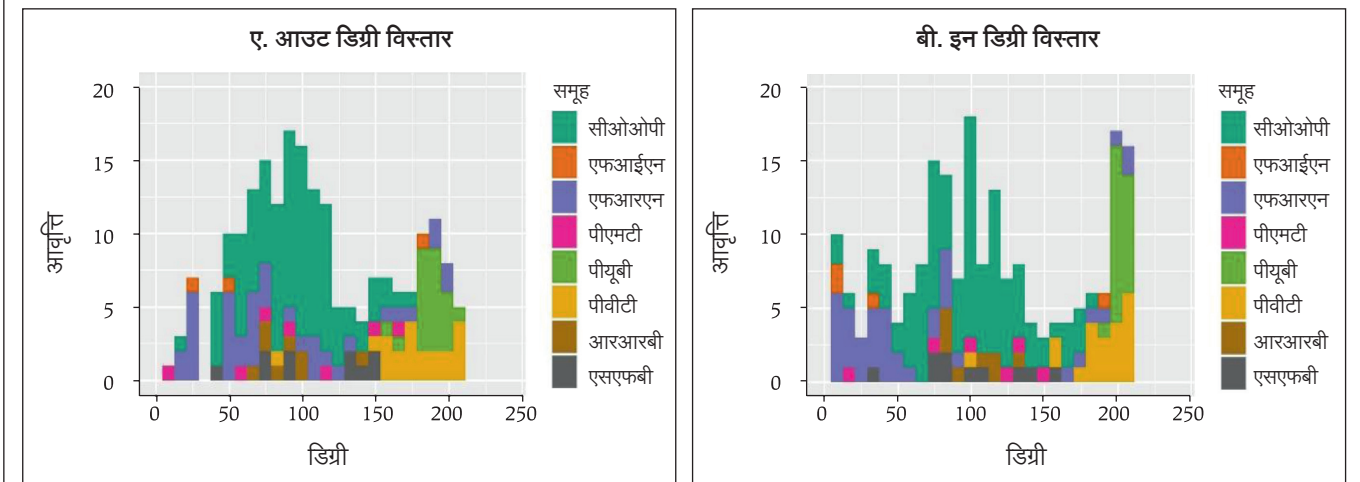
चूंकि सेंट्रालिटी उपाय विभिन्न तरीकों से एक ही सार को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, बिना किसी सामान्यता के, हम उम्मीद करते हैं कि उपाय कुछ हद तक (सारणी 4) से

सारणी 4: सेंट्रालिटी उपायों के बीच सहसंबंध

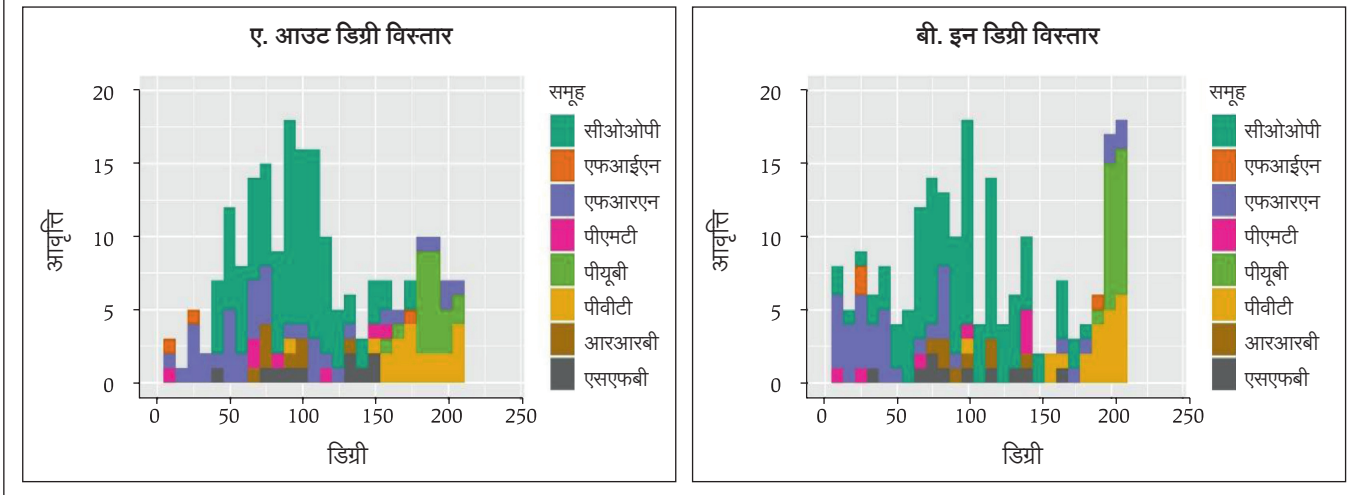
	मार्च 2019					अप्रैल 2019				
	जेडडीजी	जेडएससी	जेडबीडब्ल्यू	जेडइसी	जेडपीआर	जेडडीजी	जेडएससी	जेडबीडब्ल्यू	जेडइसी	जेडपीआर
जेडडीजी	1	0.43	0	0.97	0.46	1	0.44	0.01	0.97	0.46
जेडएससी	0.43	1	-0.05	0.35	0.92	0.44	1	0.01	0.36	0.95
जेडबीडब्ल्यू	0	-0.05	1	0.02	-0.07	0.01	0.01	1	-0.01	-0.02
जेडइसी	0.97	0.35	0.02	1	0.38	0.97	0.36	-0.01	1	0.37
जेडपीआर	0.46	0.92	-0.07	0.38	1	0.46	0.95	-0.02	0.37	1

* जेडडीजी= नॉर्मलाइज्ड डीग्री सेंट्रालिटी; जेडएससी= नॉर्मलाइज्ड स्ट्रेथ सेंट्रालिटी; जेडबीडब्ल्यू= नॉर्मलाइज्ड बिटवीननेस सेंट्रालिटी; जेडइसी= एलिजेन वेक्टर सेंट्रालिटी जेडपीआर= नॉर्मलाइज्ड पेजररेक सेंट्रालिटी

चार्ट 3ए: एनईएफटी नेटवर्क में डिग्री विस्तार - मार्च 2019



चार्ट 3बी: एनईएफटी नेटवर्क में डिग्री विस्तार- अप्रैल 2019



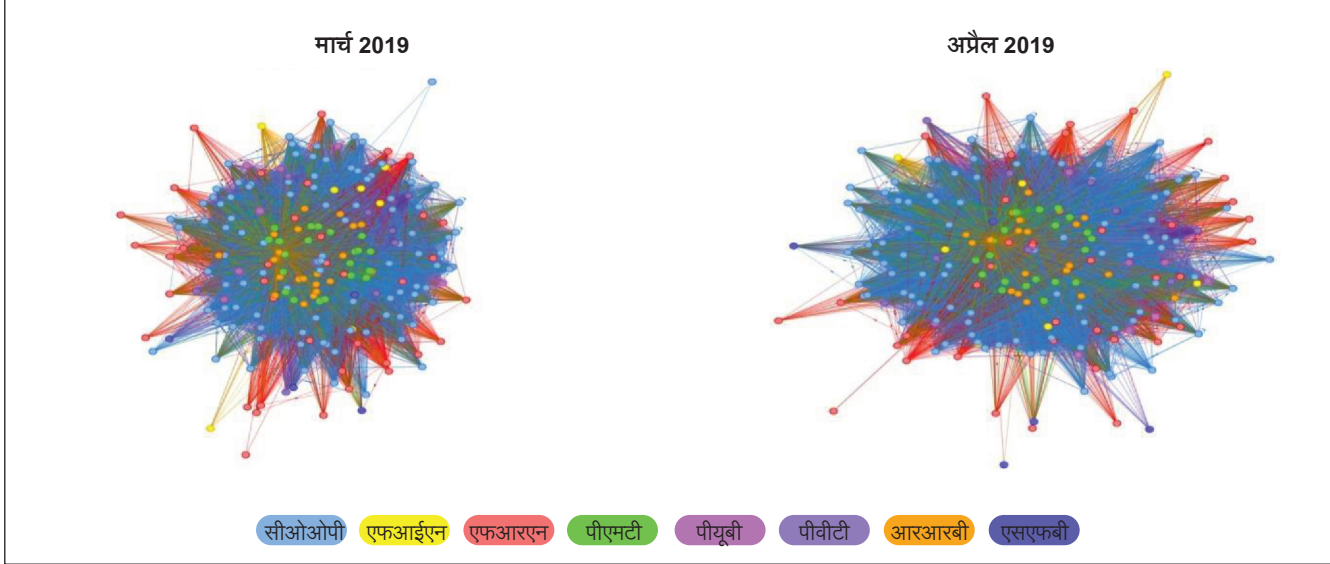
सहसंबद्ध होंगे। इसलिए, हम डेटा की आयामीता और अतिरेक को कम करने के लिए पीसीए दृष्टिकोण की सहायता लेते हैं। यह मुख्य ऑर्थोगोनल घटकों को देता है और इनमें से प्रत्येक उपाय के लिए अपेक्षित महत्व प्रदान करता है। पहला प्रमुख घटक (पीसी) अकेले सेंट्रलिटी उपायों (सारणी 5) में लगभग 55 प्रतिशत भिन्नता दर्शाता है। हम सेंट्रलिटी सूचकांक (सारणी 6) के निर्माण में पहले पीसी के गुणांक का उपयोग करते हैं।

हालांकि एनईएफटी प्रणाली में सभी बैंक सीधे एक-दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन संयोग से कुछ बैंकों में एक महीने में एक-दूसरे के साथ लेन-देन नहीं होता है। ऐसे मामलों में जहां प्रत्यक्ष लेनदेन लिंकेज नहीं होता है, बिटवीननेस गुणांक उन नोड्स को उच्च महत्व देता है जो इन नोड्स को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित हैं। जैसा कि अपेक्षित है, हमें कम बिटवीननेस गुणांक मिलता है क्योंकि अधिकांश प्रतिभागियों का नेटवर्क

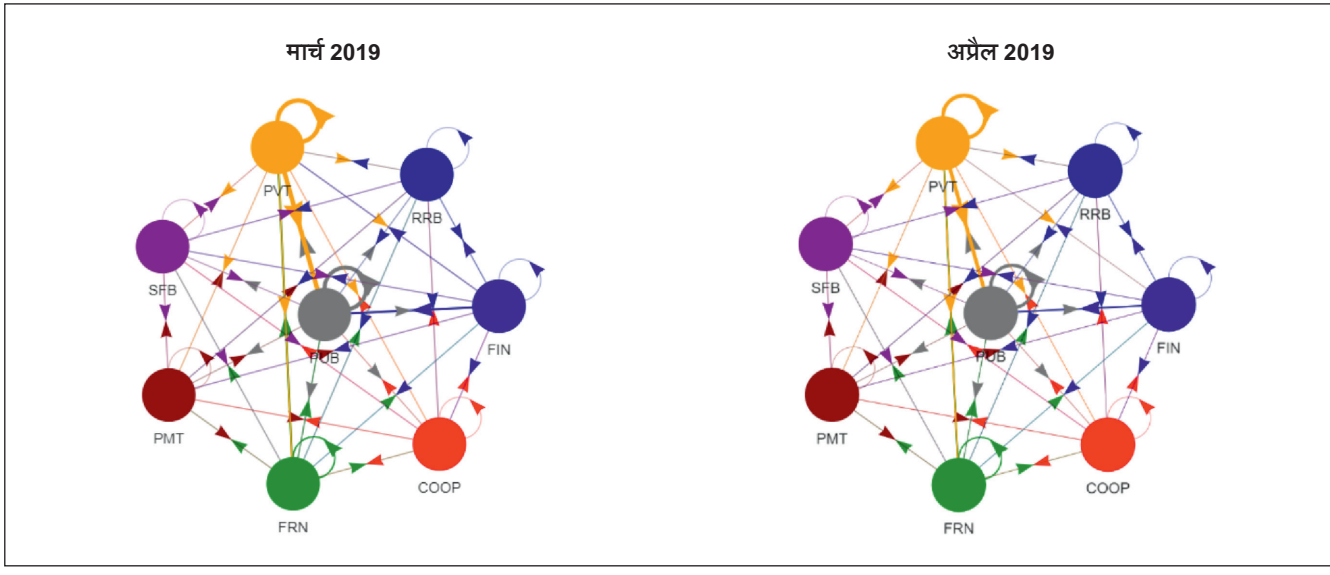
सारणी 5: घटकों का महत्व

	मार्च 2019					अप्रैल 2019				
	पीसी1	पीसी2	पीसी3	पीसी4	पीसी5	पीसी1	पीसी2	पीसी3	पीसी4	पीसी5
प्रपॉर्शन ऑफ वेरियंस	0.55	0.23	0.19	0.02	0.00	0.56	0.23	0.20	0.01	0.00
क्यूमिलेटिव प्रपॉर्शन	0.55	0.79	0.98	1.00	1.00	0.56	0.79	0.99	1.00	1.00
स्टैंडर्ड डेविएशन	1.66	1.08	0.98	0.29	0.15	1.67	1.07	1.00	0.22	0.15

चार्ट 4ए: बैंक-वार - एनईएफटी मूल्य का नेटवर्क



चार्ट 4बी: बैंक समूह-वार - एनईएफटी मूल्य का नेटवर्क



में अन्य प्रतिभागियों के साथ सीधा लेनदेन संबंध है। अंतिम सेंट्रलिटी स्कोर के आधार पर हम नोड्स को 0 और 1 के बीच रैंक देते।

सारणी 6: प्रधान घटकों के गुणांक

सेंट्रलिटी उपाय	मार्च 2019	अप्रैल 2019
डिग्री	0.52	0.52
स्ट्रेंथ	0.49	0.49
बिटवीननेस	-0.03	0.00
एजेन वेक्टर	0.49	0.49
पेजरैंक	0.50	0.50

एकीकृत सेंट्रलिटी उपाय के आधार पर, हमने सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों के शीर्ष 20 बैंकों को रैंकिंग दिया हैं। मार्च और अप्रैल 2019 में शीर्ष 20 बैंकों में 10 सरकारी बैंक, 6 निजी क्षेत्र के बैंक और 4 विदेशी बैंक (सारणी 7) शामिल थे। हम रिजर्व बैंक को शीर्ष 20 बैंकों से हटा देते हैं क्योंकि एक केंद्रीय बैंक और एक फैसिलिटेटर होने के नाते, निपटान असफलता की उसकी संभावना शून्य है। हम पाते हैं कि नेटवर्क के शीर्ष 20 बैंकों का उप-नेटवर्क मार्च और अप्रैल के महीनों में मात्रा के अनुसार भुगतान आवागमन (फिन समूह को छोड़कर) का लगभग 64 प्रतिशत और मूल्य के अनुसार भुगतान आवागमन (फिन समूह

सारणी 7: शीर्ष 20 घटक

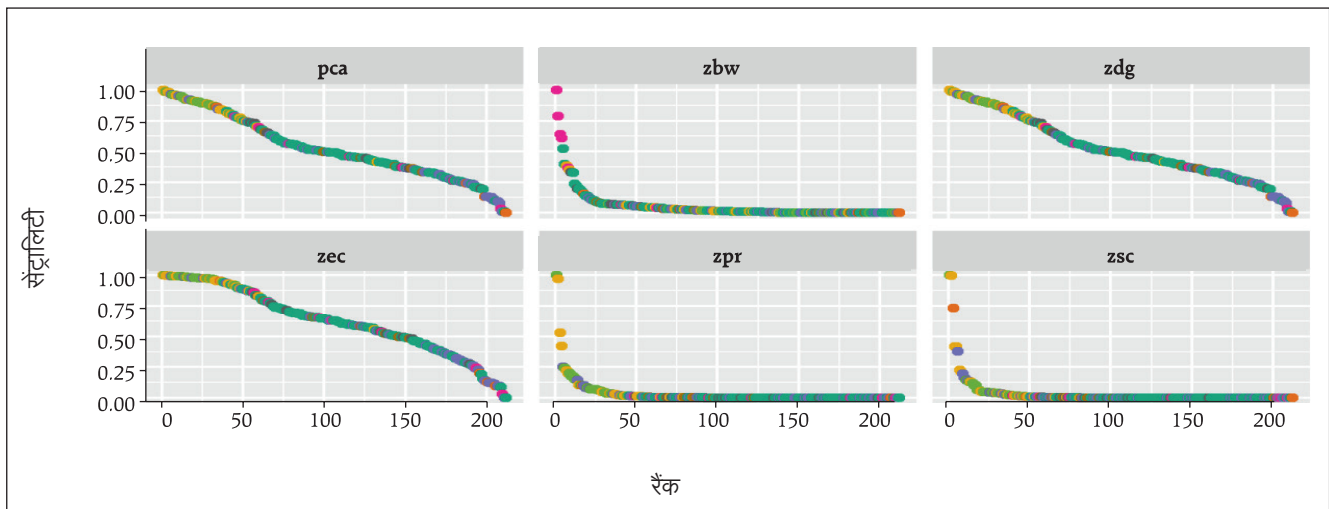
	मार्च 2019						अप्रैल 2019					
	जेडडीजी	जेडएससी	जेडबीडब्ल्यू	जेडइसी	जेडपीआर	पीसीए	जेडडीजी	जेडएससी	जेडबीडब्ल्यू	जेडइसी	जेडपीआर	पीसीए
सीओओपी			10						8			
एफआरएन	4	4	1	3	5	4	3	5	3	2	5	4
पीएमटी			5						7			
पीयूबी	9	8		10	9	10	11	8		11	9	10
पीवीटी	7	8	2	7	6	6	6	7		7	6	6
आरआरबी												
एसएफबी			2						2			

को छोड़कर) का लगभग 68 प्रतिशत योगदान देता है। नेटवर्क में कम मात्रा और मूल्य योगदान के कारण, इस सूची में सहकारी बैंकों, आरआरबी, एसएफबी और भुगतान बैंकों में से कोई भी

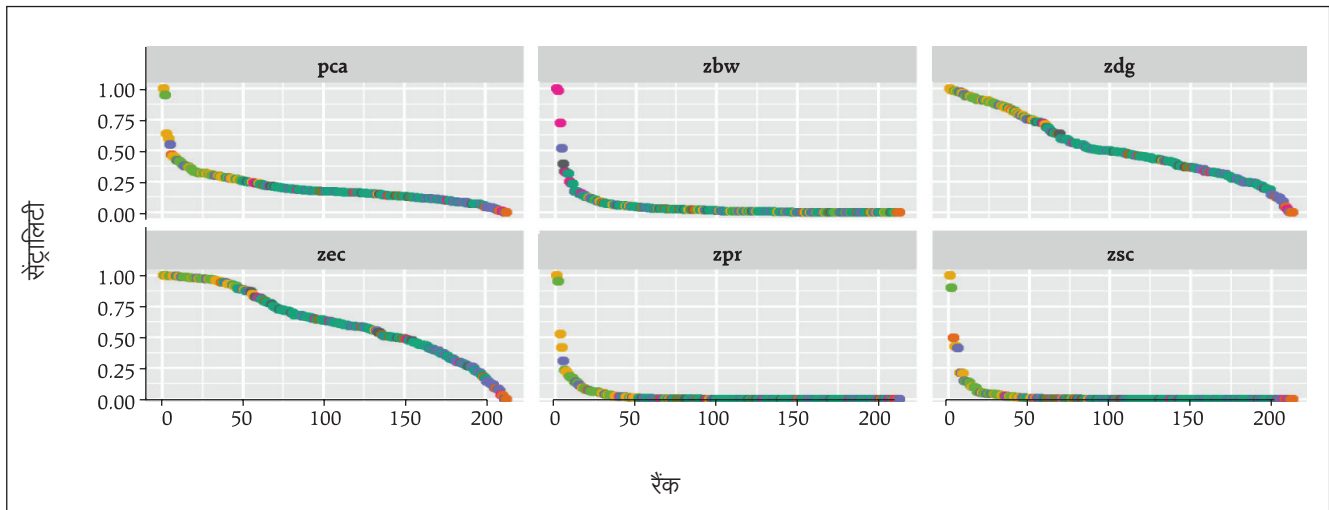
उपस्थित नहीं है। यह अध्ययन एक दिलचस्प तथ्य सामने लाता है कि एससीबी की कुल आस्तियों में 5.7 प्रतिशत की अपेक्षाकृत छोटी हिस्सेदारी के बावजूद कुछ विदेशी बैंक एनईएफटी प्रणाली में बहुत प्रभावशाली है।

हम व्यक्तिगत सेंट्रलिटी उपायों और पीसीए दृष्टिकोण (चार्ट 5) का उपयोग करके प्राप्त एकीकृत सेंट्रलिटी उपाय के आधार पर सभी एनईएफटी-सक्षम बैंकों को रैंक करते हैं। बिटवीननेस को छोड़कर सभी सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों ने शीर्ष रैंक प्राप्त करने का संकेत देते हैं। हालांकि, बिटवीननेस सूचकांक द्वारा वर्गीकृत बैंकों में हमें शीर्ष रैंक के बैंक नहीं मिलते हैं। मार्च 2019 के लिए बिटवीननेस द्वारा

चार्ट 5ए: बैंक रैंकिंग बनाम सेंट्रलिटी (मार्च 2019)



चार्ट 5बी: बैंक रैंकिंग बनाम सेंट्रलिटी (अप्रैल 2019)



● सीओओपी ● एफआईएन ● एफआरएन ● पीएमटी ● पीयूबी ● पीवीटी ● आरआरबी ● एसएफबी

वर्गीकरण करने पर शीर्ष 20 स्थानों पर हमें 10 सहकारी बैंकों, 5 भुगतान बैंकों और 2 लघु वित्त बैंक मिलते हैं और लगभग इसी प्रकार का चित्र अप्रैल 2019 में दिखाई देता है (चार्ट 5 जेडबीडब्ल्यू)। जैसा कि पहले कहा गया है, सीधे लेन-देन की कड़ी रहित दो अन्य नोडों के बीच जितनी बार कोई नोड सेतु का काम करता है, मध्यत्व माप उसको अंकबद्ध करता है। हमारे मामले में, यह सहभागियों की रैंकिंग पर एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य देता है जहाँ कुछ सहकारी बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक उन बैंकों के लिए जोड़ने वाले कोड्स का काम कर रहे हैं जो एनईएफटी नेटवर्क में सीधा लिंकेज नहीं शेयर करते। राज्य स्तरीय व बड़े शहरी सहकारी बैंक जहाँ छोटे सहकारी बैंकों के लिए माध्यम का कार्य कर रहे हैं वहीं भुगतान बैंकों की उपस्थिति बड़ी है क्योंकि वे विशिष्ट बैंक हैं जो भुगतान, जमा, धन-प्रेषण, इंटरनेट बैंकिंग आदि बैंकिंग सेवाएं देकर मुख्यतः भुगतान के क्षेत्र में कार्यरत हैं।

VI. निष्कर्ष

नेटवर्क विश्लेषण व्यापक स्तर पर भुगतान प्रणालियों के विश्लेषण के नए साधन देता है। यह प्रणाली स्तर पर प्रतिरूपों (पैटर्न्स) को पहचानने में सहायक होता है, जिसका आकलन, अन्यथा, द्विपक्षीय लेन-देन मात्रा और मूल्य स्तर विश्लेषण के प्रयोग से मुश्किल है। नेटवर्क में भुगतानों के प्रवाह को बेहतर समझने के लिए हम एनईएफटी इंटरबैंक फंड ट्रांसफरों की नेटवर्क टोपोलॉजी और संरचना का विश्लेषण करते हैं। हमारा अध्ययन नेटवर्क विन्यास में सहज बोध से स्वीकार्य पैटर्नों का पता लगाता है और उन क्लस्टरों को चिह्नित करता है जिनको ढूँढ़ना पारंपरिक अर्थशास्त्र के प्रयोग से मुश्किल होता। यह दर्शाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों की ओर से मूल्य के हिसाब से एनईएफटी सिस्टम के कुल लेन-देनों का लगभग 83 प्रतिशत और 87 प्रतिशत क्रमशः मार्च और अप्रैल में आया। सार्वजनिक से सार्वजनिक (पब्लिक टू पब्लिक) और प्राइवेट से प्राइवेट बैंकों के नेटवर्क के अंतर्गत भुगतान प्रवाह विशेष रूप से मजबूत हैं। प्राइवेट टू पब्लिक सेक्टर बैंकों का प्रवाह भी बहुत बड़ा है जिसमें सिस्टम में पब्लिक सेक्टर बैंक निवल प्राप्तकर्ता (नेट रिसीवर्स) हैं। मार्च और अप्रैल महीनों में रिजर्व बैंक से एनईएफटी सहभागियों को जाने वाले बड़े प्रवाह

भी हम देख रहे हैं। सभी 12 महीनों में एनईएफटी लेन-देनों के अध्ययन से इसमें निहित मौसमी पैटर्न के बारे में हमें अधिक संपूर्णता से जानकारी मिल सकेगी।

आदर्शतः, एनईएफटी सुविधा वाले सभी बैंक डिजाइन के जरिये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तथापि, हमारा अध्ययन इस पर भी साक्ष्य दर्शाता है कि नेटवर्क के कुछ बैंकों से कुछ बैंकों का कोई लेन-देन नहीं होता। व्यापक स्तर पर, अधिकांश सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों के आपस में सीधे लेन-देन की कड़ी जुड़ी हुई है; तथापि, सहकारी बैंकों सहित अपेक्षाकृत कुछ छोटे बैंकों के ऐसे सीधे लिंकेज नहीं होते। ऐसे मामलों में बड़े सहकारी बैंक और भुगतान/ लघु वित्त बैंक उन बैंकों के बीच कड़ी का काम करते हैं जिनमें आपस में लेन-देन के लिंकेज नहीं हैं। अतः सहकारी बैंकों, लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों में हमें बिटवीननेस सूचकांक उच्चतर तथा प्रमुख सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र व विदेशी बैंकों में निम्न देखने को मिलता है।

बड़ी संख्या में सहभागियों के प्रति भुगतान दायित्व वाले बड़े बैंकों की निपटान विफलताओं या अंतराल का भुगतान प्रणाली की स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है। इस संदर्भ में, अंतर्संबद्धताओं, स्तर, ताकत, नेटवर्क में स्थिति आदि विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए भुगतान उद्योग में महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की समग्र रैंकिंग प्राप्त करने में यह विश्लेषण एक उपयोगी उद्देश्य पूरा करता है। प्रणालीगत दृष्टि से, हम पाते हैं कि भुगतान मूल्य व मात्रा में शीर्ष 20 बैंकों का बड़ा हिस्सा है। उनमें निपटान विफलताओं से परिचालनगत बाधाएं पैदा हो सकती हैं जिसका पूरे भुगतान/ निपटान प्रणाली पर असर पड़ सकता है।

वित्तीय तकनीकों के आने से पेमेंट नेटवर्क की टोपोलॉजी तेजी से बदल रही है। इन परिवर्तनों का आकलन दीर्घवाधि में नेटवर्क टेक्नॉलॉजी में हो रहे बदलावों के माध्यम से हो सकता है। चूंकि भुगतान संबंधी आँकड़े कम समय के उपलब्ध कराए जा सकते हैं, वास्तविक समय पर अंतर्संबद्धता को ट्रैक करने में नेटवर्क विश्लेषण उपयोगी हो सकता है। भुगतान प्रणालियों का विश्लेषण अंतर्बैंक एक्सपोजरों के वर्तमान विश्लेषण का पूरक है। भारत में भुगतान (पेमेंट) नेटवर्कों के विकास पर प्रकाश डालने में और भुगतान प्रवाहों से यदि कोई जोखिम हो तो उसका सटीक पता लगाने में यह विश्लेषण उपयोगी होगा। नेटवर्क साहित्य का

साक्ष्य बताता है कि अधिक अंतर्संबद्ध नेटवर्क आघातों के बढ़ने व घटने में भी सहायक हो सकते हैं। तथापि, बढ़ने या घटने की प्रक्रिया और मात्रात्मक वितरण व टॉपोलॉजी की विशेषताओं के अनुसार उनका वर्णन आगे के शोध का एक क्षेत्र है। ऐसी प्रत्याशा है कि वित्तीय प्रणाली स्थिरता में योगदान के अलावा, यह अध्ययन भारत की भुगतान प्रणाली के संबंध में आगे और शोध को प्रेरित करेगा।

संदर्भ :

Acemoglu, D., A. Ozdaglar and A.T. Salehi (2015), "Systemic Risk and Stability in Financial Networks", *The American Economic Review*, 105(2), 564-608.

Albert, R., H. Jeong and A.L. Barabasi (1999), "Diameter of the World Wide Web", *Nature*, 401(130). Available at SSRN:

<https://ssrn.com/abstract=1733528> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1733528>

Barrat, A., M. Barthélemy, R. P. Satorras, and A. Vespignani (2004), "The architecture of complex weighted networks", *PNAS* March 16, 2004 101 (11) 3747-3752.

Becher, C., S. Millard and K. Soramäki (2008), "The network topology of CHAPS Sterling", *Bank of England Working Paper* No. 355, November.

Borgatti, S.P. and M.G. Everett (1999), "Models of core/periphery structures", *Social Networks* 21, 375-395.

Brin, S. and L. Page (1998). The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine. *Computer Networks and ISDN Systems*, 30, 107- 117.

Caccioli, F., P. Barucca and T. Kobayashi (2018). Network models of financial systemic risk: a review. *Journal of Computational Social Science*, 1, 81-114.

Chapman, J., L. Embree, and T. Roberts (2011). Payment networks: A review of recent research. *Bank of Canada Review*, winter 2010-2011.

Cont, R., M. Amal and E.B. Santos (2010). Network Structure and Systemic Risk in Banking Systems. December 1.

Cytoscape User Manual. Navigation and Layout. Accessed 13 Jul 2019. [http://manual.cytoscape.org/en/](http://manual.cytoscape.org/en/stable/Navigation_and_Layout.html#edge-weighted-spring-embedded-layout)

[stable/Navigation_and_Layout.html#edge-weighted-spring-embedded-layout](http://manual.cytoscape.org/en/stable/Navigation_and_Layout.html#edge-weighted-spring-embedded-layout)

Disney, A. (2015), "Eigen Centrality and PageRank", *Cambridge Intelligence*, Nov 2, 2015. <https://cambridge-intelligence.com/eigencentrality-pagerank/>

Dunbar, R.I.M., V. Arnaboldi, M. Conti and A. Passarella (2015), "The structure of online social networks mirrors those in the offline world", *Social Networks*, 43, 39-47.

Elliott, M., B. Golub, and M. O. Jackson (2014), "Financial Networks and Contagion", *American Economic Review*, 104(10), 3115-3153.

Embree, L. and T. Roberts (2009), "Network Analysis and Canada's Large Value Transfer System", *Bank of Canada Discussion Paper* 2009/13, December.

Gai, P. and S. Kapadia (2010), "Contagion in financial networks", *Proceedings: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 466(2120), 2401-2423.

Grandjean, M. (2016), "A social network analysis of Twitter: Mapping the digital humanities community", *Cogent Arts and Humanities*, Taylor Francis.

<https://doi.org/10.1073/pnas.0400087101>

Imakubo, K. and Y. Soejima (2010), "The Transaction Network in Japan's Interbank Money Markets", Bank of Japan, *Monetary and Economic Studies*, November.

Iori, G., G.D. Masi, O.V. Precup, G. Gabbi and G. Calderelli (2005), "A Network Analysis of the Italian Overnight Money Market", *City University London*, Discussion Paper Series 05/05.

Jaramillo, S.M., B.A. Kabadjova and B.B. Benitez, J.P.S. Margain (2014), "An empirical study of the Mexican banking system's network and its implications for systemic risk", *Journal of Economic Dynamics and Control*, 40, 242 - 265.

Kali, R. and J. Reyes (2007), "The Architecture of Globalization: A Network Approach to International Economic Integration", *Journal of International Business Studies*, 38(4), 595-620.

Kamada, T. and S. Kawai (1989), "An Algorithm for Drawing General Undirected Graphs", *Information Processing Letters*, 31, 7-15.

- Langfield, S. and Z. Liu and T. Ota (2014), "Mapping the UK interbank system", *Journal of Banking and Finance*, 45, 288–303.
- Lublóy, Á. (2006), "Topology of the Hungarian large-value transfer system", *MNB Occasional Papers* 2006/57.
- Ma, A. and Mondragón, R.J. (2015), "Rich-Cores in Networks", *PLoS ONE*, 10(3): e0119678.
- Nier, E., J. Yang, T. Yorulmazer and A. Alentorn (2007), "Network models and financial stability", *Journal of Economic Dynamics and Control*, 31, 2033–2060.
- Oesterreichische National Bank (OeNB) Financial Stability Report 7 "An Empirical Analysis of the Network Structure of the Austrian Interbank Market", 77-87.
- Pröpper, M., Lelyveld, I. V. and Heijmans, R. (2008), "Towards a Network Description of Interbank Payment Flows", *De Nederlandsche Bank, Working Paper* No. 177.
- Soramäki, K., M.L. Bech, J. Arnold, R.J. Glass and W.E. Beyeler (2006), "The Topology of Interbank Payment Flows", *Federal Reserve Bank of New York Staff Reports* 243, March.
- Upper, C. and A. Worms (2004), "Estimating bilateral exposures in the German interbank market: Is there a danger of contagion?", *European Economic Review*, 48, 827–849.

अनुबंध

कुछ महत्वपूर्ण नेटवर्क मैट्रिक्स की परिभाषा

इस अध्ययन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण केंद्रीयता मापों (सेंट्रलिटी मेजर्स) का संक्षिप्त विवरण इस अनुबंध में है।

ए.1 संयोजन आधारित माप (कनेक्शन बेस्ड मेजर्स)

- **संयोजकता (कनेक्टिविटी) :** इसे नेटवर्क घनत्व के रूप में भी जाना जाता है, यह बतता है कि कोई नेटवर्क समग्र रूप में कितनी अच्छी तरह कार्य करता है। यह एजेज की अधिकतम संभव संख्या और एजेज की वास्तविक संख्या के अनुपात को सूचित करता है। बिना किसी लिंक वाले वियोजित (डिसकनेक्टेड) ग्राफ के लिए यह 0 और पूर्ण नेटवर्क के लिए 1 है। निर्देशित (डायरेक्टेड) ग्राफ के लिए कनेक्टिविटी $\frac{m}{N(N-1)}$ के बराबर है जहाँ m कड़ियों की संख्या है और N नोड्स की संख्या। अनिर्देशित ग्राफ के लिए कनेक्टिविटी $\frac{m}{2C}$ है।
- **पारस्परिकता (रेसिप्रोसिटी) :** रेसिप्रोसिटी निर्देशित कड़ियों (m) की तुलना में प्रतिसादित (रेसिप्रोकेटेड) कड़ियों (m_r) की संख्या के अनुपात को सूचित करता है।
रेसिप्रोसिटी, $r = \frac{m_r}{m}$

ए.2 केंद्रीयता (सेंट्रलिटी) और केंद्रीकरण (सेंट्रलाइजेशन)

- **मात्रा केंद्रीयता (डिग्री सेंट्रलिटी) :** डिग्री सेंट्रलिटी प्रत्येक नोड से जुड़े नोड्स की संख्या की गणना करती है 0 व 1 के बीच संख्याओं के मापने (स्केल) के लिए इसे $(N-1)$ से भाग दिया जाता है।

$$\text{डिग्री सेंट्रलिटी, } C_{DG} = \frac{d(n_i)}{N-1}$$

जहाँ d_{n_i} नोड n_i की डिग्री है और N नोड्स की संख्या है।

- **मध्यत्व केंद्रीयता:** उन पथों का प्रतिशत मापता है जो किसी खास नोड से होकर जाते हैं। उच्च मध्यत्व के नोड दो विभिन्न समूहों या क्लस्टरों को जोड़ने में अहम हैं।

$$\text{मध्यत्व केंद्रीयता, } C_{BW} = \frac{\sum_{i,i \neq v} \sum_{j,j \neq i,j \neq v} \frac{g_{ivj}}{g_{ij}}}{(N-1)(N-2)}$$

जहाँ g_{ij} नोड i से नोड j तक सबसे छोटे पथों की संख्या है और,

g_{ivj} v से होकर नोड i से नोड j तक सबसे छोटे पथों की संख्या है।

- **अइगन वेक्टर सेंट्रलिटी :** किसी नोड की मात्रा (डिग्री) ऊँची हो सकती है, परंतु नेटवर्क की दृष्टि से इसके कनेक्शंस महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में, डिग्री के मापों से किसी नोड के महत्व के बारे में गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं। अइगन वेक्टर सेंट्रलिटी गणना पुनरावृत्तीय पद्धति है जहाँ नोड i की केंद्रीयता (सेंट्रलिटी) की गणना नोड i के पड़ोसियों (समीपस्थों/नेबर्स) की केंद्रीयता को जोड़कर निकाली जाती है। यदि प्रभावशाली नोडों से जुड़े हों तो यह नोडों को अधिक मान (भार/वेट) देता है।

$$c_i = \frac{1}{\lambda} \sum_{j \in G} a_{ij} c_j$$

उपर्युक्त समीकरण $Ac = \lambda c$, के मैट्रिक्स रूप में भी फिर से लिखा जा सकता है जहाँ A ग्राफ (G) का एडजेंसी मैट्रिक्स है। समीकरण का सबसे बड़ा ईगन वैल्यू अइगन वेक्टर सेंट्रलिटी के रूप में निकलकर आता है।

- **पेजरैंक सेंट्रलिटी:** पेजरैंक अइगन सेंट्रलिटी का एक अधिक जटिल रूप है जिसे गूगल के संस्थापकों ने वेबपेजों को रैंक करने के लिए डिजाइन किया था। हर वेबपेज को आने वाली कड़ियों (इन-कमिंग लिंक्स) की संख्या के आधार पर एक अंक (स्कोर) दिया जाता है ('इसकी इन-डिग्री')। इन लिंक्स को भी इनके प्रारंभिक नोड के सापेक्ष स्कोर के आधार पर मान दिया जाता है। यह पुनरावृत्तीय अल्गोरिथ्म पर चलता है, जहाँ निम्नलिखित फॉर्मूले के आधार पर पेजरैंक निकाला जाता है

$$PR_{t+1}(i) = \sum_{j \in L(i)} \frac{PR_t(j)}{C(j)}$$

जहाँ $L(i)$ का तात्पर्य i की ओर प्वाइंट करने वाले समस्त नोडों से है और $C(j)$ उन बहिर्गामी लिंकों की संख्या बताता है जो नोड j से निकल रहे हैं। पहली पुनरावृत्ति सभी नोडों के लिए $\frac{1}{n}$ के एक प्रारंभिक पेजरैंक से शुरू होती है।

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

अवसरिक श्रृंखलाएं

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	51
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	52
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	53
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डालर का क्रय/विक्रय	54
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	55
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	55
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	56
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	57
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	58
9	कुल चलनिधि राशियां	58
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	59
11	आरक्षित मुद्रा- घटक और स्रोत	59
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	60
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	60
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	61
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन	62
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	63
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	64
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	65
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	65
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	65
21	थोक मूल्य सूचकांक	66
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	69
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	69
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	70
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	70
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	71
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	72
28	वाणिज्यिक पत्र	72
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	72
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	73

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	74
32	विदेशी मुद्रा भंडार	74
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	74
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	75
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	75
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	76
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार	76
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	77
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (बिलियन ₹)	78
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	79
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (बिलियन ₹ में)	80
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	81
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	82
	अवसरिक श्रृंखलाएं	
44	लघु बचत	83
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	84
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	85
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	86
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	87
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	88

टिप्पणियां: .. = उपलब्ध नहीं।

- = शून्य/नगण्य

प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम

आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1: चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2018-19	2017-18		2018-19	
		ति३	ति४	ति३	ति४
	1	2	3	4	5
1 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	6.6	7.3	7.9	6.3	5.7
1.1.1 कृषि	2.9	4.6	6.5	2.8	-0.1
1.1.2 उद्योग	6.2	8.0	8.6	6.0	3.4
1.1.3 सेवाएं	7.7	8.0	8.0	7.6	8.2
1.1क अंतिम खपत व्यय	8.3	5.8	8.1	7.9	8.1
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	10.0	12.2	14.4	11.7	3.6
	2018-19	2018		2019	
		मई	जून	मई	जून
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	3.60	3.8	7.0	3.1	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	10.0	8.1	6.8	11.1	10.4
2.1.2 ऋण	13.3	12.8	10.9	13.5	11.9
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	13.4	13.0	10.9	13.3	11.9
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1.9	5.1	6.0	3.7	1.8
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	14.5	24.9	21.1	13.8	13.5
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम३)	10.5	10.4	9.8	10.3	10.1
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	19.25	19.50	19.50	19.00	19.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.1	4.7	4.9	4.9	5.1
3.4 ऋण-जमा अनुपात	77.7	75.2	75.4	76.8	76.4
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	99.9	**	65.7	-212.9	-60.4
3.6 निवेश-जमा अनुपात	26.9	29.7	29.9	27.7	27.6
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	5.4	*	169.3	302.3	105.7
4 व्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	6.25	6.00	6.25	6.00	5.75
4.2 रिवर्स रिपो दर	6.00	5.75	6.00	5.75	5.50
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	6.50	6.25	6.50	6.25	6.00
4.4 बैंक दर	6.50	6.25	6.50	6.25	6.00
4.5 आधार दर	8.95/9.40	8.70/9.45	8.70/9.45	8.95/9.40	8.95/9.40
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	8.05/8.55	7.80/7.95	7.80/8.05	8.05/8.50	8.05/8.50
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	6.25/7.50	6.25/6.75	6.25/7.00	6.25/7.50	6.25/7.30
4.8 बचत जमा दर	3.50/4.00	3.50/4.00	3.50/4.00	3.50	3.50
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	6.35	5.94	6.17	5.90	5.78
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.31	6.40	6.52	6.19	6.03
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.35	6.80	6.89	6.27	6.16
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.39	6.93	7.13	6.30	6.16
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	7.34	7.92	7.98	7.07	6.93
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिआ					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	69.17	68.26	68.58	69.81	68.92
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	77.70	79.88	79.85	77.73	78.36
5.3 फारवर्ड प्रीमिआ अमेरिकी डालर					
1-माह (%)	6.07	4.13	4.46	3.95	4.61
3-माह (%)	4.80	4.01	4.37	3.95	4.64
6-माह (%)	4.16	4.04	4.39	3.93	4.70
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	3.4	4.9	4.9	3.1	3.2
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.4	4.0	3.9	8.7	8.6
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	4.3	4.8	5.7	2.5	2.0
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	2.7	3.8	4.7	6.2	6.7
6.3.2 ईंधन और पावर	11.5	12.7	16.5	1.0	-2.2
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	3.7	3.8	4.2	1.3	0.9
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	10.3	14.7	19.6	3.3	-9.1
7.2 निर्यात	8.6	20.5	20.4	4.0	-9.7

** हर और अंश नकारात्मक है

* हर नकारात्मक है

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) ने भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसारण शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2: भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(बिलियन ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार / शुक्रवार की स्थिति						
	2018-19	2018	2019				
		जुलाई	जून 28	जुलाई 5	जुलाई 12	जुलाई 19	जुलाई 26
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	21,137.64	18,968.03	21,635.30	21,716.25	21,790.36	21,615.26	21,495.53
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	0.11	0.11	0.09	0.11	0.12	0.14	0.13
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	21,137.75	18,968.14	21,635.39	21,716.36	21,790.48	21,615.40	21,495.66
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	794.81	743.49	757.82	792.04	792.04	792.04	825.72
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	20,335.59	18,215.32	20,869.24	20,916.01	20,990.24	20,815.16	20,661.81
1.2.3 रुपया सिक्का	7.35	9.33	8.33	8.32	8.20	8.20	8.13
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	—	—	—	—	—	—	—
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	8,060.12	5,835.36	7,455.15	7,837.37	7,764.92	7,857.65	7,593.96
2.1.1.1 केंद्र सरकार	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	—	—	—	—	—	—	—
2.1.1.3 राज्य सरकारें	0.43	0.42	0.42	0.43	0.43	0.42	0.42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	5,657.07	4,738.57	5,720.13	5,099.69	5,100.77	5,330.13	5,259.08
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	41.97	35.17	39.97	40.30	39.99	40.09	40.83
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	34.94	20.12	26.61	26.92	26.22	26.47	26.18
2.1.1.7 अन्य बैंक	320.36	271.68	308.66	299.57	299.77	306.46	303.27
2.1.1.8 अन्य	1,997.34	768.39	1,358.36	2,341.00	2,296.74	2,125.63	1,963.17
2.1.1.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थान	7.00	—	—	28.45	—	27.44	—
2.1.2 अन्य देयताएं	10,876.86	10,363.28	11,309.45	11,173.50	11,195.54	11,338.43	11,343.10
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	18,936.98	16,198.64	18,764.59	19,010.87	18,960.46	19,196.08	18,937.06
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	0.11	0.11	0.09	0.11	0.12	0.14	0.13
2.2.2 विदेश में रखे शेष	6,466.40	8,065.31	6,926.94	6,784.78	6,690.02	7,037.43	7,104.69
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	—	—	65.96	667.93	789.43	657.29	370.84
2.2.3.2 राज्य सरकारें	0.10	1.71	16.61	55.66	69.94	31.40	8.96
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1,806.88	762.95	541.85	343.05	293.65	352.63	295.70
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.6 नाबार्ड	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.7 एक्विजम बैंक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.8 अन्य	134.63	62.82	67.91	55.31	60.87	59.87	58.46
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	7.00	—	—	-0.14	—	-0.14	—
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	—	—	—	—	—	—	—
2.2.5 निवेश	9,230.80	6,433.51	9,857.67	9,918.63	9,870.35	9,870.66	9,870.96
2.2.6 अन्य आस्तियां	1,291.06	872.23	1,287.57	1,185.54	1,186.08	1,186.80	1,227.31
2.2.6.1 सोना	871.69	710.41	844.83	882.98	882.98	882.98	920.52

* डाटा अंतिम है।

सं. 3: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(बिलियन ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9-2-4-7-8)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिपोर्ट दर				विक्रय	क्रय	
जून 1, 2019	20.00	343.10	-	-	1.50	-	-	-	-	-321.60
जून 3, 2019	43.41	185.33	-	869.07	21.00	-	-	-	-	-989.99
जून 4, 2019	52.86	148.66	4.40	601.43	19.50	-2.32	-	-	-	-675.65
जून 6, 2019	42.56	183.87	-	350.08	22.31	-0.70	-	-	-	-469.78
जून 7, 2019	71.17	244.16	139.75	390.42	26.54	0.70	-	-	-	-396.42
जून 10, 2019	88.72	104.08	-	277.70	-	-	-	-	-	-293.06
जून 11, 2019	43.62	101.51	138.40	390.24	-	-10.06	-	-	-	-319.79
जून 12, 2019	43.47	107.67	-	425.03	-	5.86	-	-	-	-483.37
जून 13, 2019	51.42	119.70	-	445.59	9.00	4.25	-	-	-	-500.62
जून 14, 2019	124.57	135.71	48.00	662.95	20.55	-0.32	-	-	150.00	-455.86
जून 15, 2019	40.08	133.36	-	-	12.95	-	-	-	-	-80.33
जून 17, 2019	46.62	83.93	-	406.79	65.11	-	-	-	-	-378.99
जून 18, 2019	135.23	186.95	80.25	443.76	1.45	-1.10	-	-	-	-414.88
जून 19, 2019	46.98	109.53	-	487.26	2.01	1.10	-	-	-	-546.70
जून 20, 2019	71.27	119.99	-	369.63	18.36	-	-	-	-	-399.99
जून 21, 2019	51.23	312.06	220.65	429.54	14.00	-	-	-	125.10	-330.62
जून 24, 2019	113.82	149.80	-	588.76	23.22	-	-	-	-	-601.52
जून 25, 2019	109.82	158.00	177.90	737.49	0.53	-	-	-	-	-607.24
जून 26, 2019	93.62	327.35	-	850.17	0.01	-	-	-	-	-1,083.89
जून 27, 2019	44.37	371.26	-	947.80	7.60	-	-	-	-	-1,267.09
जून 28, 2019	63.37	547.94	40.85	464.95	2.20	-	-	-	-	-906.47
जून 29, 2019	20.35	791.76	-	-	9.80	-	-	-	-	-761.61

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डालर का क्रय/विक्रय

i) ओटीसी सेगमेंट में परिचालन

मद	2018-19	2018	2019	
		जून	मई	जून
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डालर) (1.1-1.2)	-15,377.00	-6,184.00	2,538.00	2,463.00
1.1 क्रय (+)	40,804.00	4,020.00	5,118.00	4,434.00
1.2 विक्रय (-)	56,181.00	10,204.00	2,580.00	1,971.00
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (बिलियन ₹)	-1,119.45	-424.00	167.98	163.95
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डालर)	-15,377.00	-14,434.00	7,439.00	9,902.00
(बिलियन ₹)	-1,119.45	-976.19	498.90	662.85
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डालर)	-13,774.00	10,689.00	-18,288.00	-13,406.00

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2018-19	2018	2019	
		जून	मई	जून
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डालर) (1.1-1.2)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 क्रय (+)	13,935.00	1,714.00	312.00	0.00
1.2 विक्रय (-)	13,935.00	1,714.00	312.00	0.00
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डालर)	0.00	-692.00	0.00	0.00

सं. 4ए: भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण

(अमरीकी मिलियन डालर)

मद	30 जून 2019 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	1,070	1,469	-399
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	320	1,636	-1,316
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	2,439	3,965	-1,526
4. 1 वर्ष से अधिक	720	10,885	-10,165
कुल (1+2+3+4)	4,549	17,955	-13,406

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2018-19	2018	2019					जुलाई 19
			जुलाई 20	फरवरी 15	मार्च 29	अप्रैल 26	मई 24	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	128.8	29.8	10.9	128.8	10.0	16.2	14.0	11.5
2 अनुसूचित बैंकों के लिए निर्यात ऋण पूर्णवित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 पीडी के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
3.2 बकाया	26.8	24.3	17.9	26.8	23.5	27.6	24.5	23.6
4 अन्य								
4.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	155.6	54.2	28.8	155.6	33.5	43.8	38.5	35.1

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2018-19	2018	2019		
		जून 22	मई 24	जून 7	जून 21
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	20,522.3	18,767.6	21,173.7	21,322.2	21,166.8
1.1 संचलन में नोट	21,108.8	19,316.8	21,786.1	21,936.4	21,799.7
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	251.4	249.7	251.7	252.1	252.1
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
1.4 बैंकों के पास नकदी	845.4	806.3	871.5	873.8	892.5
2 जनता की जमा राशियां	16,580.5	13,123.6	14,562.1	14,378.4	14,329.7
2.1 बैंकों के पास मांग जमा राशियां	16,263.1	12,898.5	14,277.5	14,081.9	14,032.8
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा राशियां	317.4	225.2	284.5	296.5	296.8
3 एम₁ (1+2)	37,102.8	31,891.3	35,735.8	35,700.6	35,496.5
4 डाकघर बचत बैंक जमा राशियां	1,406.0	1,162.0	1,406.0	1,406.0	1,406.0
5 एम₂ (3+4)	38,508.8	33,053.3	37,141.8	37,106.6	36,902.5
6 बैंकों के पास मीयादी जमा राशियां	117,205.9	108,141.0	118,475.0	119,081.2	118,664.7
7 एम₃ (3+6)	154,308.7	140,032.3	154,210.8	154,781.8	154,161.1
8 कुल डाकघर जमा राशियां	3,672.9	3,161.5	3,672.9	3,672.9	3,672.9
9 एम₄ (7+8)	157,981.6	143,193.8	157,883.7	158,454.7	157,834.0

सं. 7: मुद्रा स्टॉक (एम₃) का स्रोत

(बिलियन ₹)

स्रोत	मार्च 31 / माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018	2019		
			जून 22	मई 24	जून 7
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	43,877.9	42,210.0	46,044.1	47,027.0	45,891.1
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	8,019.5	6,188.4	8,792.1	10,060.0	9,197.0
1.1.1 सरकार पर दावे	9,296.9	6,336.9	9,465.3	10,061.4	9,847.7
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	9,281.7	6,336.5	9,460.0	10,007.4	9,846.1
1.1.1.2 राज्य सरकारें	15.2	0.4	5.3	54.0	1.6
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियां	1,277.4	148.5	673.2	1.4	650.7
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	1,276.9	148.1	672.8	1.0	650.3
1.1.2.2 राज्य सरकारें	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	35,858.4	36,021.6	37,252.0	36,967.1	36,694.2
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	103,801.8	92,026.8	102,296.6	102,613.8	102,583.5
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	153.6	95.4	92.5	88.0	84.4
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	103,648.2	91,931.5	102,204.1	102,525.9	102,499.1
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	97,691.9	86,144.2	96,215.5	96,519.0	96,487.3
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	5,859.3	5,704.3	5,888.1	5,907.8	5,912.0
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	97.0	82.9	100.6	99.1	99.8
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	30,708.4	28,834.3	31,365.5	31,489.3	31,820.6
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	28,485.9	27,597.3	29,143.0	29,266.8	29,598.1
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	28,488.0	27,599.4	29,145.1	29,268.9	29,600.2
3.1.2 विदेशी देयताएं	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2,222.5	1,237.0	2,222.5	2,222.5	2,222.5
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	258.9	257.1	259.1	259.5	259.5
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	24,338.2	23,296.0	25,754.5	26,607.9	26,393.7
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	10,588.0	9,785.8	10,711.3	10,979.0	11,159.8
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	13,750.3	13,510.3	15,043.2	15,628.9	15,233.9
एम₃ (1+2+3+4-5)	154,308.7	140,032.3	154,210.8	154,781.8	154,161.1

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018		2019	
		जून 22	मई 24	जून 7	जून 21
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम ₁ (1.1 + 1.2.1+1.3)	37,102.8	31,891.3	35,735.8	35,700.6	35,496.5
एन एम ₂ (एन एम ₁ + 1.2.2.1)	89,108.8	79,849.7	88,279.5	88,514.5	88,122.8
एन एम ₃ (एन एम ₂ + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5)	156,452.1	142,310.9	156,077.8	156,560.3	156,015.6
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	20,522.3	18,767.6	21,173.7	21,322.2	21,166.8
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	131,831.8	119,472.8	131,041.5	131,446.1	130,980.3
1.2.1 मांग जमाराशियां	16,263.1	12,898.5	14,277.5	14,081.9	14,032.8
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	115,568.7	106,574.3	116,763.9	117,364.1	116,947.5
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	52,005.9	47,958.5	52,543.8	52,813.9	52,626.4
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	2,849.9	1,797.8	2,550.0	2,343.0	2,100.8
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	63,562.8	58,615.9	64,220.2	64,550.3	64,321.1
1.3 भारि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	317.4	225.2	284.5	296.5	296.8
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	3,780.5	3,845.3	3,578.1	3,495.6	3,571.6
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	156,561.0	142,746.0	157,242.9	158,551.7	157,390.7
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	43,877.9	42,210.0	46,044.1	47,027.0	45,891.1
2.1.1.1 सरकार को निवल भारि.बैं. ऋण	8,019.5	6,188.4	8,792.1	10,060.0	9,197.0
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	35,858.4	36,021.6	37,252.0	36,967.1	36,694.2
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	112,683.1	100,536.0	111,198.8	111,524.7	111,499.6
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भारि.बैंक ऋण	153.6	95.4	92.5	88.0	84.4
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	112,529.4	100,440.6	111,106.4	111,436.7	111,415.2
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	8,798.5	8,429.7	8,805.3	8,796.1	8,836.1
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	258.9	257.1	259.1	259.5	259.5
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	28,017.3	26,373.0	28,380.1	28,726.7	28,914.7
2.3.1 भारि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	28,485.9	27,597.3	29,143.0	29,266.8	29,598.1
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-468.6	-1,224.2	-762.9	-540.0	-683.4
2.4 पूंजी खाता	23,467.4	21,805.2	24,055.7	24,013.6	24,326.0
2.5 अन्य मदें (निवल)	4,917.6	5,260.1	5,748.6	6,964.1	6,223.4

सं. 9: कुल चलनिधि राशियां

(बिलियन ₹)

समुच्चय	2018-19	2018	2019		
		जून	अप्रैल	मई	जून
	1	2	3	4	5
1 एन एम₃	156,452.1	142,310.9	155,721.7	156,077.8	156,015.6
2 डाकघर जमाराशियां	3,672.9	3,161.5	3,672.9	3,672.9	3,672.9
3 एल₁ (1 + 2)	160,125.0	145,472.5	159,394.6	159,750.7	159,688.4
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3
4.1 सावधि मुद्रा उधार	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
4.3 सावधि जमाराशियां	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5 एल₂ (3 + 4)	160,154.3	145,501.8	159,423.9	159,780.0	159,717.8
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	319.1	319.1	319.1
7 एल₃ (5 + 6)	160,473.3	145,820.8	160,036.8

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018	2019		
		जून 22	मई 24	जून 7	जून 21
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	21,367.7	19,573.9	22,045.2	22,196.0	22,059.3
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	6,019.7	5,177.0	5,343.7	5,459.1	5,393.8
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	5,585.0	4,851.3	4,982.0	5,093.6	5,032.5
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	317.4	225.2	284.5	296.5	296.8
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	27,704.8	24,976.1	27,673.4	27,951.5	27,749.9
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	9,548.0	6,907.4	8,982.6	9,404.2	9,052.1
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	8,019.5	6,188.4	8,792.1	10,060.0	9,197.0
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	8,004.7	6,188.4	8,787.3	10,006.4	9,195.8
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	—	—	—	425.3	—
2.1.1.1.2 खजाना बिलों में निवेश	—	—	—	—	—
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	9,274.3	6,327.3	9,451.3	9,573.6	9,837.7
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	9,274.3	6,327.3	9,451.3	9,573.6	9,837.7
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	7.4	9.2	8.7	8.5	8.4
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	1,276.9	148.1	672.8	1.0	650.3
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	14.8	—	4.8	53.6	1.2
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	1,374.9	623.6	98.1	-743.8	-229.3
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	1,374.9	623.6	98.1	-744.1	-229.3
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	153.6	95.4	92.5	88.0	84.4
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	26.8	23.9	27.6	24.8	24.5
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	—	—	—	—	—
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	258.9	257.1	259.1	259.5	259.5
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	28,485.9	27,597.3	29,143.0	29,266.8	29,598.1
2.3.1 सोना	1,595.9	1,438.9	1,607.8	1,602.7	1,602.7
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	26,890.2	26,158.5	27,535.4	27,664.3	27,995.6
2.4 पूंजी खाता	9,702.7	9,261.0	9,752.0	9,701.4	9,834.9
2.5 अन्य मदें (निवल)	885.3	524.8	959.3	1,277.6	1,324.9

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया						
	2018-19	2018	2019				
		जून 22	मई 31	जून 7	जून 14	जून 21	जून 28
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	27,704.8	24,976.1	28,001.0	27,951.5	28,297.8	27,749.9	28,286.1
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	21,367.7	19,573.9	21,973.2	22,196.0	22,198.5	22,059.3	21,894.8
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	6,019.7	5,177.0	5,730.8	5,459.1	5,807.0	5,393.8	6,095.4
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	317.4	225.2	297.0	296.5	292.3	296.8	295.9
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	8,019.5	6,188.4	9,440.0	10,060.0	10,237.7	9,197.0	9,927.5
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	1,374.9	623.6	-90.2	-743.8	-560.8	-229.3	-471.0
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	153.6	95.4	89.9	88.0	86.2	84.4	87.6
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	28,485.9	27,597.3	29,351.1	29,266.8	29,277.4	29,598.1	29,396.7
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	258.9	257.1	259.5	259.5	259.5	259.5	259.5
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	10,588.0	9,785.8	11,049.3	10,979.0	11,002.3	11,159.8	10,914.1

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	माह के नियत अंतिम शुक्रवार / माह के नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018		2019	
			जून 22	मई 24	जून 7
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	124,088.4	111,963.2	123,284.4	123,685.5	123,207.6
1.1.1 मांग जमाराशियां	15,110.8	11,763.3	13,130.9	12,935.3	12,888.4
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	108,977.5	100,199.9	110,153.5	110,750.3	110,319.2
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	49,039.9	45,090.0	49,569.1	49,837.6	49,643.6
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	2,849.9	1,797.8	2,550.0	2,343.0	2,100.8
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	59,937.6	55,109.9	60,584.5	60,912.6	60,675.6
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधायन	3,780.5	3,845.3	3,578.1	3,495.6	3,571.6
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	140,289.7	128,532.0	140,249.7	140,274.4	139,982.8
2.1.1 सरकार को ऋण	33,783.0	33,955.1	35,199.7	34,910.9	34,646.3
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	106,506.7	94,576.9	105,050.0	105,363.5	105,336.5
2.1.2.1 बैंक ऋण	97,691.9	86,144.2	96,215.5	96,519.0	96,487.3
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	97,275.8	85,518.8	95,558.3	95,743.0	95,773.1
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	85.4	82.1	99.6	117.4	82.6
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	20.5	10.6	19.3	20.7	20.1
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	8,708.9	8,340.0	8,715.6	8,706.5	8,746.5
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	-468.6	-1,224.2	-762.9	-540.0	-683.4
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	2,623.8	1,532.3	2,408.2	2,544.5	2,457.9
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	1,637.2	1,566.7	1,711.1	1,717.1	1,717.2
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	1,455.3	1,189.9	1,460.0	1,367.4	1,424.0
2.3 निवल बैंक रिजर्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	5,380.8	4,935.4	5,658.0	6,614.2	6,056.3
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	5,657.1	4,851.3	4,982.0	5,093.6	5,032.5
2.3.2 उपलब्ध नकदी	748.5	707.7	774.2	776.5	794.5
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	1,024.8	623.6	98.1	-744.1	-229.3
2.4 पूंजी खाता	13,523.1	12,302.5	14,061.9	14,070.5	14,249.4
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	3,809.9	4,132.2	4,220.4	5,097.0	4,327.1
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	3,979.8	3,586.5	3,384.0	3,921.4	3,478.8
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	-484.5	-357.8	-579.0	-475.7	-501.9

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(बिलियन ₹)

मद	29 मार्च, 2019 की स्थिति	2018	2019		
		जून 22	मई 24	जून 7	जून 21
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	33,810.6	33,965.6	35,219.0	34,931.6	34,666.5
2 वाणिज्यिक पत्र	903.6	1,274.2	907.5	872.6	972.4
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	115.4	118.4	116.9	115.7	115.8
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	695.9	743.0	695.3	693.9	692.4
3.3 अन्य	63.8	42.8	55.9	56.2	56.2
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	1,348.2	1,293.8	1,309.4	1,265.8	1,264.2
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	2,687.8	2,213.0	2,536.2	2,572.4	2,574.9
4.3 अन्य	1,700.5	1,130.4	1,673.9	1,647.1	1,604.7
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	209.9	715.4	489.1	557.4	556.3
5.2 वित्तीय संस्थाएं	983.8	809.5	933.8	925.3	909.6

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / नियत शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2018-19	2018	2019		2018-19	2018	2019	
		जून	मई	जून		जून	मई	जून
1	2	3	4	5	6	7	8	
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	222	223	213	215	147	149	138	139
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	2,763.5	2,254.4	2,565.2	2,611.3	2,714.3	2,207.1	2,517.4	2,560.5
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमा राशियां	1,816.5	1,570.9	1,760.4	1,848.6	1,768.3	1,526.3	1,713.9	1,800.8
1.2 बैंकों से उधार राशि	794.9	587.8	699.7	648.8	794.6	586.9	699.7	647.2
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	152.1	95.7	105.0	113.9	151.4	94.0	103.8	112.5
2 अन्य के प्रति देयताएं	138,359.8	127,282.9	138,324.8	139,160.7	134,956.7	124,125.5	134,887.9	135,669.7
2.1 कुल जमा राशियां	129,015.8	117,986.7	129,421.9	130,259.7	125,737.7	114,982.2	126,129.1	126,907.7
2.1.1 मांग	15,425.5	12,919.8	13,753.1	14,347.8	15,112.9	12,632.6	13,452.5	14,033.4
2.1.2 मीयादी	113,590.3	105,066.9	115,668.9	115,911.9	110,624.8	102,349.6	112,676.6	112,874.3
2.2 उधार	3,818.6	4,006.4	3,561.3	3,609.0	3,782.5	3,946.3	3,523.8	3,574.7
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	5,525.3	5,289.7	5,341.5	5,292.0	5,436.5	5,197.0	5,235.0	5,187.3
3 रिजर्व बैंक से उधार	1,806.9	918.3	450.1	541.9	1,806.9	918.3	449.8	541.9
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2 अन्य	1,806.9	918.3	450.1	541.9	1,806.9	918.3	449.8	541.9
4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष	6,575.6	5,775.1	6,298.0	6,666.6	6,405.8	5,632.6	6,147.2	6,513.5
4.1 उपलब्ध नकदी	765.5	728.9	801.7	811.2	748.77	710.5	783.0	793.3
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेष	5,810.0	5,046.1	5,496.3	5,855.3	5,657.1	4,922.1	5,364.2	5,720.1
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	3,726.7	3,063.4	3,583.6	3,691.3	3,278.1	2,678.4	3,131.6	3,193.2
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	2,458.8	2,064.1	2,480.6	2,628.2	2,230.5	1,893.7	2,266.4	2,398.8
5.1.1 चालू खाते में	172.2	122.5	147.3	189.1	133.3	95.1	121.0	160.2
5.1.2 अन्य खातों में	2,286.6	1,941.7	2,333.3	2,439.2	2,097.2	1,798.5	2,145.4	2,238.7
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	470.5	339.7	335.2	327.3	322.5	175.1	202.0	165.6
5.3 बैंकों को अग्रिम	329.5	369.3	317.6	306.4	296.4	361.6	275.4	265.5
5.4 अन्य आस्तियां	467.9	290.3	450.1	429.4	428.8	248.0	387.9	363.3
6 निवेश	34,756.1	35,352.4	35,928.9	35,971.6	33,810.6	34,404.3	34,991.1	35,033.3
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	34,678.4	35,292.3	35,852.9	35,905.1	33,790.0	34,396.1	34,973.2	35,026.9
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	77.6	60.1	76.0	66.5	20.5	8.1	17.9	6.4
7 बैंक ऋण	100,471.2	89,289.1	99,739.7	99,860.7	97,717.2	86,728.1	96,884.0	97,010.2
7क खाद्यान्न ऋण	646.4	823.3	1,031.1	907.1	416.1	593.0	760.8	636.8
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	97,922.9	87,038.5	97,393.5	97,582.8	95,219.9	84,531.4	94,584.0	94,775.0
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	276.4	224.1	279.4	274.4	262.2	203.6	267.2	263.3
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	1,609.8	1,381.9	1,457.7	1,408.1	1,583.0	1,355.8	1,433.6	1,385.6
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	249.1	250.6	226.5	240.4	245.9	248.4	222.4	237.1
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	413.0	394.0	382.6	355.1	406.2	388.8	376.7	349.3

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(बिलियन ₹)

मद	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 29, 2019	2018	2019		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			जून 22	मई 24		
	1	2	3	4	5	6
1 सकल बैंक ऋण	86,749	76,949	85,167	85,476	-1.5	11.1
1.1 खाद्यान्न ऋण	415	624	655	712	71.6	14.2
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	86,334	76,325	84,512	84,764	-1.8	11.1
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	11,113	10,355	11,079	11,258	1.3	8.7
1.2.2 उद्योग	28,858	26,417	28,140	28,120	-2.6	6.4
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु	3,755	3,641	3,653	3,662	-2.5	0.6
1.2.2.2 मझौले	1,064	1,029	1,054	1,052	-1.2	2.2
1.2.2.3 बड़े	24,039	21,747	23,433	23,407	-2.6	7.6
1.2.3 सेवाएं	24,156	20,218	22,879	22,847	-5.4	13.0
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	1,385	1,223	1,416	1,417	2.3	15.8
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	185	183	184	183	-1.2	0.0
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	390	366	389	396	1.5	8.2
1.2.3.4 नौवहन	77	67	62	61	-21.5	-9.2
1.2.3.5 पेशेवर सेवाएं	1,715	1,536	1,708	1,687	-1.7	9.9
1.2.3.6 व्यापार	5,282	4,700	5,075	5,116	-3.1	8.9
1.2.3.6.1 थोक व्यापार	2,505	2,049	2,267	2,301	-8.2	12.3
1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार	2,776	2,651	2,808	2,815	1.4	6.2
1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	2,023	1,863	2,007	2,055	1.6	10.3
1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)	6,412	4,616	6,235	6,351	-1.0	37.6
1.2.3.9 अन्य सेवाएं	6,686	5,663	5,802	5,582	-16.5	-1.4
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	22,207	19,336	22,414	22,538	1.5	16.6
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	63	203	61	58	-8.4	-71.5
1.2.4.2 आवास	11,601	9,983	11,769	11,870	2.3	18.9
1.2.4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	829	679	665	671	-19.0	-1.2
1.2.4.4 शेयरों और बाडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	63	57	55	54	-14.3	-5.4
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	883	744	936	949	7.5	27.5
1.2.4.6 शिक्षा	680	686	674	676	-0.5	-1.5
1.2.4.7 वाहन ऋण	2,022	1,906	2,019	2,004	-0.9	5.1
1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण	6,068	5,078	6,235	6,256	3.1	23.2
1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	27,390	24,975	27,275	27,520	0.5	10.2
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	11,050	10,292	11,005	11,187	1.2	8.7
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम	10,672	9,572	10,623	10,628	-0.4	11.0
1.2अ.2.1 विनिर्माण	3,755	3,641	3,653	3,662	-2.5	0.6
1.2अ.2.2 सेवाएं	6,917	5,930	6,970	6,966	0.7	17.5
1.2अ.3 आवास	4,327	3,739	4,325	4,400	1.7	17.7
1.2अ.4 माइक्रो क्रेडिट	241	211	276	287	19.0	36.2
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	540	563	542	542	0.5	-3.7
1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं	4	3	4	4	-3.5	14.3
1.2अ.7 कमजोर वर्ग	6,626	5,765	6,794	7,015	5.9	21.7
1.2अ.8 निर्यात ऋण	156	223	144	143	-8.3	-36.1

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन

(बिलियन ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 29, 2019	2018	2019		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			जून 22	मई 24		
	1	2	3	4	5	6
1 उद्योग	28,858	26,417	28,140	28,120	-2.6	6.4
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	418	399	414	411	-1.5	3.0
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	1,571	1,498	1,517	1,516	-3.5	1.2
1.2.1 चीनी	297	276	296	296	-0.4	7.1
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	213	212	201	201	-5.8	-5.1
1.2.3 चाय	50	49	50	51	2.9	4.7
1.2.4 अन्य	1,010	961	970	968	-4.2	0.8
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	147	140	138	144	-2.0	2.7
1.4 वस्त्र	2,035	2,033	1,945	1,936	-4.9	-4.8
1.4.1 सूती वस्त्र	977	1,008	933	919	-5.9	-8.8
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	21	22	22	21	0.1	-1.9
1.4.3 मानव - निर्मित वस्त्र	267	239	257	260	-2.9	8.8
1.4.4 अन्य वस्त्र	770	764	733	735	-4.4	-3.8
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	111	111	111	112	0.7	0.5
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	120	111	116	117	-2.3	5.5
1.7 कागज और कागज से बने उत्पाद	303	304	301	301	-0.6	-0.9
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	631	640	526	558	-11.7	-12.8
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	1,915	1,571	1,760	1,745	-8.8	11.1
1.9.1 उर्वरक	400	272	340	331	-17.3	21.9
1.9.2 औषधि और दवाइयां	505	495	485	490	-2.9	-1.0
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	467	349	398	395	-15.5	13.3
1.9.4 अन्य	542	456	538	529	-2.4	16.1
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	458	415	458	458	0.1	10.3
1.11 कांच और कांच के सामान	99	90	99	98	-0.6	9.4
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	557	520	555	561	0.8	8.0
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	3,716	3,925	3,516	3,520	-5.3	-10.3
1.13.1 लोहा और स्टील	2,829	3,005	2,665	2,662	-5.9	-11.4
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	887	920	851	859	-3.2	-6.7
1.14 सभी अभियांत्रिकी	1,686	1,526	1,652	1,646	-2.4	7.9
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	379	337	374	379	0.2	12.7
1.14.2 अन्य	1,308	1,189	1,277	1,266	-3.2	6.5
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	799	748	788	814	2.0	8.8
1.16 रत्न और आभूषण	720	681	657	662	-8.0	-2.7
1.17 निर्माण	995	911	974	972	-2.3	6.7
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	10,559	8,912	10,419	10,265	-2.8	15.2
1.18.1 पावर	5,690	5,140	5,567	5,637	-0.9	9.7
1.18.2 दूरसंचार	1,156	883	1,239	1,068	-7.6	20.9
1.18.3 सड़क	1,869	1,624	1,863	1,861	-0.4	14.6
1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	1,845	1,265	1,750	1,698	-8.0	34.2
1.19 अन्य उद्योग	2,020	1,882	2,195	2,284	13.1	21.3

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2018-19	2018		2019					
		मई, 25	मार्च, 15	मार्च, 29	अप्रैल, 12	अप्रैल, 26	मई, 10	मई, 24	मई, 31
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	32	32	32	31	31	31	31	31
1 कुल जमा राशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	620.0	561.7	614.7	620.0	625.0	618.1	630.3	623.3	623.4
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	182.4	171.0	187.3	182.4	176.8	179.7	174.5	175.8	177.2
2.1.1 जमा राशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	58.4	48.8	55.4	58.4	46.6	52.6	47.4	47.7	48.7
2.1.1.2 अन्य	98.1	90.5	97.9	98.1	101.7	96.6	97.7	98.0	99.1
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	6.1	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	25.9	25.5	31.5	25.9	28.6	30.5	29.5	29.4	28.7
2.2 मीयादी देयताएं	985.3	905.4	963.9	985.3	1004.6	983.8	999.8	993.1	993.4
2.2.1 जमा राशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	456.6	424.7	437.6	456.6	474.4	455.7	460.4	461.2	462.5
2.2.1.2 अन्य	521.9	471.1	516.8	521.9	523.3	521.5	532.6	525.4	524.4
2.2.2 बैंकों से उधार	0.0	2.4	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	6.8	7.2	6.9	6.8	6.9	6.6	6.7	6.5	6.6
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	503.8	438.0	499.2	503.8	478.2	469.5	458.9	443.2	471.0
4.1 मांग	168.3	146.4	160.3	168.3	153.7	151.9	152.6	144.3	141.1
4.2 मीयादी	335.5	291.6	338.8	335.5	324.5	317.7	306.3	298.8	329.9
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	57.2	47.6	49.5	57.2	50.6	54.4	51.0	51.0	48.5
5.1 उपलब्ध नकदी	3.2	3.1	3.2	3.2	2.6	2.9	2.9	3.0	3.4
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	54.0	44.5	46.4	54.0	48.0	51.5	48.0	48.0	45.1
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	15.4	7.7	11.0	15.4	8.6	8.9	10.9	8.4	9.6
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	308.9	322.8	313.7	308.9	311.6	313.5	311.8	313.2	311.0
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	161.9	200.4	167.3	161.9	167.1	144.0	156.3	160.8	150.0
9 बैंक ऋण (10.1+11)	600.9	556.5	592.6	600.9	620.6	627.6	704.3	626.5	625.3
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	600.9	556.5	592.6	600.9	620.6	627.6	704.3	626.5	625.3
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	826.1	701.8	812.8	826.1	807.7	804.4	790.1	786.4	783.5
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2018-19			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	जून 18	मई 19	जून 19	जून 18	मई 19	जून 19	जून 18	मई 19	जून 19
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	139.5	138.4	139.1	140.0	139.2	141.0	138.4	143.8	145.5	139.4	140.9	142.7
1.1 अनाज और उत्पाद	137.7	137.2	137.5	137.6	137.4	137.8	135.3	140.4	140.7	136.9	138.3	138.7
1.2 मांस और मछली	149.5	147.5	148.8	148.1	159.5	163.5	149.7	156.7	159.5	148.7	158.5	162.1
1.3 अंडा	137.3	137.3	137.3	136.7	134.5	136.2	133.9	138.3	140.4	135.6	136.0	137.8
1.4 दूध और उत्पाद	142.7	141.3	142.2	143.2	142.6	143.2	140.8	142.4	143.3	142.3	142.5	143.2
1.5 तेल और चर्बी	124.0	117.6	121.6	124.0	124.0	124.3	116.6	118.6	118.6	121.3	122.0	122.2
1.6 फल	146.8	143.4	145.2	154.1	143.7	143.3	152.2	149.7	150.8	153.2	146.5	146.8
1.7 सब्जी	141.4	142.1	141.6	143.5	133.4	140.6	144.0	161.6	169.4	143.7	143.0	150.4
1.8 दाल और उत्पाद	124.1	115.3	121.1	126.0	125.1	128.7	112.3	124.4	127.4	121.4	124.9	128.3
1.9 चीनी और उत्पाद	111.9	110.8	111.5	112.4	109.3	110.6	108.4	111.2	111.8	111.1	109.9	111.0
1.10 मसाले	138.8	140.7	139.4	137.6	139.3	140.4	140.0	141.0	141.0	138.4	139.9	140.6
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	134.9	127.5	131.8	132.8	137.7	138.1	126.7	128.9	129.0	130.3	134.0	134.3
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	155.3	151.3	153.4	154.3	156.4	156.6	149.0	154.5	155.1	151.8	155.5	155.9
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	159.4	162.9	160.4	157.3	163.3	164.2	161.0	166.2	166.6	158.3	164.1	164.8
3 कपड़ा और जूते	150.3	139.3	145.9	150.3	150.7	150.7	137.4	142.2	142.3	145.2	147.3	147.4
3.1 कपड़ा	151.2	141.0	147.2	151.3	151.3	151.4	138.9	144.0	144.2	146.4	148.4	148.6
3.2 जूते	145.2	129.5	138.7	144.7	146.6	146.4	128.7	131.7	131.7	138.1	140.4	140.3
4 आवास	--	145.6	145.6	--	--	--	142.5	150.1	149.4	142.5	150.1	149.4
5 ईंधन और लाइट	147.0	129.3	140.3	145.1	146.9	147.9	126.5	129.4	130.5	138.1	140.3	141.3
6 विविध	138.6	131.1	134.9	135.6	142.9	143.3	129.5	133.3	133.5	132.6	138.2	138.5
6.1 घरेलू सामान और सेवा	145.9	134.8	140.6	142.2	149.5	149.6	133.1	137.2	137.4	137.9	143.7	143.8
6.2 स्वास्थ्य	143.5	135.5	140.5	138.4	151.3	151.7	132.6	139.8	140.3	136.2	146.9	147.4
6.3 परिवहन और संचार	128.5	120.3	124.2	127.4	130.2	130.2	120.4	120.1	119.6	123.7	124.9	124.6
6.4 मनोरंजन	140.4	130.3	134.7	137.8	145.9	146.4	128.5	134.0	134.2	132.6	139.2	139.5
6.5 शिक्षा	149.4	144.5	146.5	145.1	156.7	157.7	141.2	148.0	148.8	142.8	151.6	152.5
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	132.6	129.9	131.5	131.4	133.9	134.8	128.2	132.6	133.6	130.1	133.4	134.3
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	141.3	137.7	139.6	140.5	142.4	143.6	136.2	141.5	142.1	138.5	142.0	142.9

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2018-19	2019		
				जून	मई	जून
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2001	4.63	300	291	314	316
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	907	894	940	950
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	915	902	948	957

स्रोत : श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2018-19	2018	2019	
			जून	मई
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	31,193	30,707	31,738	33,121
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	38,404	39,907	36,590	37,187

स्रोत : मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि. मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2018-19	2018		2019	
			जून	अप्रैल	मई (अ)	जून (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	100.000	119.8	119.1	121.1	121.2	121.5
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	134.2	132.5	139.3	139.5	141.4
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	143.7	141.8	148.8	150.1	151.7
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+दाल)	3.462	146.7	141.0	153.5	154.3	155.4
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	147.3	145.9	158.5	161.5	166.8
1.1.1.3 दूध	4.440	143.1	142.5	143.2	143.4	143.8
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	138.0	138.2	142.9	144.3	146.0
1.1.1.5 मसाले	0.529	129.6	129.6	127.4	132.3	133.9
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	144.4	142.2	149.6	148.5	144.2
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	123.1	122.5	127.7	127.8	128.7
1.1.2.1 फाइबर	0.839	127.0	127.3	133.4	134.2	133.9
1.1.2.2 तिलहन	1.115	140.5	137.3	147.8	147.8	150.0
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	107.3	110.6	102.8	103.6	106.1
1.1.2.4 फूल	0.204	164.1	136.1	234.2	225.1	208.3
1.1.3 खनिज	0.833	136.5	123.2	158.0	138.0	158.0
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	123.0	105.6	153.7	124.9	153.7
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	183.5	184.6	173.0	183.7	173.0
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	2.410	92.4	94.1	92.7	92.8	92.5
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	104.1	104.4	102.8	103.4	102.1
1.2.1 कोल	2.138	123.3	123.0	123.6	123.6	124.0
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	132.9	132.0	133.9	133.9	133.9
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	120.3	120.0	121.2	121.2	129.9
1.2.2 खनिज तेल	7.950	96.7	97.3	95.4	96.4	94.3
1.2.3 बिजली	3.064	109.6	109.6	107.3	107.3	107.3
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	117.9	117.3	118.5	118.4	118.4
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	128.6	128.5	129.4	129.2	130.4
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	136.7	137.6	135.6	135.6	140.5
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	132.1	124.4	133.6	134.3	132.9
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	114.3	116.1	112.2	113.8	115.6
1.3.1.4 सब्जियाँ और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	117.6	120.6	113.9	113.2	112.5
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	136.2	138.3	135.1	135.9	139.9
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	141.6	137.8	143.4	143.3	145.0
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	116.6	110.1	133.3	135.6	135.8
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	129.3	127.9	131.3	131.3	130.9
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	111.2	110.5	112.9	115.0	114.5
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	126.7	125.2	128.2	127.8	128.2
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	134.5	131.5	133.1	137.8	133.7
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	137.7	144.8	146.2	139.0	145.5
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	122.2	121.3	125.3	126.3	124.7
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	127.0	128.8	128.3	128.3	126.6
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	143.6	138.9	158.7	156.9	154.5
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	157.5	153.4	165.3	163.7	172.3
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	120.7	119.3	122.7	122.5	123.3
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	113.8	112.1	115.6	115.6	116.5
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	120.5	119.4	122.6	123.4	124.2
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	131.2	129.9	133.3	132.0	132.5
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	0.514	150.4	150.8	153.2	152.1	155.1
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	150.4	150.8	153.2	152.1	155.1
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	117.9	116.2	119.4	119.7	119.3
1.3.4.1 धागों की कटाई और वस्त्र तैयार करना	2.582	110.6	109.0	111.7	111.2	110.7
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	127.3	125.3	130.3	130.9	130.6
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	112.9	112.2	111.6	114.4	115.2
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	130.3	126.5	132.2	134.8	134.8
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	138.7	137.6	139.4	139.7	139.8
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	118.3	117.6	115.7	116.6	117.3
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	0.814	138.8	139.7	139.0	139.2	138.7
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	139.4	140.5	140.2	140.5	139.6
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेट वस्त्र	0.221	137.0	137.7	135.5	136.0	136.3

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारत	2018-19	2018		2019	
			जून	अप्रैल	मई (अ)	जून (अ)
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	0.535	121.8	123.1	120.6	119.7	119.2
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगाई	0.142	111.0	117.0	108.4	106.0	106.0
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	134.7	134.2	135.3	135.6	136.3
1.3.6.3 जुते चप्पल	0.318	123.5	123.1	122.5	122.0	121.1
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और काँक के उत्पाद	0.772	133.5	132.7	133.6	134.3	134.6
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	124.5	123.4	125.6	126.5	126.6
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॉमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पैनल और बोर्ड	0.493	136.3	134.6	135.3	135.4	134.9
1.3.7.3 बिल्डरों की बड़ईगीरी	0.036	158.7	158.3	173.9	174.6	175.5
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	124.1	126.7	123.3	126.0	129.2
1.3.8 कागज और कागज के उत्पाद का विनिर्माण	1.113	123.3	121.3	123.9	123.5	122.7
1.3.8.1 लुगदी, कागज और कागज बोर्ड	0.493	129.3	126.4	129.5	128.9	127.9
1.3.8.2 लहरदार कागज और पेपर बोर्ड और कागज के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	116.5	115.1	116.2	115.7	114.7
1.3.8.3 कागज की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	120.6	119.3	122.9	122.9	122.6
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	146.6	147.0	150.1	148.3	148.6
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	146.6	147.0	150.1	148.3	148.6
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	6.465	119.1	117.6	119.9	119.7	119.3
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	125.0	123.1	125.4	124.9	124.1
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	121.1	118.7	122.9	123.1	123.3
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	117.6	117.7	116.9	115.5	114.3
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रीकेमिकल उत्पाद	0.454	120.2	117.9	123.0	124.2	123.9
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	112.7	111.8	116.2	115.2	115.6
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	116.8	114.7	120.0	119.6	120.2
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	116.6	115.9	115.6	115.8	115.2
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	104.0	104.0	100.7	101.0	100.4
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	123.5	122.2	125.1	125.5	125.5
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	123.5	122.2	125.1	125.5	125.5
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	2.299	109.6	108.9	109.7	109.2	109.1
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	98.9	97.2	100.2	99.5	99.3
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	91.7	90.5	92.5	92.5	93.1
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	117.6	117.5	117.1	116.6	116.3
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	115.9	115.2	117.4	118.4	118.2
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	121.4	119.1	125.4	126.0	125.5
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	111.1	112.1	108.0	107.7	109.5
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	98.0	95.2	102.2	101.4	100.5
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	112.7	112.5	114.5	114.5	114.5
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	114.3	113.5	119.9	122.0	121.7
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	121.5	121.5	121.8	120.8	120.6
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	118.8	118.0	120.5	119.9	119.6
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	130.4	131.2	94.4	95.2	94.6
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	112.2	112.9	110.5	109.7	108.7
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	113.0	112.9	106.2	105.7	105.4
1.3.14.2 मेटलिक आयरन	0.653	117.8	118.6	115.5	114.0	113.7
1.3.14.3 नरम इस्पात - अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	99.5	100.8	98.0	96.7	96.0
1.3.14.4 नरम इस्पात - लंबे उत्पाद	1.081	110.2	110.8	110.1	109.4	108.7
1.3.14.5 नरम इस्पात - चपटे उत्पाद	1.144	119.6	120.6	116.0	115.3	113.7
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	111.7	111.3	110.6	109.5	108.5
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	112.7	116.9	109.9	109.7	106.6
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	126.6	126.5	127.1	127.1	128.2
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	112.2	114.7	110.1	109.2	107.9
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	109.8	107.6	113.1	111.5	110.9
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	126.8	115.3	140.5	141.6	142.8
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	115.1	114.1	116.8	116.9	116.4
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	112.8	110.6	115.6	115.3	114.5
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	127.3	128.3	126.7	126.3	126.4
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरस को छोड़कर	0.145	105.9	108.5	102.7	102.6	102.6
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैमिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	96.3	95.9	101.6	102.3	101.6
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	99.7	99.9	99.9	100.1	100.2
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	123.1	120.8	125.3	126.1	125.2
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	111.8	111.2	111.4	111.4	111.4
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	100.9	100.4	98.0	98.7	98.3
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	132.5	127.3	135.1	135.0	135.0

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारत	2018-19	2018	2019			
		1	2	जून	अप्रैल	मई (अ)	जून (अ)
				3	4	5	6
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	116.7	117.4	116.6	116.6	116.7	
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	103.8	104.6	101.9	102.0	102.2	
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	109.1	109.2	111.9	111.9	112.1	
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	137.9	137.4	139.7	136.6	136.6	
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	103.2	103.7	105.3	105.3	103.6	
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	108.7	111.8	109.2	109.2	109.3	
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	2.930	111.7	111.8	112.7	112.0	111.9	
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	107.7	107.4	111.0	109.6	109.6	
1.3.17.2 बैटरी और एवयुम्युलेटर	0.236	117.7	118.0	117.6	117.5	117.6	
1.3.17.3 डेटा संवर्णन या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	126.1	127.3	119.0	118.0	117.2	
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	111.2	111.9	110.2	110.2	108.6	
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	108.6	108.2	110.3	110.0	111.4	
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	121.6	122.9	120.4	120.4	120.4	
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	108.6	107.6	108.9	108.5	109.3	
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	111.3	110.5	112.5	112.7	113.1	
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	103.0	102.1	105.0	105.5	105.4	
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	118.2	117.4	119.5	119.3	119.4	
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	108.9	109.1	110.1	110.2	110.4	
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	111.2	111.7	110.1	109.9	109.8	
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर भट्टियां	0.008	78.2	79.3	77.9	79.3	79.3	
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने - उतारने वाले उपकरण	0.285	110.4	109.5	111.8	111.9	111.7	
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2	
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	129.6	130.2	128.4	128.6	131.2	
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	116.9	114.6	119.3	119.2	119.7	
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	101.8	97.5	104.9	107.2	107.4	
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.7	74.1	76.9	76.8	76.7	
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	124.7	124.1	123.1	123.9	125.4	
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	119.9	121.8	122.1	121.8	121.8	
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	123.8	123.4	125.6	125.8	126.0	
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	67.3	67.2	66.6	66.6	66.6	
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	4.969	112.8	111.7	113.2	113.3	114.1	
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	113.3	112.5	113.6	113.7	114.6	
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	112.2	111.0	112.8	112.9	113.6	
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	111.7	110.6	114.2	114.8	116.9	
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली - वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.8	158.8	158.8	
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	104.7	105.2	106.2	106.2	106.2	
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	106.6	105.4	109.4	110.3	113.0	
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	127.8	125.2	130.5	128.7	128.8	
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	123.5	121.3	124.7	125.0	125.1	
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	127.3	124.6	128.4	129.4	128.4	
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	127.3	124.6	128.4	129.4	128.4	
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	107.0	106.9	106.5	106.3	106.2	
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	103.9	103.8	103.3	103.1	103.0	
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	174.1	173.7	170.4	173.0	177.2	
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	127.4	126.2	127.7	127.0	127.8	
1.3.22.4 खेल और खिलाड़ियों	0.005	132.2	129.2	138.9	136.1	137.4	
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	159.2	160.4	160.9	160.9	161.1	
2 खाद्य सूचकांक	24.378	138.1	136.8	141.5	142.3	143.7	

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारत	2017-18	2018-19	अप्रैल-मई		मई	
				2018-19	2019-20	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	125.3	129.8	126.1	130.8	129.6	133.6
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	104.9	107.9	105.1	109.4	107.6	111.0
1.2 विनिर्माण	77.63	126.6	131.1	126.6	130.7	130.1	133.3
1.3 बिजली	7.99	149.2	156.9	159.2	169.9	164.7	176.9
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	121.8	126.1	124.4	129.0	129.0	132.2
2.2 पूंजीगत माल	8.22	105.6	108.5	101.9	102.9	106.1	106.9
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	125.1	124.5	121.8	123.3	123.4	124.2
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	132.0	141.9	138.4	147.2	140.8	148.6
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	123.6	130.4	129.0	130.3	133.5	133.4
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	139.9	145.4	135.7	145.0	138.6	149.3

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी खाते और खजाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल - जून			
	2019-20 (बजट अनुमान)	2019-20 (वर्तमान)	2018-19 (वर्तमान)	बजट अनुमान का प्रतिशत	
				2019-20	2018-19
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्ति	19,627.6	2,848.9	2,677.7	14.5	15.5
1.1 कर राजस्व (निवल)	16,495.8	2,514.1	2,371.7	15.2	16.0
1.2 करेतर राजस्व	3,131.8	334.8	306.0	10.7	12.5
2 पूंजीगत प्राप्ति	1,198.3	47.6	108.4	4.0	11.8
2.1 ऋण की वसूली	148.3	24.1	20.8	16.2	17.1
2.2 अन्य प्राप्ति	1,050.0	23.6	87.6	2.2	11.0
2.3 उधारियां और अन्य देयताएं	20,825.9	2,896.5	2,786.1	13.9	15.3
3 कुल प्राप्ति (1+2)	24,477.8	6,587.1	6,206.6	26.9	29.0
4 राजस्व व्यय					
4.1 ब्याज भुगतान	6,604.7	1,417.6	1,449.2	21.5	25.2
5 पूंजी व्यय	3,385.7	630.0	869.9	18.6	29.0
6 कुल व्यय (4+5)	27,863.5	7,217.1	7,076.5	25.9	29.0
7 राजस्व घाटा (4-1)	4,850.2	3,738.2	3,528.9	77.1	84.8
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	7,037.6	4,320.6	4,290.3	61.4	68.7
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	432.9	2,903.0	2,841.2	670.6	586.0

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और यूनिनियन बजट 2018-19।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(बिलियन ₹)

मद	2018-19	2018		2019				
		जून 22	मई 24	मई 31	जून 7	जून 14	जून 21	जून 28
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	185.2	503.3	248.9	245.8	250.4	259.9	294.6	297.0
1.2 प्राथमिक व्यापारी	178.8	164.7	182.1	218.7	159.8	151.5	152.5	167.0
1.3 राज्य सरकारें	270.0	718.1	551.1	521.1	523.3	523.3	571.3	596.4
1.4 अन्य	277.5	376.4	609.6	627.0	730.6	779.4	793.1	825.2
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	319.5	290.2	409.7	419.1	419.9	436.6	468.5	463.2
2.2 प्राथमिक व्यापारी	387.4	401.0	554.5	556.2	561.5	558.1	563.5	595.4
2.3 राज्य सरकारें	280.4	327.9	209.2	209.2	209.2	140.1	87.9	62.8
2.4 अन्य	185.7	244.8	170.6	190.0	214.7	231.5	223.0	226.3
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	488.1	381.4	491.6	474.4	469.6	467.0	479.0	511.4
3.2 प्राथमिक व्यापारी	741.7	683.2	867.4	884.5	864.4	876.0	887.3	884.4
3.3 राज्य सरकारें	188.9	149.5	187.1	187.1	196.9	196.9	159.0	159.0
3.4 अन्य	623.9	510.5	489.8	493.2	516.8	508.0	487.1	458.1
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 प्राथमिक व्यापारी	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 राज्य सरकारें	1,656.1	1,307.4	1,436.5	1,309.1	947.4	792.4	1,322.4	1,219.6
4.4 अन्य	2.5	12.3	3.3	4.5	13.1	4.1	10.5	2.3
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	4,127.0	4,750.9	4,971.5	5,026.4	5,117.2	5,128.4	5,166.7	5,246.2

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं हैं। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि बिलियन ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां				स्वीकृत बोलियां				कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य						
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
91-दिवसीय खज़ाना बिल												
2019-20												
मई 29	90	77	963.80	30.02	22	89.98	30.02	120.00	98.48	6.1908		
जून 4	90	67	854.72	10.37	27	89.93	10.37	100.30	98.51	6.0668		
जून 12	90	59	524.99	11.25	16	89.95	11.25	101.20	98.54	5.9428		
जून 19	90	59	374.49	61.57	42	89.93	61.57	151.50	98.53	5.9841		
जून 26	90	62	450.12	35.06	46	89.94	35.06	125.00	98.52	6.0254		
182-दिवसीय खज़ाना बिल												
2019-20												
मई 29	70	56	194.05	0.00	24	70.00	0.00	70.00	96.97	6.2665		
जून 4	70	58	143.32	0.00	37	70.00	0.00	70.00	97.01	6.1812		
जून 12	70	56	131.86	0.01	41	69.99	0.01	70.00	97.04	6.1173		
जून 19	70	61	164.47	1.48	36	69.74	1.48	71.22	97.05	6.0960		
जून 26	70	52	152.70	0.00	27	70.00	0.00	70.00	97.02	6.1599		
364-दिवसीय खज़ाना बिल												
2019-20												
मई 29	40	53	155.70	0.09	14	39.91	0.09	40.00	94.09	6.2985		
जून 4	40	63	142.50	10.00	19	40.00	10.00	50.00	94.19	6.1853		
जून 12	40	52	111.33	0.02	31	39.98	0.02	40.00	94.24	6.1288		
जून 19	40	42	90.06	0.00	27	40.00	0.00	40.00	94.24	6.1288		
जून 26	40	56	119.46	0.00	24	40.00	0.00	40.00	94.21	6.1627		

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार		दरों का दायरा	भारित औसत दरें
		उधार लेना/उधार देना	उधार लेना/उधार देना
		1	2
जून	1, 2019	4.50-6.00	5.58
जून	3, 2019	4.50-6.00	5.85
जून	4, 2019	4.50-6.00	5.87
जून	6, 2019	4.40-6.00	5.85
जून	7, 2019	4.40-5.80	5.69
जून	10, 2019	4.40-5.80	5.69
जून	11, 2019	4.40-5.80	5.70
जून	12, 2019	4.40-5.80	5.69
जून	13, 2019	4.40-5.85	5.69
जून	14, 2019	4.40-6.12	5.81
जून	15, 2019	4.60-6.00	5.59
जून	17, 2019	4.40-5.90	5.78
जून	18, 2019	4.40-5.90	5.75
जून	19, 2019	4.40-5.91	5.80
जून	20, 2019	4.40-6.00	5.81
जून	21, 2019	4.40-5.90	5.78
जून	24, 2019	4.40-5.90	5.77
जून	25, 2019	4.40-6.00	5.76
जून	26, 2019	4.40-7.45	5.77
जून	27, 2019	4.40-6.02	5.73
जून	28, 2019	4.40-6.30	5.90
जून	29, 2019	4.50-6.05	5.79
जुलाई	1, 2019	4.40-5.90	5.74
जुलाई	2, 2019	4.40-6.05	5.71
जुलाई	3, 2019	4.40-5.90	5.65
जुलाई	4, 2019	4.40-5.90	5.67
जुलाई	5, 2019	4.40-5.80	5.53
जुलाई	6, 2019	4.50-5.80	5.52
जुलाई	8, 2019	4.40-5.90	5.65
जुलाई	9, 2019	4.40-5.85	5.62
जुलाई	10, 2019	4.40-5.85	5.62
जुलाई	11, 2019	4.40-5.90	5.58
जुलाई	12, 2019	4.40-5.85	5.63
जुलाई	15, 2019	4.40-5.80	5.59

टिप्पणी : नोटिस मुद्रा सहित।

सं. 27: जमा प्रमाणपत्र

मद	2018	2019			
	जून 22	मई 10	मई 24	जून 7	जून 21
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (बिलियन ₹)	1,745.0	2,494.8	2,271.5	2,186.7	2,159.4
1.1 परखवाड़े के दौरान जारी (बिलियन ₹)	212.0	66.2	139.4	191.6	280.7
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.80-8.50	7.30-8.60	6.72-7.90	6.35-8.00	5.97-6.96

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2018	2019			
	जून 30	मई 15	मई 31	जून 15	जून 30
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (बिलियन ₹)	4,918.3	5,837.2	5,519.8	5,561.8	5,039.4
1.1 परखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (बिलियन ₹)	1,267.3	1,059.7	1,024.5	1,078.7	1,076.9
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.16-11.19	6.81-13.04	6.43-10.08	5.87-13.97	5.79-11.89

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(बिलियन ₹)

मद	2018-19	2018	2019					
		जून 22	मई 24	मई 31	जून 7	जून 14	जून 21	जून 28
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	312.8	428.6	425.0	340.8	303.3	303.1	397.6	315.0
2 नोटिस मुद्रा	49.3	3.3	4.8	74.0	3.6	96.6	4.1	56.8
3 मीयादी मुद्रा	7.4	7.0	7.8	4.8	11.5	8.7	8.5	12.6
4 सीबीएलओ / त्रिपक्षीय रिपो	2,130.1	2,237.9	2,713.2	2,757.3	2,398.0	2,993.5	2,594.9	2,985.2
5 बाजार रिपो	2,009.7	2,491.1	1,985.5	2,334.4	2,024.2	2,698.7	2,067.8	2,551.9
6 कार्पोरेट बांड में रिपो		7.6	19.5	29.5	6.2	62.7	46.4	34.0
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67,793	62,202	64,867	65,606	65,574	60,894	64,690	77,216
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	658	623.9	908.2	1,091.7	1,565.5	1,061.6	1,780.7	1,301.3
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	43.2	29.5	58.0	98.9	85.0	95.1	80.4	45.7
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	33.8	44.9	37.4	28.2	24.4	57.0	51.7	49.9
10.2 182-दिवसीय	14.5	4.5	17.8	39.7	34.8	26.5	24.0	28.8
10.3 364-दिवसीय	16.2	9.0	29.4	41.4	63.2	29.2	17.1	28.3
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	14	13.2	-	-	-	-	-	-
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	779.7	725.0	1,050.8	1,300.0	1,773.0	1,269.3	1,954.0	1,454.0
11.1 भारतीय रिजर्व बैंक	-	20.1	2.8	2.7	3.6	41.8	27.9	0.2

टिप्पणी : मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) खंड को समाप्त किया गया तथा उसके स्थान पर 5 नवंबर 2018से त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि बिलियन ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2018-19		2018-19 (अप्रैल-जून)		2019-20 (अप्रैल-जून)*		जून 2018		जून 2019 *	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	129	167.5	44	52.6	25	528.0	10	26.9	9	5.7
1ए प्रीमियम	124	160.8	43	51.0	25	315.8	10	26.6	9	5.4
1.1 पब्लिक	119	146.1	42	51.1	20	34.1	10	26.9	8	5.6
1.1.1 प्रीमियम	115	141.2	41	49.5	20	33.2	10	26.6	8	5.4
1.2 राइट्स	10	21.5	2	1.5	5	493.9	—	—	1	0.1
1.2.1 प्रीमियम	9	19.6	2	1.5	5	282.6	—	—	1	0.1
2 अधिमान शेयर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 डिबेंचर	25	366.8	5	154.2	10	40.9	—	—	1	8.5
3.1 परिवर्तनीय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2 अपरिवर्तनीय	25	366.8	5	154.2	10	40.9	—	—	1	8.5
3.1.1 पब्लिक	25	366.8	5	154.2	10	40.9	—	—	1	8.5
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 कुल (1+2+3+4)	154	534.3	49	206.8	35	568.9	10	26.9	10	14.2
5.1 पब्लिक	144	512.8	47	205.3	30	75.0	10	26.9	9	14.1
5.2 राइट्स	10	21.5	2	1.5	5	493.9	—	—	1	0.1

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

टिप्पणी : अप्रैल 2018 से मासिक डाटा का समेकन निर्गम की समाप्ति की तारीख के आधार पर की जाती है जबकि पूर्व में समेकन का कार्य निर्गम चालू होने की तारीख के आधार पर किया जाता था।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2018-19	2018		2019			
		1	जून	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
			2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	बिलियन ₹	23,076.6	1,878.0	1,913.2	2,273.7	1,809.4	2,093.7	1,736.8
	अमेरिकी मिलियन डालर	330,069.6	27,702.0	26,862.1	32,725.2	26,061.5	30,008.0	25,012.3
1.1 तेल	बिलियन ₹	3,258.6	275.8	219.6	251.3	254.8	360.0	189.7
	अमेरिकी मिलियन डालर	46,544.4	4,069.0	3,083.4	3,616.9	3,669.9	5,159.4	2,732.4
1.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	19,818.0	1,602.2	1,693.6	2,022.4	1,554.6	1,733.8	1,547.1
	अमेरिकी मिलियन डालर	283,525.2	23,633.0	23,778.7	29,108.2	22,391.5	24,848.5	22,279.9
2 आयात	बिलियन ₹	35,943.7	3,003.5	2,606.1	3,035.6	2,874.3	3,164.5	2,797.7
	अमेरिकी मिलियन डालर	514,034.1	44,304.2	36,591.1	43,690.4	41,400.0	45,354.1	40,290.3
2.1 तेल	बिलियन ₹	9,862.6	862.7	670.5	818.5	794.3	868.2	765.9
	अमेरिकी मिलियन डालर	140,918.4	12,725.6	9,414.0	11,780.2	11,440.7	12,443.5	11,029.4
2.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	26,081.1	2,140.8	1,935.6	2,217.1	2,080.0	2,296.3	2,031.8
	अमेरिकी मिलियन डालर	373,115.6	31,578.6	27,177.1	31,910.2	29,959.2	32,910.6	29,260.9
3 व्यापार शेष	बिलियन ₹	-12,867.1	-1,125.5	-692.9	-761.9	-1,064.9	-1,070.8	-1,060.9
	अमेरिकी मिलियन डालर	-183,964.5	-16,602.2	-9,729.1	-10,965.3	-15,338.5	-15,346.2	-15,278.0
3.1 तेल	बिलियन ₹	-6,604.0	-586.9	-450.9	-567.2	-539.5	-508.2	-576.1
	अमेरिकी मिलियन डालर	-94,374.0	-8,656.6	-6,330.6	-8,163.3	-7,770.8	-7,284.1	-8,297.0
3.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	-6,263.1	-538.7	-242.0	-194.7	-525.4	-562.5	-484.7
	अमेरिकी मिलियन डालर	-89,590.5	-7,945.6	-3,398.4	-2,802.0	-7,567.7	-8,062.1	-6,981.0

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2018	2019						
		1	जून 20	जून 14	जून 21	जून 28	जुलाई 5	जुलाई 12	जुलाई 19
			2	3	4	5	6	7	
1 कुल भंडार	बिलियन ₹	27,873	29,376	29,697	29,495	29,471	29,450	29,636	
	अमेरिकी मिलियन डालर	405,143	422,200	426,416	427,679	429,911	428,798	430,376	
1.1 विदेशी मुद्रा आरिक्तियां	बिलियन ₹	26,151	27,440	27,760	27,561	27,467	27,446	27,618	
	अमेरिकी मिलियन डालर	380,050	394,447	398,649	399,902	400,809	399,698	401,091	
1.2 स्वर्ण	बिलियन ₹	1,450	1,603	1,603	1,603	1,675	1,675	1,675	
	अमेरिकी मिलियन डालर	21,140	22,959	22,959	22,959	24,305	24,305	24,305	
1.3 एसडीआर	बिलियन ₹	102	101	101	100	100	100	100	
	अमेरिकी मिलियन डालर	1,480	1,449	1,453	1,456	1,452	1,450	1,447	
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	बिलियन ₹	170	233	234	232	230	229	243	
	अमेरिकी मिलियन डालर	2,474	3,345	3,355	3,362	3,347	3,345	3,534	

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(अमेरिकी मिलियन डालर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2018-19	2018	2019		2018-19	2019-20
		जून	मई	जून	अप्रैल-जून	अप्रैल-जून
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	130,423	124,256	131,937	133,692	3,512	2,859
1.1 एफसीएनआर (बी)	23,170	22,568	24,318	24,364	543	1,194
1.2 एनआर (ई) आरए	92,017	87,836	92,193	93,405	2,501	1,040
1.3 एनआरओ	15,236	13,852	15,425	15,922	468	624

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(अमेरिकी मिलियन डालर)

मद	2018-19	2018-19	2019-20	2018	2019	
		अप्रैल-जून	अप्रैल-जून	जून	मई	जून
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	30,712	9,572	14,491	1,645	3,034	7,001
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	43,302	13,126	17,332	3,015	4,199	7,845
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	62,001	16,960	21,310	4,293	5,076	9,198
1.1.1.1.1 ईक्विटी	45,055	12,914	16,492	2,945	3,850	7,336
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	2,429	1,541	2,715	236	208	2,444
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	36,315	10,038	12,192	1,972	2,979	4,628
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	5,622	1,173	1,422	683	608	210
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	689	163	163	54	54	54
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	13,672	3,228	3,228	1,076	1,076	1,076
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	3,274	817	1,590	272	150	785
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	18,699	3,834	3,979	1,278	876	1,353
1.1.1.2.1 ईक्विटी	18,452	3,821	3,959	1,274	875	1,341
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	247	12	19	4	1	12
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	12,590	3,554	2,841	1,371	1,165	844
1.1.2.1 ईक्विटी पूंजी	7,201	2,326	1,220	912	535	371
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3,032	758	758	253	253	253
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5,202	745	1,248	298	522	347
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	2,845	276	384	92	145	127
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	-618	-8,145	3,938	-3,882	4,528	1,053
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	1,820	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	-2,225	-9,106	3,928	-4,202	2,295	1,658
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	213	-961	-10	-320	-2,233	605
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	30,094	1,427	18,429	-2,237	7,562	8,054

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(अमेरिकी मिलियन डालर)

मद	2018-19	2018	2019		
		जून	अप्रैल	मई	जून
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	13,787.6	1,030.6	1,287.9	1,486.1	1,407.5
1.1 जमाराशियां	455.9	25.8	65.2	50.2	37.4
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	84.5	7.7	8.5	9.4	3.9
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	422.9	25.2	35.4	31.6	28.6
1.4 उपहार	1,370.2	107.8	166.6	154.2	130.9
1.5 दान	8.7	0.6	0.5	2.8	0.9
1.6 यात्रा	4,803.8	380.5	429.8	568.3	595.9
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2,800.9	208.5	296.1	300.0	230.2
1.8 चिकित्सा उपचार	28.6	2.1	2.5	2.5	2.2
1.9 विदेश में शिक्षा	3,569.9	257.2	252.8	334.4	353.9
1.10 अन्य	242.2	15.2	30.5	32.7	23.5

**सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और
सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)**

मद	2017-18	2018-19	2018	2019	
			जुलाई	जून	जुलाई
	1	2	3	4	5
36-मुद्रा निर्यात और व्यापार आधारित भारांक (आधार: 2004-05=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	76.94	72.64	73.68	74.23	74.68
1.2 रीर	119.71	114.01	115.84	116.22	116.93
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	78.89	74.18	75.11	75.75	76.28
2.2 रीर	121.94	116.32	118.07	118.71	119.54
6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक					
1 आधार : 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100					
1.1 नीर	67.91	63.07	64.03	64.45	65.12
1.2 रीर	129.19	121.70	123.37	124.59	125.08
2 आधार : 2017-18 (अप्रैल-मार्च) =100					
2.1 नीर	100.00	92.88	94.30	94.91	95.89
2.2 रीर	100.00	94.20	95.50	96.44	96.82

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार — पंजीकरण

(राशि अमेरिकी मिलियन डालर में)

मद	2018-19	2018	2019	
		जून	मई	जून
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	999	85	117	104
1.2 राशि	28,387	2,714	2,895	3,499
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	21	-	5	5
2.2 राशि	13,537	-	653	1,900
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1,020	85	122	109
3.2 राशि	41,924	2,714	3,548	5,399
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	5.20	5.10	5.40	4.80
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारत औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.20	1.35	1.35	1.59
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-15.00	0.30-11.00	0.00-11.50	0.00-9.53

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	जनवरी-मार्च 2018 (आं.सं)			जनवरी-मार्च 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	329,455	316,218	13,237	324,141	309,979	14,162
1 चालू खाता (1.1+1.2)	156,683	169,750	-13,066	165,160	169,807	-4,647
1.1 पण्य	82,218	123,841	-41,623	87,367	122,581	-35,214
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	74,466	45,909	28,557	77,792	47,226	30,567
1.2.1 सेवाएं	51,585	31,421	20,164	54,630	33,299	21,331
1.2.1.1 यात्रा	7,710	4,728	2,983	7,583	5,112	2,470
1.2.1.2 परिवहन	4,688	4,941	-253	5,154	5,436	-282
1.2.1.3 बीमा	638	370	268	720	603	117
1.2.1.4 जीएनआईई	179	305	-126	156	285	-129
1.2.1.5 विविध	38,370	21,076	17,293	41,018	21,863	19,155
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	19,906	1,345	18,561	21,439	1,571	19,868
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	9,936	9,433	503	10,290	11,109	-820
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1,686	1,171	515	1,111	618	494
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	600	263	337	760	336	424
1.2.2 अंतरण	18,100	1,887	16,213	17,972	1,812	16,160
1.2.2.1 आधिकारिक	30	219	-190	69	226	-157
1.2.2.2 निजी	18,070	1,668	16,402	17,903	1,587	16,317
1.2.3 आय	4,781	12,601	-7,820	5,190	12,115	-6,925
1.2.3.1 निवेश आय	3,651	11,984	-8,333	4,033	11,521	-7,488
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षति पूर्ति	1,129	617	513	1,157	593	564
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	171,492	146,468	25,024	158,982	139,740	19,241
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	85,777	77,094	8,683	93,816	77,960	15,856
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	13,840	7,432	6,408	16,654	10,235	6,420
2.1.1.1 भारत में	13,097	4,492	8,605	15,461	5,671	9,790
2.1.1.1.1 इक्विटी	9,096	4,458	4,638	11,058	5,636	5,422
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3,393	-	3,393	3,650	-	3,650
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	608	34	574	753	36	718
2.1.1.2 विदेश में	743	2,941	-2,198	1,193	4,563	-3,370
2.1.1.2.1 इक्विटी	743	1,263	-520	1,193	1,683	-489
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	713	-713	0	758	-758
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	964	-964	0	2,123	-2,123
2.1.2 सविभाग निवेश	71,937	69,661	2,276	77,162	67,726	9,436
2.1.2.1 भारत में	71,802	69,427	2,376	76,807	65,338	11,469
2.1.2.1.1 एफआईआई	71,802	69,427	2,376	76,807	65,338	11,469
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	58,274	56,148	2,126	58,600	50,602	7,998
2.1.2.1.1.2 ऋण	13,528	13,279	249	18,207	14,736	3,471
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	-	0
2.1.2.2 विदेश में	135	235	-100	355	2,388	-2,033
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	40,835	33,870	6,965	31,255	20,997	10,258
2.2.1 बाह्य सहायता	2,686	1,257	1,430	2,554	1,301	1,253
2.2.1.1 भारत द्वारा	14	31	-17	12	30	-18
2.2.1.2 भारत को	2,673	1,225	1,447	2,542	1,271	1,271
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	13,581	12,589	992	17,993	10,456	7,537
2.2.2.1 भारत द्वारा	6,134	6,098	36	7,291	7,000	292
2.2.2.2 भारत को	7,447	6,491	956	10,702	3,456	7,246
2.2.3 भारत को अल्पावधि	24,568	20,025	4,543	10,708	9,241	1,468
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	22,951	20,025	2,926	10,052	9,241	812
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	1,617	0	1,617	656	0	656
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	31,834	27,205	4,629	21,606	29,670	-8,064
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	31,751	27,205	4,547	20,599	29,668	-9,069
2.3.1.1 आस्तियां	7,132	10,960	-3,829	443	16,542	-16,099
2.3.1.2 देयताएं	24,620	16,244	8,375	20,156	13,127	7,029
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	20,068	15,432	4,636	14,974	11,563	3,411
2.3.2 अन्य	83	0	83	1,007	1	1,006
2.4 रुपया ऋण चुकौती	-	50	-50	-	7	-7
2.5 अन्य पूंजी	13,045	8,250	4,795	12,304	11,107	1,197
3 भूल-चूक	1,279	-	1,279	-	431	-431
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	13,237	-13,237	0	14,162	-14,162
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	13,237	-13,237	0	14,162	-14,162

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(बिलियन ₹)

मद	जनवरी-मार्च 2018 (आं.सं)			जनवरी-मार्च 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	21,198	20,347	852	22,845	21,847	998
1 चालू खाता (1.1+1.2)	10,082	10,922	-841	11,640	11,968	-328
1.1 पण्य	5,290	7,968	-2,678	6,157	8,639	-2,482
1.2 अदृश्य मर्चे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	4,791	2,954	1,837	5,483	3,328	2,154
1.2.1 सेवाएं	3,319	2,022	1,297	3,850	2,347	1,503
1.2.1.1 यात्रा	496	304	192	534	360	174
1.2.1.2 परिवहन	302	318	-16	363	383	-20
1.2.1.3 बीमा	41	24	17	51	42	8
1.2.1.4 जीएनआईई	12	20	-8	11	20	-9
1.2.1.5 विविध	2,469	1,356	1,113	2,891	1,541	1,350
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	1,281	87	1,194	1,511	111	1,400
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	639	607	32	725	783	-58
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	108	75	33	78	44	35
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	39	17	22	54	24	30
1.2.2 अंतरण	1,165	121	1,043	1,267	128	1,139
1.2.2.1 आधिकारिक	2	14	-12	5	16	-11
1.2.2.2 निजी	1,163	107	1,055	1,262	112	1,150
1.2.3 आय	308	811	-503	366	854	-488
1.2.3.1 निवेश आय	235	771	-536	284	812	-528
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	73	40	33	82	42	40
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	11,034	9,424	1,610	11,205	9,849	1,356
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	5,519	4,961	559	6,612	5,494	1,117
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	891	478	412	1,174	721	452
2.1.1.1 भारत में	843	289	554	1,090	400	690
2.1.1.1.1 इक्विटी	585	287	298	779	397	382
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	218	0	218	257	0	257
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	39	2	37	53	3	51
2.1.1.2 विदेश में	48	189	-141	84	322	-238
2.1.1.2.1 इक्विटी	48	81	-33	84	119	-34
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	46	-46	0	53	-53
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	62	-62	0	150	-150
2.1.2 संविभाग निवेश	4,629	4,482	146	5,438	4,773	665
2.1.2.1 भारत में	4,620	4,467	153	5,413	4,605	808
2.1.2.1.1 एफआईआई	4,620	4,467	153	5,413	4,605	808
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	3,750	3,613	137	4,130	3,566	564
2.1.2.1.1.2 ऋण	870	854	16	1,283	1,039	245
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	9	15	-6	25	168	-143
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	2,628	2,179	448	2,203	1,480	723
2.2.1 बाह्य सहायता	173	81	92	180	92	88
2.2.1.1 भारत द्वारा	1	2	-1	1	2	-1
2.2.1.2 भारत को	172	79	93	179	90	90
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	874	810	64	1,268	737	531
2.2.2.1 भारत द्वारा	395	392	2	514	493	21
2.2.2.2 भारत को	479	418	62	754	244	511
2.2.3 भारत को अल्पावधि	1,581	1,288	292	755	651	103
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	1,477	1,288	188	708	651	57
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	104	0	104	46	0	46
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	2,048	1,750	298	1,523	2,091	-568
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	2,043	1,750	293	1,452	2,091	-639
2.3.1.1 आस्तियां	459	705	-246	31	1,166	-1,135
2.3.1.2 देयताएं	1,584	1,045	539	1,421	925	495
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	1,291	993	298	1,055	815	240
2.3.2 अन्य	5	0	5	71	0	71
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	3	-3	0	0	-0
2.5 अन्य पूंजी	839	531	309	867	783	84
3 भूल-चूक	82	0	82	0	30	-30
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	852	-852	0	998	-998
4.1 आईएमएफ	-	-	-	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	0	852	-852	0	998	-998

सं. 40: बीपीएम6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(अमेरिकी मिलियन डालर)

मद	जनवरी-मार्च 2018 (आं.सं)			जनवरी-मार्च 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	156,683	169,730	-13,047	165,158	169,786	-4,628
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)	133,803	155,262	-21,459	141,998	155,880	-13,883
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	82,218	123,841	-41,623	87,367	122,581	-35,214
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	82,872	116,776	-33,904	86,579	114,412	-27,832
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	-655	0	-655	788	0	788
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	-	7,065	-7,065	-	8,170	-8,170
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	51,585	31,421	20,164	54,630	33,299	21,331
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	55	13	43	78	11	67
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	60	155	-95	41	358	-317
1.अ.ख.3 परिवहन	4,688	4,941	-253	5,154	5,436	-282
1.अ.ख.4 यात्रा	7,710	4,728	2,983	7,583	5,112	2,470
1.अ.ख.5 निर्माण	535	585	-50	747	625	122
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	638	370	268	720	603	117
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1,686	1,171	515	1,111	618	494
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	212	1,704	-1,492	120	1,826	-1,706
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	20,574	1,708	18,866	22,262	2,029	20,233
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	9,936	9,433	503	10,290	11,109	-820
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	480	616	-136	451	649	-198
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	179	305	-126	156	285	-129
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	4,830	5,691	-861	5,917	4,638	1,279
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	4,781	12,601	-7,820	5,190	12,115	-6,925
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1,129	617	513	1,157	593	564
1.आ.2 निवेश आय	2,844	11,841	-8,997	3,390	11,109	-7,719
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1,337	5,968	-4,631	1,411	4,708	-3,297
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	56	2,347	-2,292	71	2,435	-2,364
1.आ.2.3 अन्य निवेश	268	3,515	-3,247	354	3,951	-3,596
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	1,183	11	1,173	1,553	15	1,538
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	807	143	664	643	412	231
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	18,099	1,868	16,231	17,970	1,791	16,179
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	18,070	1,668	16,402	17,903	1,587	16,317
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	17,484	1,260	16,224	17,322	1,199	16,123
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	586	408	178	581	387	194
1.इ.2 सामान्य सरकार	29	200	-171	67	204	-138
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	62	105	-43	84	167	-83
2.1 अनुपादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	6	5	1	14	94	-81
2.2 पूँजी अंतरण	56	100	-44	70	72	-3
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	171,430	159,620	11,811	158,900	153,757	5,143
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	13,840	7,432	6,408	16,654	10,235	6,420
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	13,097	4,492	8,605	15,461	5,671	9,790
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	12,489	4,458	8,031	14,708	5,636	9,072
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	9,096	4,458	4,638	11,058	5,636	5,422
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3,393	-	3,393	3,650	-	3,650
3.1.अ.2 ऋण लिखत	608	34	574	753	36	718
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	608	34	574	753	36	718
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	743	2,941	-2,198	1,193	4,563	-3,370
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	743	1,976	-1,234	1,193	2,441	-1,247
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	743	1,263	-520	1,193	1,683	-489
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	-	713	-713	-	758	-758
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	964	-964	0	2,123	-2,123
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	-	964	-964	-	2,123	-2,123
3.2 संविभाग निवेश	71,937	69,661	2,276	77,162	67,726	9,436
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	71,802	69,427	2,376	76,807	65,338	11,469
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	58,274	56,148	2,126	58,600	50,602	7,998
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	13,528	13,279	249	18,207	14,736	3,471
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	135	235	-100	355	2,388	-2,033
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	5,010	5,114	-104	6,425	5,687	739
3.4 अन्य निवेश	80,643	64,175	16,468	58,659	55,948	2,711
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमा राशियां	20,151	15,432	4,719	15,981	11,564	4,417
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	83	0	83	1,007	1	1,006
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमा राशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमा राशियां)	20,068	15,432	4,636	14,974	11,563	3,411
3.4.2.3 सामान्य सरकार	-	-	-	-	-	-
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	27,951	25,618	2,333	26,172	29,862	-3,690
3.4.3अ भारत को ऋण	21,803	19,489	2,313	18,869	22,832	-3,963
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	6,148	6,129	19	7,303	7,030	273
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	41	951	-910	21	364	-344
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	24,568	20,025	4,543	10,708	9,241	1,468
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	7,933	2,149	5,784	5,777	4,917	860
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	-	-	-	-	-	-
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	13,237	-13,237	0	14,162	-14,162
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	-	-	-	-	-	-
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	13,237	-13,237	0	14,162	-14,162
4. कुल आस्तियां / देयताएं	171,430	159,620	11,811	158,900	153,757	5,143
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	76,692	68,882	7,810	81,302	67,117	14,184
4.2 ऋण लिखत	86,806	75,352	11,454	71,822	67,561	4,261
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	7,933	15,386	-7,453	5,777	19,079	-13,303
5. निवल भूल-चूक	1,279	-	1,279	-	431	-431

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(विलियन ₹)

मद	जनवरी-मार्च 2018 (आं.सं)			जनवरी-मार्च 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	10,082	10,921	-840	11,640	11,966	-326
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	8,609	9,990	-1,381	10,008	10,986	-978
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	5,290	7,968	-2,678	6,157	8,639	-2,482
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	5,332	7,514	-2,182	6,102	8,063	-1,962
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	-42	0	-42	56	0	56
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	455	-455	0	576	-576
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	3,319	2,022	1,297	3,850	2,347	1,503
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	4	1	3	6	1	5
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	4	10	-6	3	25	-22
1.अ.ख.3 परिवहन	302	318	-16	363	383	-20
1.अ.ख.4 यात्रा	496	304	192	534	360	174
1.अ.ख.5 निर्माण	34	38	-3	53	44	9
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	41	24	17	51	42	8
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	108	75	33	78	44	35
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए भौतिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	14	110	-96	8	129	-120
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	1,324	110	1,214	1,569	143	1,426
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	639	607	32	725	783	-58
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	31	40	-9	32	46	-14
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	12	20	-8	11	20	-9
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	311	366	-55	417	327	90
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	308	811	-503	366	854	-488
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	73	40	33	82	42	40
1.आ.2 निवेश आय	183	762	-579	239	783	-544
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	86	384	-298	99	332	-232
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	4	151	-147	5	172	-167
1.आ.2.3 अन्य निवेश	17	226	-209	25	278	-253
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	76	1	75	109	1	108
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	52	9	43	45	29	16
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	1,165	120	1,044	1,266	126	1,140
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्ततंत्र निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	1,163	107	1,055	1,262	112	1,150
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	1,125	81	1,044	1,221	85	1,136
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	38	26	11	41	27	14
1.इ.2 सामान्य सरकार	2	13	-11	5	14	-10
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	4	7	-3	6	12	-6
2.1 अनुत्पादित वित्ततंत्र आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	0	0	0	1	7	-6
2.2 पूँजी अंतरण	4	6	-3	5	5	-0
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	11,031	10,271	760	11,199	10,836	362
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	891	478	412	1,174	721	452
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	843	289	554	1,090	400	690
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	804	287	517	1,037	397	639
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	585	287	298	779	397	382
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	218	0	218	257	0	257
3.1.अ.2 ऋण लिखत	39	2	37	53	3	51
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	39	2	37	53	3	51
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	48	189	-141	84	322	-238
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	48	127	-79	84	172	-88
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	48	81	-33	84	119	-34
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	46	-46	0	53	-53
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	62	-62	0	150	-150
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	62	-62	0	150	-150
3.2 संविभाग निवेश	4,629	4,482	146	5,438	4,773	665
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	4,620	4,467	153	5,413	4,605	808
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	3,750	3,613	137	4,130	3,566	564
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	870	854	16	1,283	1,039	245
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	9	15	-6	25	168	-143
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	322	329	-7	453	401	52
3.4 अन्य निवेश	5,189	4,129	1,060	4,134	3,943	191
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमा राशियां	1,297	993	304	1,126	815	311
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	5	0	5	71	0	71
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमा राशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमा राशियां)	1,291	993	298	1,055	815	240
3.4.2.3 सामान्य सरकार	-	-	-	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	-	-	-	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	1,798	1,648	150	1,845	2,105	-260
3.4.3अ भारत को ऋण	1,403	1,254	149	1,330	1,609	-279
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	396	394	1	515	495	19
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	3	61	-59	1	26	-24
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	1,581	1,288	292	755	651	103
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	510	138	372	407	347	61
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	-	-	-	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	852	-852	0	998	-998
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	-	-	-	-	-	-
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	852	-852	0	998	-998
4. कुल आस्तियां / देयताएं	11,031	10,271	760	11,199	10,836	362
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	4,935	4,432	503	5,730	4,730	1,000
4.2 ऋण लिखत	5,585	4,848	737	5,062	4,762	300
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	510	990	-480	407	1,345	-938
5. निवल भूत-चूक	82	-	82	0	30	-30

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(अमेरिकी मिलियन डालर)

मद	वित्तीय वर्ष / समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2018-19		2018				2019	
			मार्च		दिसंबर		मार्च	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	169,964	399,199	157,373	378,957	166,594	386,203	169,964	399,199
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	111,122	382,105	103,734	363,190	109,875	369,544	111,122	382,105
1.2 अन्य पूंजी	58,841	17,094	53,640	15,767	56,719	16,659	58,841	17,094
2 संविभाग निवेश	4,699	260,009	3,577	272,151	2,666	245,849	4,699	260,009
2.1 इक्विटी	637	147,479	2,054	155,106	1,386	138,091	637	147,479
2.2 ऋण	4,062	112,530	1,524	117,045	1,280	107,759	4,062	112,530
3 अन्य निवेश	54,538	419,309	48,246	401,166	41,550	401,290	54,538	419,309
3.1 व्यापार ऋण	924	105,191	1,696	103,155	252	103,648	924	105,191
3.2 ऋण	9,884	168,143	8,235	159,820	6,553	160,454	9,884	168,143
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	25,158	130,644	20,790	126,456	17,211	125,997	25,158	130,644
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	18,574	15,332	17,524	11,736	17,534	11,190	18,574	15,332
4 रिज़र्व्स	412,871	–	424,545	–	395,591	–	412,871	–
5 कुल आस्तियां/देयताएं	642,072	1,078,518	633,741	1,052,275	606,401	1,033,342	642,072	1,078,518
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-436,446		-418,533		-426,942		-436,446

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

प्रणाली	मात्रा (मिलियन)				मूल्य (बिलियन ₹)			
	2018-19	2019			2018-19	2019		
		अप्रैल	मई	जून		अप्रैल	मई	जून
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 आरटीजीएस	136.63	11.48	12.49	11.83	1,715,520.61	148,481.20	158,379.63	152,991.31
1.1 ग्राहक लेनदेन	133.30	11.23	12.22	11.60	1,184,368.12	93,080.66	104,886.16	101,776.08
1.2 अंतरबैंक लेनदेन	3.31	0.25	0.26	0.22	172,513.75	19,372.66	19,087.66	18,241.35
1.3 अंतरबैंक समाशोधन	0.027	0.002	0.003	0.002	358,638.74	36,027.89	34,405.81	32,973.89
2 सीसीआईएल परिचालित प्रणाली	3.62	0.25	0.31	0.31	1,165,510.38	95,078.03	108,987.82	109,183.63
2.1 सीबीएलओ	0.130	—	—	—	181,404.63	—	—	—
2.2 सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	1.11	0.09	0.13	0.15	509,315.87	48,748.73	64,438.30	68,284.52
2.2.1 एकमुश्त	0.81	0.06	0.09	0.11	93,550.07	7,915.80	10,329.18	15,074.46
2.2.2 रिपो	0.216	0.016	0.022	0.020	271,249.89	16,857.34	24,166.31	24,412.04
2.3 विदेशी समाशोधन	0.09	0.02	0.02	0.02	144,515.90	23,975.59	29,942.82	28,798.02
3 पेपर समाशोधन	2.38	0.16	0.19	0.16	474,789.88	46,329.31	44,549.52	40,899.10
3.1 चेक ट्रंकेशन प्रणाली	1,123.76	89.79	92.11	83.96	82,460.65	7,268.12	7,170.78	6,357.98
3.2 एमआईसीआर समाशोधन	1,111.67	89.36	91.77	83.65	81,535.92	7,235.33	7,136.88	6,330.18
3.2.1 आरबीआई के केन्द्र	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2.2 अन्य केन्द्र	—	—	—	—	—	—	—	—
3.3 गैर-एमआईसीआर समाशोधन	—	—	—	—	—	—	—	—
4 खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन	12.09	0.44	0.34	0.32	924.73	32.79	33.91	27.81
4.1 ईसीएस नामे	7,113.25	731.85	683.81	643.65	258,745.44	23,801.05	24,834.16	20,580.81
4.2 ईसीएस जमा (एनईसीएस शामिल है)	0.93	0.03	0.03	0.03	12.60	0.09	0.09	0.09
4.3 ईएफटी/एनईएफटी	5.36	0.52	0.29	0.33	132.35	11.87	7.77	9.24
4.4 तुरंत भुगतान सेवाएं (आईएमपीएस)	2,318.89	203.44	217.68	199.14	227,936.08	20,546.69	21,277.74	17,496.45
4.5 राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	1,752.91	185.04	183.33	171.33	15,902.57	1,691.97	1,804.56	1,730.19
5 कार्ड	3,035.17	342.82	282.48	272.83	14,761.84	1,550.43	1,744.00	1,344.84
5.1 क्रेडिट कार्ड	16,046.26	1,384.27	1,397.34	1,355.80	45,121.45	3,974.05	4,139.95	3,969.21
5.1.1 एटीएम का प्रयोग	1,772.36	167.79	174.04	163.16	6,078.81	580.50	616.76	570.94
5.1.2 पीओएस का प्रयोग	9.77	0.86	0.89	0.79	45.33	4.02	4.17	3.80
5.2 डेबिट कार्ड	1,762.59	166.92	173.15	162.37	6,033.48	576.48	612.58	567.14
5.2.1 एटीएम का प्रयोग	14,273.90	1,216.48	1,223.30	1,192.64	39,042.64	3,393.55	3,523.19	3,398.27
5.2.2 पीओएस का प्रयोग	9,859.61	808.91	815.71	786.11	33,107.89	2,843.96	2,946.67	2,828.54
6 प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)	4,604.34	420.97	419.00	389.82	2,128.76	185.54	182.97	177.64
6.1 एम-वॉलेट	4,139.28	380.62	367.45	334.70	1,836.55	159.75	157.27	154.71
6.2 पीपीआई कार्ड	465.00	40.35	51.54	55.12	291.34	25.79	25.70	22.93
6.3 पेपर वाउचर	0.05	0.00	0.00	0.00	0.87	—	—	—
7 मोबाइल बैंकिंग	6,200.32	881.23	841.74	848.61	29,584.07	4,020.18	4,850.08	4,975.43
8 कार्ड बकाया	971.72	932.77	873.85	886.20	—	—	—	—
8.1 क्रेडिट कार्ड	47.09	48.00	48.92	49.31	—	—	—	—
8.2 डेबिट कार्ड	924.63	884.78	824.93	836.89	—	—	—	—
9 एटीएम की संख्या (वास्तव में)	221703	227164	227227	226757	—	—	—	—
10 पीओएस की संख्या (वास्तव में)	3722229	3757621	3845111	3991007	—	—	—	—
11 कुल जोड़ (1.1+1.2+2+3+4+5+6)	29,027.83	2,638.61	2,605.07	2,485.36	2,910,848.56	242,760.11	269,289.51	260,286.70

टिप्पणी : पिछले 12 माह अवधि का डाटा अनंतिम है।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

2.1: 5 नवंबर 2018 से सीसीआईएल ने सीबीएलओ को समाप्त कर दिया है।

2.2.3: 5 नवंबर 2018 से सिक्कुरिटीज सेगमेंट के अंतर्गत त्रिपक्षीय रिपो की शुरुआत की गई है।

अवसरिक श्रृंखलाएं

सं. 44: लघु बचत

(बिलियन ₹)

योजना		2017-18	2018		2019	
			फरवरी	दिसंबर	जनवरी	फरवरी
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	728.98	59.21	104.15	85.67	98.39
	बकाया	8,039.71	7,919.97	8,806.98	8,893.96	8,991.91
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	583.32	46.20	85.79	63.58	71.30
	बकाया	5,273.10	5,197.72	5,934.32	5,997.90	6,069.20
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	171.45	15.11	29.15	23.18	23.60
	बकाया	1,092.10	1,066.94	1,301.85	1,325.03	1,348.63
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	-1.62	-0.19	-0.30	-0.21	-0.19
	बकाया	31.38	30.32	29.17	28.96	28.77
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	0.05	-0.68	-0.01	0.04	0.00
	बकाया	-0.43	-0.46	-0.12	-0.08	-0.08
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	16.25	5.27	10.36	9.66	9.28
	बकाया	1,816.91	1,808.01	1,897.59	1,907.25	1,916.53
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	122.64	10.39	12.32	11.90	11.84
	बकाया	417.18	405.90	520.72	532.62	544.46
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	196.33	15.00	23.17	25.08	24.51
	बकाया	992.92	973.90	1,167.28	1,192.36	1,216.87
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	598.18	590.68	676.62	689.20	701.79
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	45.97	45.59	56.17	57.34	58.24
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	61.40	60.36	68.60	68.88	69.10
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	287.37	277.27	365.89	376.94	387.74
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	78.68	1.30	11.10	-6.07	2.15
	बकाया	923.20	913.57	1,017.99	1,011.92	1,014.07
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	-0.45	0.00	0.00	0.00	0.11
	बकाया	-0.37	-0.68	-0.37	-0.37	-0.26
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	79.43	7.90	15.00	16.23	17.32
	बकाया	2,066.76	2,059.53	2,158.15	2,175.69	2,192.57
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	-0.65	5.83	11.24	11.59	12.62
	बकाया	871.74	862.05	923.74	935.33	947.95
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	-9.56	-0.01	0.05	0.09	0.03
	बकाया	-0.71	11.04	2.88	2.97	3.00
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-155.92	-12.80	-18.95	-16.55	-16.09
	बकाया	379.81	388.77	244.96	228.41	212.32
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	245.88	14.89	22.59	20.95	20.65
	बकाया	706.12	687.83	871.54	892.49	913.14
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	-0.29	0.00	0.07	0.15	0.12
	बकाया	-1.40	-1.45	-0.74	-0.59	-0.47
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-0.03	-0.01	0.00	0.00	-0.01
	बकाया	-0.64	-0.64	-0.81	-0.81	-0.82
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	111.84	111.93	116.58	117.89	117.45
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	66.23	5.11	3.36	5.86	9.77
	बकाया	699.85	662.72	714.51	720.37	730.14

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों पर प्राप्त डाटा निवल प्राप्तियां अर्थात् सकल भुगतानों और सकल प्राप्तियों का अंतर हैं।

स्रोत : महालेखाकार, डाक और तार।

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2018				2019
	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर	मार्च
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ बिलियन में)	53967.78	54556.81	56028.30	57581.03	59210.26
1. वाणिज्यिक बैंक	42.68	41.84	41.41	40.51	40.28
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.29	0.33	0.37	0.33	0.31
3. बीमाकृत कंपनियां	23.49	24.24	24.61	24.57	24.34
4. म्यूच्युअल फंड	1.00	1.13	1.41	0.64	0.35
5. सहकारी बैंक	2.57	2.59	2.51	2.38	2.29
6. वित्तीय संस्थाएं	0.90	0.93	0.97	1.01	1.05
7. कॉरपोरेट	0.91	1.09	1.01	1.05	0.97
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	4.35	3.84	3.65	3.60	3.22
9. भविष्य निधियां	5.88	5.79	5.71	5.54	5.47
10. भारतीय रिजर्व बैंक	11.62	11.63	11.76	13.81	15.27
11. अन्य	6.30	6.58	6.58	6.55	6.46
11.1 राज्य सरकार	1.91	1.97	1.99	1.97	2.00

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2018				2019
	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर	मार्च
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ बिलियन में)	24288.29	24954.61	25668.33	26693.93	27772.29
1. वाणिज्यिक बैंक	35.79	35.02	34.66	34.00	33.87
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.51	0.75	0.58	0.60	0.58
3. बीमाकृत कंपनियां	34.13	34.24	33.74	33.90	33.04
4. म्यूच्युअल फंड	1.64	1.20	1.05	1.23	1.20
5. सहकारी बैंक	4.78	4.79	4.75	4.67	4.55
6. वित्तीय संस्थाएं	0.35	0.35	0.43	0.37	0.42
7. कॉरपोरेट	0.15	0.16	0.17	0.22	0.29
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.23	0.15	0.10	0.09	0.09
9. भविष्य निधियां	19.67	20.34	21.04	21.29	22.15
10. भारतीय रिजर्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	2.76	2.99	3.48	3.64	3.81
11.1 राज्य सरकार	0.05	0.06	0.07	0.07	0.11

खजाना बिल					
श्रेणी	2018				2019
	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर	मार्च
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ बिलियन में)	3798.76	5280.07	5657.50	5298.26	4127.04
1. वाणिज्यिक बैंक	60.74	55.30	47.84	53.76	57.56
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	2.17	1.41	1.86	2.06	2.68
3. बीमाकृत कंपनियां	4.17	3.66	4.55	4.74	6.61
4. म्यूच्युअल फंड	2.27	7.03	10.69	5.65	2.78
5. सहकारी बैंक	2.42	1.29	1.20	1.21	2.48
6. वित्तीय संस्थाएं	3.55	2.36	1.67	1.88	2.49
7. कॉरपोरेट	2.45	1.88	6.67	1.86	2.23
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
9. भविष्य निधियां	0.11	0.21	0.01	0.02	0.08
10. भारतीय रिजर्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	22.12	26.87	25.50	28.72	23.10
11.1 राज्य सरकार	16.35	23.11	21.36	24.04	17.91

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(बिलियन ₹)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सं.अ.)	2018-19 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	30,002.99	32,852.10	37,606.11	42,659.69	48,579.90	53,611.81
1.1 गतिविधियां	17,142.21	18,720.62	22,012.87	25,379.05	29,324.08	32,025.64
1.1.1 राजस्व	13,944.26	14,830.18	16,682.50	18,784.17	22,525.73	24,390.87
1.1.2 पूंजी	2,785.08	3,322.62	4,120.69	5,012.13	5,857.77	6,745.79
1.1.3 ऋण	412.88	567.82	1,209.68	1,582.75	940.58	888.98
1.2 गैर गतिविधियां	12,427.83	13,667.69	15,108.10	16,726.46	18,542.53	20,762.79
1.2.1 राजस्व	11,413.65	12,695.20	13,797.27	15,552.39	17,684.36	19,839.32
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	5,342.30	5,845.42	6,480.91	7,244.48	8,166.36	8,851.50
1.2.2 पूंजी	990.37	946.87	1,273.06	1,157.75	844.41	909.08
1.2.3 ऋण	23.81	25.63	37.77	16.32	13.76	14.40
1.3 अन्य	432.95	463.79	485.14	554.17	713.29	823.38
2. कुल प्राप्तियां	30,013.72	31,897.37	37,780.49	42,884.32	47,718.59	52,780.35
2.1 राजस्व प्राप्तियां	22,114.75	23,876.93	27,483.74	31,322.01	35,923.82	41,185.41
2.1.1 कर प्राप्तियां	18,465.45	20,207.28	22,971.01	26,221.45	30,132.23	34,941.02
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	11,257.81	12,123.48	14,409.52	16,523.77	18,296.56	22,138.76
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	7,176.34	8,051.76	8,522.71	9,656.22	11,802.47	12,775.14
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	31.30	32.04	38.78	41.46	33.20	27.12
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	3,649.30	3,669.65	4,512.72	5,100.56	5,791.59	6,244.38
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	401.62	396.22	357.79	332.20	316.10	368.35
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	391.13	609.55	598.27	690.63	1,651.83	1,428.43
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	93.85	220.72	165.61	209.42	648.80	616.50
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	297.28	388.83	432.66	481.22	1,003.03	811.93
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	7,497.11	8,365.63	9,524.10	10,647.04	11,004.25	10,997.97
अक वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
अक.1 घरेलू वित्तपोषण	7,424.19	8,236.30	9,396.62	10,467.08	10,980.08	11,023.86
अक.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	3,358.58	-374.76	2,310.90	6,171.23	1,447.92	..
अक.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	1,081.30	-3,341.85	604.72	1,958.16	-1,448.47	..
अक.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	4,065.61	8,611.06	7,085.72	4,295.85	9,532.16	..
अक.2 बाह्य वित्तपोषण	72.92	129.33	127.48	179.97	24.18	-25.89
अख वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
अख.1 घरेलू वित्तपोषण	7,424.19	8,236.30	9,396.62	10,467.08	10,980.08	11,023.86
अख.1.1 बाजार उधार (निवल)	6,391.99	6,640.58	6,732.98	6,898.21	7,951.99	8,398.36
अख.1.2 लघु बचत (निवल)	-142.81	-565.80	-785.15	-1,050.38	-1,653.29	-1,434.61
अख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	312.90	343.39	352.61	456.88	406.13	474.19
अख.1.4 आरक्षित निधियां	34.63	51.09	-33.22	-64.36	6.70	31.14
अख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	255.45	275.45	134.70	177.92	168.45	159.10
अख.1.6 नकद शेष	-10.72	954.74	-174.38	-224.63	861.31	831.46
अख.1.7 अन्य	582.75	536.84	3,169.08	4,273.43	3,238.79	2,564.21
अख.2 बाह्य वित्तपोषण	72.92	129.33	127.48	179.97	24.18	-25.89
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	26.7	26.3	27.3	27.8	28.4	28.1
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	26.7	25.6	27.4	27.9	27.9	27.7
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	19.7	19.2	20.0	20.4	21.0	21.6
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	16.4	16.2	16.7	17.1	17.6	18.3
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.7	6.7	6.9	6.9	6.4	5.8

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज।

...: उपलब्ध नहीं। आरई: संशोधित अनुमान; बीई: बजट अनुमान

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जून 2019 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	1.47	19	13.69	19	10.82	11
2	अरुणाचल प्रदेश	0.33	6	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	7.40	12	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	0.60	16	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	5.45	26	3.79	2
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	1.39	17	3.83	17	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	0.16	20	1.95	20	2.65	19
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिजोरम	-	-	-	-	-	-
19	नगालैंड	-	-	0.43	7	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	0.84	14	3.45	14	-	-
23	राजस्थान	5.37	4	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	6.47	23	7.75	14	6.34	8
26	त्रिपुरा	15.16	5	-	-	-	-
27	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	4.12	19	9.89	19	4.38	6

- टिप्पणी :**
- राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।
 - राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।
 - प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।
 - : नगण्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मई 2019 के दौरान			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	75.90	7.47	0.02	0
2	अरुणाचल प्रदेश	10.51	0.01	--	0
3	असम	38.60	0.47	--	40.00
4	बिहार	64.78	--	--	100.00
5	छत्तीसगढ़	39.28	--	0.01	60.00
6	गोवा	5.46	2.74	--	0
7	गुजरात	125.44	4.41	--	0
8	हरियाणा	19.11	10.98	--	0
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	0
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	0
11	झारखंड	--	--	--	0
12	कर्नाटक	35.47	--	--	65.00
13	केरल	19.72	--	--	0
14	मध्य प्रदेश	--	8.45	--	0
15	महाराष्ट्र	358.90	2.69	--	200.00
16	मणिपुर	3.46	0.92	--	0
17	मेघालय	5.62	0.28	0.09	0
18	मिज़ोरम	5.05	0.29	--	0
19	नगालैंड	13.64	0.29	--	0
20	उड़ीसा	122.92	13.26	0.77	183.95
21	पुदुचेरी	2.94	--	--	9.10
22	पंजाब	0.76	--	0.08	0
23	राजस्थान	--	--	1.29	0
24	तमिलनाडु	60.86	--	0.45	160.09
25	तेलंगाना	51.13	10.35	0.01	0
26	त्रिपुरा	3.02	0.05	--	0
27	उत्तरप्रदेश	--	--	1.80	0
28	उत्तराखंड	27.56	0.72	--	0
29	पश्चिम बंगाल	101.23	4.86	2.14	0
	कुल	1191.36	68.24	6.65	818.14

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य	2017-18		2018-19		2019-20						2019-20 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	अप्रैल		मई		जून		सकल	निवल
						सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	228.00	189.22	302.00	238.24	50.00	34.84	20.00	14.17	31.04	25.21	101.04	74.21
2	अरुणाचल प्रदेश	8.88	7.03	7.19	6.93	2.11	2.11	-	-	2.61	2.61	4.72	4.72
3	असम	77.60	67.97	105.95	80.89	-	-	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	100.00	89.08	143.00	109.03	-	-	-	-	-	-10.00	-	-10.00
5	छत्तीसगढ़	81.00	81.00	129.00	129.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	18.00	14.00	23.50	18.50	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	4.00	3.00
7	गुजरात	240.00	157.85	369.71	274.57	33.00	33.00	20.00	20.00	20.00	10.00	73.00	63.00
8	हरियाणा	166.40	158.40	212.65	179.70	10.00	10.00	10.00	10.00	-	-7.00	20.00	13.00
9	हिमाचल प्रदेश	46.00	25.51	42.10	21.08	4.00	4.00	2.00	2.00	-	-	6.00	6.00
10	जम्मू और कश्मीर	62.00	39.74	66.84	49.27	8.00	2.61	3.00	3.00	2.49	2.49	13.49	8.10
11	झारखंड	60.00	48.07	55.09	40.23	-	-5.17	-	-	15.00	15.00	15.00	9.83
12	कर्नाटक	220.98	173.48	396.00	313.83	-	-	-	-	-	-	-	-
13	केरल	205.00	162.03	195.00	147.84	30.00	30.00	25.00	25.00	7.29	1.29	62.29	56.29
14	मध्य प्रदेश	150.00	131.25	204.96	149.71	5.00	5.00	15.00	15.00	20.00	20.00	40.00	40.00
15	महाराष्ट्र	450.00	364.80	208.69	31.17	25.00	25.00	35.00	35.00	20.00	20.00	80.00	80.00
16	मणिपुर	5.25	2.78	9.70	6.67	2.03	2.03	-	-	4.00	4.00	6.03	6.03
17	मेघालय	11.16	9.20	11.22	8.63	-	-	-	-	-	-0.50	-	-0.50
18	मिज़ोरम	4.24	2.77	0.00	-1.23	1.58	1.58	-	-	-	-	1.58	1.58
19	नगालैंड	11.35	7.66	8.22	3.55	1.00	-1.60	-	-	-	-	1.00	-1.60
20	उड़ीसा	84.38	84.38	55.00	45.00	10.00	10.00	-	-	-	-	10.00	10.00
21	पुदुचेरी	8.25	4.88	8.25	4.75	-	-	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	174.70	133.49	221.15	170.53	23.00	12.00	10.00	10.00	19.00	14.00	52.00	36.00
23	राजस्थान	249.14	167.77	331.78	201.86	40.00	40.00	15.00	10.00	59.95	31.83	114.95	81.83
24	सिक्कीम	9.95	7.45	10.88	7.95	-	-	-	-	2.13	2.13	2.13	2.13
25	तमिलनाडु	409.65	360.23	431.25	322.78	30.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	110.00	110.00
26	तेलंगाना	246.00	218.28	267.40	221.83	15.00	4.16	25.00	20.83	33.00	28.83	73.00	53.83
27	त्रिपुरा	11.37	11.37	15.43	13.87	-	-	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	416.00	371.78	460.00	333.07	-	-	-	-15.00	-	-5.00	-	-20.00
29	उत्तराखंड	66.60	58.30	63.00	52.89	5.00	2.00	-	-	-	-	5.00	2.00
30	पश्चिम बंगाल	369.11	253.04	428.28	304.31	-	-20.00	-	-40.00	20.00	20.00	20.00	-40.00
	कुल	4191.00	3402.81	4783.23	3486.43	295.72	222.56	221.00	151.00	298.51	215.89	815.23	589.45

- : शून्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
- 3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
- 4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
- 4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
- 4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
- 4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
- 7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
- 2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे- आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्विजम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

- अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
- 2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

- एनएम2 और एनएम3 में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
- 2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
- 2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय संस्थाओं में एक्विजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल1 और एल2 मासिक आधार पर और एल3 तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 15 और 16

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये गये कुल खाद्येतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामिल है।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दि. 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी.केका.प्लान. बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिजर्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूंजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक। 6-मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005 और अप्रैल 2014 अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

1.3: बहुपक्षीय निवल निपटान समूहों से संबंधित है।

3.1: मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नै - तीन केन्द्रों से संबंधित है।

3.3: 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित है।

6: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।

7: आईएमपीएस लेनदेन शामिल हैं।

9: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोले गए एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम शामिल है। अप्रैल 2014 से व्हाइट लेबल एटीएम शामिल किए गए हैं।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खजाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

2011-12 से जीडीपी डाटा 2011-12 के आधार पर हैं। वर्ष 2015-16 का डाटा 29 राज्यों से संबंधित हैं।

2015-16 से जीडीपी डाटा 28 फरवरी 2018 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम से संबंधित है।

जीडीपी के लिए 2016-17 (आरई) और 2017-18 के लिए केंद्रीय बजट 2017-18 से लिए गए हैं।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते हैं।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार हैं।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों और 364 दिन के खज़ाना बिलों के माध्यम से प्राप्त उधारियों सहित।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते हैं।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों (364-दिन के खज़ाना बिलों को छोड़कर) सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/scripts/publicationsview.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

‘वर्तमान सांख्यिकी’ का टाइम सीरिज डाटा (<https://dbie.rbi.org.in>) पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2019	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष का रियायती दर) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित [®]) ₹2,520 (एक वर्ष का रियायती दर [®])	15 अमरीकी डॉलर एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंड बुक 2018-19	₹650 (सामान्य) ₹700 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंड बुक 2017-18	₹700 (सामान्य) ₹750 (डाक प्रभार सहित) ₹525 (रियायती) ₹575 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2017-18 और 2018-19 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 38, 2017	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 39, 2018	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नंस; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (काउंटर पर)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियाः

- उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
 - टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेश:

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं हैं।
4. प्रकाशनों की (सोमवार से शुक्रवार) तक बिक्री तथा वितरण प्रभाग, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 पर उपलब्ध हैं। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdcs@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, मुख्य महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरी मंजिल, मुख्य भवन, मुंबई - 400 001 को संबोधित होना चाहिए।
एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं
बैंक का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBISOMBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-86
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रताशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdcs@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।